रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1987/श्रावण 17, 1909
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1987/SRAVANA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1987

का.आ. 1962—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री ओ.पी. भरद्वाज, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जिला व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(41)/87-न्या.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 20th July, 1987

S.O. 1962.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri O. P. Bhardwaj, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jalandhar.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(41)/87-Judl.]

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.आ. 1963.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एस.आर. खुराना, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जालंधर व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं 5(40)/87-न्याय.]

आर. एन. पोद्दार, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 1963.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri S. R. Khurana, Advocate for appointment as a Notary to pratise in Jalandhar.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(40)/87-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

का.आ. 1964.—विस्थापित व्यक्ति (दावा) अनुपूरक अधिनियम 1954 (1954 की सं. 12) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग पुनर्वास प्रभाग के अधीन (बन्दोबस्त विंग) में बन्दोबस्त अधिकारी श्री जे.बी. मुदगल को उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके द्वारा ऐसे अधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है ।

2. इसके द्वारा भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की दिनांक 8-8-1984 की अधिसूचना संख्या-1(12)/विशेष सैल/83 एस.एस. II का अतिक्रमण किया जाता है ।

[संख्या 1(5)/विशेष सैल/86/एस.एस. II]

एम.के. कंसल, बंदोबस्त आयुक्त/पदेन अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 30th June, 1987

S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (No. 12 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri J. B. Mudgal, Settlement Officer in the Settlement Wing of Rehabilitation Division, Department of Internal Security, Ministry of Home Affairs as Additional Settlement Commissioner for the purpose of performing the functions assigned to such officer by or under the said Act with immediate effect.

2. This supersedes erstwhile Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation)'s Notification No. 1(12)/Spl. Cell/83-SS II dated 8th August, 1984.

[No. 1(5)/Spl. Cell/86-SS. II]

M. K. KANSAL, Settlement Commissioner/

Ex-officio Under Secy.

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.आ. 1965.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 में स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (1) में, उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सभी उधार, चाहे वे प्रतिभूत हैं या नहीं, जो सरकारी सेवक द्वारा उधार दिए गए हैं या लिए गए हैं।"

[सं 11013/1/87-स्था.(ए)]

अ. जयरामन, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 27th July, 1987.

S.O. 1965:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to presons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Conduct) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 18 of the Central Civil Services (Conduct) rule, 1964, in Explanation 1, in clause (1), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(b) all loans, whether secured or not, advanced or taken by the Government servant."

[No. 11013/1/87-Estt(A)]

A. JAYARAMAN, Director.

Note :—The following Amendments have been made to CCS (Conduct) Rules, 1964 :—

S. No.	Notification No.	Date	Published in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-Section (ii) S.O. No.	Date
1	2		3	4
1.	25/23/68-Estt (A)	3-2-70	482	14-2-70
2.	25/11/72-Estt(A)	24-10-72	3643	4-11-72
3.	25/57/64-Estt (A)	5-1-73	83	13-1-73
4.	11013/12/75--Estt (A)	13-2-76	846	28-2-76
5.	25/19/74-Estt(A)	30-6-76	2563	17-7-76
6.	11013/19/75-Estt(A)	6-7-76	2691	24-7-76
7.	11013/6/75--Estt(A)	24-11-76	4663	11-12-76
8.	11013/14/76-Estt(A)	24-8-77	2859	17-9-77
9.	11013/3/78-Estt(A)	20-9-78	2859	30-9-78
10.	11013/12/78-Estt(A)	20-12-78	3	6-1-80

1	2	3	4	5
11.	11013/13/3/80-Estt(A)	24-4-80	1270	10-5-80
12.	11013/21/85-Estt(A)	3-10-85	4812	19-10-85
13.	11013/6/85-Estt(A)	21-2-86	935	8-3-86
14.	11013/11/85-Estt(A)	7-3-86	1124	22-3-86
15.	11013/5/86-Estt(A)	4-9-86	3159	20-9-86
16.	11013/16/85-Estt(A)	10-9-86	3280	27-9-86

का.आ. 1966—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"29. जब किसी सरकारी सेवक को फालतू घोषित कर दिया गया हो, तब अर्हक सेवा में परिवर्धन : ऐसा सरकारी सेवक, जो उस स्थापन में जिसमें वह सेवा कर रहा था, फालतू घोषित किए जाने पर, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अवस्थित केन्द्रीय (फालतू कर्मचारिवृन्द) कोष्ठ के माध्यम से या समूह "घ" कर्मचारी की दशा में, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से पुनः अभिनियोजित किए जाने की प्रसुविधा के लिए पात्र है और पुनः अभिनियोजन चाहने के बजाय स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का विकल्प करता है, उसे यह हक होगा कि वह अपने द्वारा की गई अर्हक सेवा में पांच वर्ष और जोड़

परन्तु यह तब जब :

(क) इन नियमों के नियम 13 के प्रथम परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सरकारी सेवक द्वारा की गई अर्हक सेवा उस तारीख को, जिसको वह ऐसे विकल्प का प्रयोग करता है, पन्द्रह वर्ष से कम नहीं होगी और पूर्वोक्त परिवर्धन को लेखे में लेने के पश्चात् अर्हक सेवा की अवधि उतनी सेवा से अधिक नहीं हो, जितनी सेवा उसने की होती जब वह अपनी अधिवर्षिता की तारीख को सेवा निवृत्त हो गया होता; और

(ख) सेवानिवृत्त होने के विकल्प का प्रयोग कर दिया गया है और पेंशन मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को, उस तारीख से, जिससे संबंधित कर्मचारी फालतू घोषित किया गया है, दो मास की अवधि के भीतर सूचना दे दी गई है ।

[सं. 38/57/87-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू]

ए. के. पटनायक, उप सचिव

पादटिप्पण :

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का.आ. 934 तारीख 1-4-1972 के रूप में प्रकाशित किए गए थे नियमों का तीसरा संस्करण (दिसम्बर, 1981 तक संशोधित) 1982 में मुद्रित किया गया था । नियम तत्पश्चात् पेंशन और प्रशासनिक सुधार विभाग (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	तारीख
1.	का.आ. 3477	10-9-83
2.	का.आ. 4041	1-12-84
3.	का.आ. 4218	8-12-84
4.	का.आ. 3324	20-7-85
5.	का.आ. 5192	16-11-85
6.	का.आ. 5304	30-11-85
7.	का.आ. 762	1-3-86
8.	का.आ. 1246	29-3-86
9.	का.आ. 2325	21-6-86
10.	का.आ. 1174	9-5-87

S.O. 1966.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Second Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:—

"29. Addition to qualifying service when a Government servant is declared surplus.—A Government servant who, on being declared surplus to the establishment in which he was serving, is eligible for the facility of being redeployed through the Central (Surplus Staff) Cell located in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions or in the case of a Group 'D' employee, through the Directorate General, Employment and Training and opts to retire voluntarily, instead of seeking redeployment, shall be entitled to have five years added to the qualifying service rendered by him :

Provided that—

(a) not-withstanding anything contained in the first proviso to rule 13, the qualifying service rendered by such Government servant shall be not less than fifteen years on the date on which he exercises such option and the qualifying length of service after taking into account the aforesaid addition is not more than the service he could have rendered had he retired on the date of his superannuation; and

(b) the option to retire is exercised and is communicated to the authority competent to sanction pension within a period of two months from the date from which the employee concerned has been declared surplus."

[No. 38/57/87-P&PW]

A. K. PATNAIK, Dy. Secy.

Foot Note:—The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1-4-1972. The Third Edition (corrected upto December 1981) of the rules was printed in 1982. The rules

were subsequently amended vide DP&AR (DP&PW) Notifications given below:—

S. No.	Notification No.	Date
1.	S.O. 3477	10-9-1983
2.	S.O. 4041	1-12-1984
3.	S.O. 4218	8-12-1984
4.	S.O. 3324	20-7-1985
5.	S.O. 5192	16-11-1985
6.	S.O. 5304	30-11-1985
7.	S.O. 762	1-3-1986
8.	S.O. 1246	29-3-1986
9.	S.O. 2325	21-6-1986
10.	S.O. 1174	9-5-1987

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.आ. 1967.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुरी कोयला खान साइडिंग, बिहार से कोयले की चोरी के बारे में खाना खेलरी, जिला रांची (बिहार) में रजिस्ट्रीकृत मामला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 46/84 तारीख 11-6-84 की बाबत भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराधों और उक्त अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के अन्वेषण के लिए, बिहार सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण बिहार राज्य पर करती है ।

[संख्या 228/2/86-ए.वी.डी.II]

के.एन.के. कार्थियायनी, निदेशक

ORDER

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 1967.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delh Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), th Central Government with the consent of Government o Bihar hereby extends the powers and jurisdiction of the mem bers of the Delhi Special Police Establishment to the whol of the State of Bihar for the investigation of offences punish able under section 379 of the Indian Penal Code (45 o 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation t or in connection with the said offences and any other offen ces committed in the course of the same transaction in regar to case FIR No. 46/84 dated the 11th June, 1984 registered at Police Station Khelari, District Ranchi (Bihar) in regard to the theft of coal from Churi Colliery Siding, Bihar.

[No 228/2/86-AVD. II]

K. N. K. KARTHIAYANI, Director (Vigilance)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 1987

(आयकर)

का. आ. 1968—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "दोहनावर फैलोशिप, तमिलनाडु", को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1987-88 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7298/का.सं. 197/167/85-आ.क.(नि.-1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th May, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 1968.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dohnavur Fellowship, Tamil Nadu" for the purpose of the said clause for the assessment years 1986-87 and 1987-88.

[No. 7298/F. No. 197/167/85-IT(A1)]

का.आ. 1969:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "श्री हरीहर पुत्र भजन समाज (रजिस्टर्ड), बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1987-88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 7299/फा.सं. 197/105/86

S.O. 1969.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Hariharaputra Bhajan Samaj (Reg.), Bombay" for the purpose of the said clause for the assessment years 1986-87 and 1987-88.

[No. 7299/F. No. 197/105/86-IT(AI)]

का० आ० 1970 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ "श्री कैलाश आश्रम महासंस्थान, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7294/फा०सं० 197/84/86-आ०का० (नि०-1)]

दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

S.O. 1970.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Kailash Ashram Mahasamsthana, Bangalore" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7294/F. No. 197/84/86-IT(AI)]

DALIP SINGH, Officer on Special Duty

(आयकर)

का० आ० 1971 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "बाला मन्दिर कामराज ट्रस्ट, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 के लिए अधिसूचित करती है ।

[सं. 7292/फा. सं. 197/204/86—आ..क. (नि.-1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1971.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bala Mandir Kamraj Trust, Madras" for the purpose of the said clause for the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[N. 7292/F. No. 197/204/86-IT(AI)]

का० आ० 1972 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "स्टूडेन्ट क्रिस्चियन मूवमेंट ऑफ इण्डिया, बंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1985—86 से 1987—88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7291/फा०सं० 197क/223/82-आ०क० (नि०—1)]

S.O. 1972.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Student Christian Movement of India, Bangalore" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7291/F. No. 197A/223/82-IT(AI)]

का० आ० 1973 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "(i) श्री शारदा मठ, कलकत्ता और (ii) रामाकृष्ण शारदा मिशन, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1987—88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7293/फा०सं० 197/41/85-आ०क० (नि०—1)]

S.O. 1973.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "(i) Sri Sarda Math, Calcutta and (ii) Ramakrishna Sarda Mission, Calcutta" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-88.

[No. 7293/F. No. 197/41/85-IT(AI)]

का० आ० 1974 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "गुरु गोबिन्द सिंह फाउण्डेशन, चण्डीगढ़" को कर निर्धारण वर्ष 1985—86 से 1987—88 के लिए अधिसूचित क

[सं० 7296/फा०सं० 197/109/85-आ०क०/नि०—1)]

S.O. 1974.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Guru Gobind Singh Foundation, Chandigarh" for the purpose of the said clause for the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 7296/F. No. 197/109/85-IT(AI)]

का० आ० 1975 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मालंकार मर्थामा सीरियन चर्च ऑफ मालाबार" को कर निर्धारण वर्ष 1987—88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7295/फा०सं० 197/140/86-आ०क० (नि० 1)]

S.O. 1975.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Malankara Marthoma Syrin Church of Malabar" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-88.

[No. 7295/F. No. 197/140/86-IT(AI)]

का० आ० 1976 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23—ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि बम्बई सोसायटी आफ दि फ्रान्सिस्कन सिस्टर्स ऑफ मेरी" को कर निर्धारण वर्ष 1987—88 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7290 (फा०सं० 197/196/86-आ०क० (नि०—I)]

S.O. 1976.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Bombay Society of the Franciscan Sisters of Mary" for the purpose of the said clause for the assessment year 1987-88.

[No. 7290/F. No. 197/196/86-IT(AI)]

का० आ० 1977.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "अरुलमिगु श्री श्रीनिवास पेरुमल तिरुकोइल", नचियारकोइल, जिला तंजोर को ऐतिहासिक महत्व के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 7302/फा०सं० 176/84/86-आ०का० (नि०—1)]

S.O. 1977.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80-G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Arlmigu Sri Srinivasa Perumal Tirukoil", Nachiarkoil Tanjore District to be historic importance for the purpose of the said section.

[No. 7302/F. No. 176/84/86-IT(AI)]

(आयकर)

का० आ० 1978:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपधारा के प्रयोजनार्थ, "श्री महागणपति टेम्पल, चथापुरम, पालघाट को सम्मस्त केरल राज्य के प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० 7303 फा०स० 176/3/87-आ०क० नि०-1]

S.O. 1978.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Mahaganapathy Temple", Chathapuram, Palghat to be a place of public worship of renown throughout the State of Kerala for the purpose of the said sub-section

[No. 7303|F No. 176|3|87-IT(A1)]

(केन्द्रीय प्रयत्क्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 मई, 1987

(आयकर)

का. आ. 1979:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनाक 20-7-1974 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. 679 [फा. सं. 187/2/74 आ. क. (नि-1)] में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. क्रम सं. 14 तथा 14-क के सामने स्तम्भ सं०. 1, 2 तथा 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:—

आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
14. लखनऊ	लखनऊ	1. सम्पदा शुल्क एवं आयकर परिमण्डल लखनऊ 1 2. लखनऊ परिमण्डल, लखनऊ 3. वेतन परिमण्डल, लखनऊ 4. अल्मोड़ा 5. बाराबंकी 6 बरेली 7. बिजनौर 8. बदायू 9. चन्दौसी 10. हरदोई 11. हल्द्वानी 12. काशीपुर 13. लखीमपुर-खेड़ी 14 परिमण्डल-1, मुरादाबाद 15. परिमण्डल—II, मुरादाबाद 16. नैनीताल 17. नजीबाबाद 18. पीलीभीत 19. पिथौरागढ़ 20. रामपुर 21. रायबरेली 22. सम्भल 23. शाहजहांपुर 24. सीतापुर 25. उन्नाव 26. बहराईच

1	2	3
14-क इलाहाबाद	इलाहाबाद	1. इलाहाबाद 2. सम्पदा शुल्क एवं आयकर परिमण्डल, इलाहाबाद 3. सुल्तानपुर 4. फैजाबाद 5. फतेहपुर 6. गोरखपुर 7. बस्ती 8. गोंडा 9. आजमगढ़ 10. बलिया 11. देवरिया 12. वाराणसी 13. मिर्जापुर 14. जौन पुर 15. गाजीपुर 16. प्रतापगढ़ 17. माउनाथ भंजन 18. बधौली।

यह अधिसूचना दिनांक 1-6-1987 से लागू होगी।

[संख्या 7305/फा. सं. 189/4/87 आ. क. (नि.-1)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 19th May, 1987

INCOME TAX

S. O. 1979.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 679 [F. No. 187/2/74-IT(A1)] dated 20-7-1974 as amended from time to time.

2. The existing entries under column No. 1, 2 and 3 against Serial No. 14 and 14A shall be substituted by the following entries :—

Commissioner of Income Tax	Head Quarters	Jurisdiction
1	2	3
14. Lucknow	Lucknow	1. Estate Duty-Cum-Income-tax Circle, Lucknow. 2. Lucknow Circle, Lucknow. 3. Salary Circle, Lucknow. 4. Almora 5. Barabanki 6. Bareilly 7. Bijnor 8. Badaun 9. Chandausi 10. Hardoi 11. Haldwani 12. Kashipur 13. Lakhimpur-kheri 14. Circle-I, Moradabad 15. Circle-II, Moradabad

1	2	3
		16. Nainital 17. Najibabad 18. Pilibhit 19. Pithoragarh 20. Rampur 21. Raebareli 22. Sambhal 23. Shahjahanpur 24. Sitapur 25. Unnao 26. Bahraich
14A. Allahabad	Allahabad	1. Allahabad 2. ED-cum-IT. Circle, Allahabad. 3. Sultanpur 4. Faizabad 5. Fatehpur 6. Gorakhpur 7. Basti 8. Gonda 9. Azamgarh 10. Ballia 11. Deoria 12. Varanasi 13. Mirzapur 14. Jaunpur 15. Ghazipur 16. Paratapgarh 17. Mau Nath Bhanjan 18. Badhcli

This notification shall take effect from 1-6-1987.

[No. 7305/F. No. 189/4/87-IT(A1)]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1987

का. आ. 1980—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 25 मई, 1978 की अधिसूचना सं. 2309 [फा. सं. 187/11/78—आ. क. (नि-1)] में दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

क्रम सं. 11-ग के सामने स्तम्भ (1), (2) तथा (3) के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी:—

आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
11-ग	कानपुर सेंट्रल	कानपुर	1. केन्द्रीय परिमण्डल—I से VI कानपुर। 2. केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद 3. केन्द्रीय परिमण्डल, गोरखपुर 4. केन्द्रीय परिमण्डल-I, और II वाराणसी 5. केन्द्रीय परिमण्डल-I, II और III लखनऊ। 6. केन्द्रीय परिमण्डल, बरेली 7. निरीक्षी सहायक आयुक्त (कर-नि.) (केन्द्रीय) वाराणसी

यह अधिसूचना दिनांक 15-1-1987 से लागू होगी।

[सं. 7206/फा. सं. 187/3/87 आ. क. (नि-1)]

रोशन सहाय, अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 27th March, 1987

S.O. 1980.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the Schedule appended to its Notification No. 2309 (F. No. 187/11/78-IT(A1) dated 25th May, 1978.

Existing entries under Columns (1), (2) & (3) against serial No. 11C shall be substituted by the following entries :—

Commissioner of Income-tax	Head Quarters	Jurisdiction
1	2	3
11C. Kanpur Central	Kanpur	1. Central Circles I to VI, Kanpur. 2. Central Circle Allahabad. 3. Central Circle Gorakhpur. 4. Central Circles I & II, Varanasi. 5. Central Circles I, II & III Lucknow. 6. Central Circle Bareilly. 7. I.A.C. (Asstt) (Central), Varanasi.

The notification shall take effect from 15-1-1987.

[No. 7206 /F. No. 187/3/87-IT(A1)]
ROSHAN SAHAY, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 25 मई, 1987

(आयकर)

का. आ. 1981.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड 44 के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे स्तम्भ 4 में उल्लिखित अधिसूचना (अधिसूचनाओं) का अधिलंघन करते हुए, नीचे स्तम्भ 3 में उल्लिखित कर वसूली अधिकारियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित, अधिकारी है उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

क्र. सं.	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हे कर वसूली अधिकारी (अधिकारियों) की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाना है	उन कर वसूली अधिकारी (अधिकारियों) के नाम जिनके स्थान पर स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाना है।	पुरानी अधिसूचनाओं की संख्या और तारीख जिनका अधिलंघन किया जाना है
	2	3	4
1.	सर्वश्री ए. डी. सरवाह	सर्वश्री एन. सी. सोरभजन	6050 दिनांक 23-11-84 [फा. सं. 398/39/84-आ. क. (ब)]
2.	सर्वश्री पी. सी. गुप्ता	सर्वश्री एस. पी. शर्मा	—तदैव—
3.	सर्वश्री आर. ए. बंसल	सर्वश्री के. एल. भाटिया-II,	6168 दिनांक 8-3-85 [फा. सं. 398/4/85-आ. क. (ब)]
4	सर्वश्री आर. एन. अग्रवाल	सर्वश्री एम. के. किरपाल	—तदैव—
5.	सर्वश्री एस. एल. कुमार	सर्वश्री ए. के. मोंगा	6206 दिनांक 25-4-85 [फा. सं. 398/4/85-आ. क. (ब)]
6.	सर्वश्री बी. एन. ग्यान चंदानी,	सर्वश्री पी. के. विश्वास	6226 दिनांक 18-5-85 [फा. सं. 398/4/85-आ. क.) (ब.]

2. यह अधिसूचना तत्काल लागू होगी और जहां तक स्तम्भ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों का सम्बन्ध है कर वसूली अधिकारियों के रूप में उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख (तारीखों) से लागू होगी।

[सं. 7312 /फा. सं. 398/17/87-आई टी (बी)]

New Delhi, the 25th May, 1987

(INCOME-TAX)

S.O. 1981 : In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby authorises the persons mentioned below in column 2, being the Gazetted officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer (s) under the said Act in place of the Tax Recovery Officers mentioned below in column 3 in supersession of the Notification (s) mentioned below in column 4 :

Sl. No.	Name of the persons to be authorised to exercise powers of Tax-Recovery Officer(s)	Name of Tax Recovery Officer(s) in place of whom the persons mentioned in column 2 are to be authorised	Old Notification No. and date to be superseded
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	S/Shri A.D. Marwah	S/Shri N.C. Sarbhajana	6050 dt. 23-11-84 [F. No. 398/39/84-IT(B)]
2.	,, P.C Gupta	,, S.P. Sharma	-do-
3.	,, R.A. Bansal	,, K.L. Bhatia-II	6168 dt. 8-3-85 [F. No 398/4/85/-IT(B)]
4.	,, R.N. Aggarwal	,, S.K. Kirpal	-do-
5.	,, S.L. Kumar	,, A.K. Monga	6206 dt. 25-4-85 [F. No. 398/4/85-IT(B)]
6.	,, V.N Khanchandani	,, P.K. Biswas	6226 dt. 18-5-85 [F. No. 398/4/85-T(B)]

2. This Notification shall come into force with immediate effect and in so far as persons mentioned in column 2 from the date(s) they take over charge(s) as Tax Recovery Officers.

[No. 7312 F. No. 398/17/87-IT(B)]

नई दिल्ली, 5 जून, 1987

(आयकर)

का. आ. 1982.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण कर वसूली अधिकारी के रूप में श्री के. आर. उपाध्याय की नियुक्ति के संबंध में जारी की गई वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21-5-84 की अधिसूचना सं. 5812 [फा. सं. 398/14/84 आ. क. (ब.)] को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना श्री के. आर. उपाध्याय द्वारा कर वसूली अधिकारी का कार्यभार सौंपने की तारीख से लागू होगी ।

[सं. 7335/फा. सं. 398/15/87/आ. क. (ब.)]

बी. ई. अलैक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th June, 1987

(INCOME-TAX)

S.O 1982.—The notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5812 [F. No. 398/14/84-IT(B)] dated 21-5-84 in pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) appointing Shri K. R. Upadhyay as Tax Recovery Officer is hereby cancelled.

2 This notification shall come into force with effect from the date Shri K. R Upadhyay hands over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 7335/F. No. 398/15/87-IT(B)]

B F ALEXANDER, Under Secy

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

का. आ. 1983—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) स्तम्भ (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों परिमण्डलों और जिलों में आयकर अथवा अतिकर या ब्याज कर में निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में अपना कार्य निर्वहण करेंगे, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए है और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी कार्य निर्वहण करेंगे, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दे।

अनुसूची

क्रम सं.	अधिकार क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	परिमण्डल का नाम
1	2	3
1	आयकर आयुक्त (अपील)-1 हैदराबाद।	1. खेतन परिमण्डल, हैदराबाद। 2 परिमण्डल—1, हैदराबाद। 3. विशेष जांच परिमण्डल—1, हैदराबाद। 4. फिल्म परिमण्डल, हैदराबाद। 5. सर्वेक्षण परिमण्डल, हैदराबाद करनूल वारंगल गण्टूर तथा तिरूपति। 6. तिरूपति परिमण्डल तिरूपति, 7. चित्तूर परिमण्डल 8. अनंतपुर परिमण्डल 9 अडोनी परिमण्डल 10. करनूल परिमण्डल 11. नि. स. आ. (क नि) रेंज—1, हैदराबाद।
2.	आयकर आयुक्त (अपील)—II हैदराबाद।	1 कम्पनी परिमण्डल हैदराबाद। 2. रामरेड्डी परिमण्डल 3. निजामाबाद परिमण्डल 4. निरमल परिमण्डल 5. नि. स आ. (क नि) रेंज II हैदराबाद।
3.	आयकर आयुक्त (अपील) III) हैदराबाद।	1. वारंगल परिमण्डल 2. खम्मम परिमण्डल 3 हिन्दुपुर परिमण्डल 4 कड्डापाह परिमण्डल 5. ताण्डयाल परिमण्डल 6 प्रोद्दातुर परिमण्डल 7 गण्टूर परिमण्डल 8. विशेष जांच परिमण्डल, गण्टूर 9. परिमण्डल—III. हैदराबाद 10 केन्द्रीय परिमण्डल, हैदराबाद 11 केन्द्रीय परिमण्डल, कोकीनाडा

1	2	3
		12. केन्द्रीय परिमण्डल, विजयवाडा
		13. नालगोंडा परिमण्डल
		14. महबूबनगर परिमण्डल
		15. करीम नगर परिमण्डल
		16. नि. स. आ. (क. नि.) रेंज—III हैदराबाद
		17. परिमण्डल—II, हैदराबाद
		18. परिमण्डल—IV हैदराबाद।
	4. आयकर आयुक्त (अपील), विशाखापत्तनम	1. श्री काकुलम परिमण्डल
		2. विजय नगरम् परिमण्डल
		3. विशाखापत्तनम परिमण्डल
		4. विशेष जांच परिमण्डल, विशाखापत्तनम
		5. वेतन परिमण्डल, विशाखापत्तनम
		6. अनाकापल्ली परिमण्डल
		7. परिमण्डल-I, काकीनाडा
		8. परिमण्डल-II, काकीनाडा
		9. राजा सुन्दरी परिमण्डल
		10. अमालापुरम परिमण्डल
		11. गलाकोल परिमण्डल
		12. तनकु परिमण्डल
		13. भीमावरम् परिमण्डल
		14. एलरू परिमण्डल
		15. परिमण्डल-I, विजयवाड़ा
		16. परिमण्डल-II, विजयवाड़ा
		17. विशेष जांच परिमण्डल, विजयवाड़ा
		18. मछलीपत्तनम परिमण्डल
		19. गुडीवाडा परिमण्डल
		20. बापाटला परिमण्डल
		21. तेनाली परिमण्डल
		22. अंगोले परिमण्डल
		23. नेल्लोर परिमण्डल
		24. गण्टूर परिमण्डल
		25. विशेष जांच परिमण्डल, गण्टूर

जहां कहीं कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार-क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व अधिकार-क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से अधिकार-क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटाई जायेंगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया है।

यह अधिसूचना दिनांक 15-4-1987 से लागू होगी।

[सं० 7246/फा०सं० 261/8/87-आ०क०न्या०]

New Delhi, 15th April, 1987

S.O. 1983.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest tax in the Income-tax Wards, Circles and Districts specified in the corresponding entries in the column No. (2) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in classes (a) to (h) of Sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section 11 of the Companies (Profits) Sur tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of 15 of Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or clauses of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

S. No.	Charges with Headquarters	Name of the Circle
1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-I, Hyderabad.	1. Salary Circle, Hyderabad. 2. Circle-I, Hyderabad. 3. Spl. Inv. Circle-I, Hyderabad. 4. Film Circle, Hyderabad. 5. Survey Circles, Hyderabad. Kurnool, Warangal, Guntur & Tirupathi. 6. Tirupathi Circle, Tirupathi. 7. Chittoor Circle. 8. Ananthapur Circle.. 9. Adoni Circle. 10. Kurnool Circle. 11. IAC (Assts) Range-I, Hyderabad.
2.	Commissioner of Income-tax (Appeals)-II, Hyderabad.	1. Company Circle, Hyderabad. 2. Sangareddy Circle. 3. Nizamabad Circle. 4. Nirmal Circle. 5. IAC (Assts) Range-II, Hyderabad.
3.	Commissioner of Income-tax, (Appeals)-III, Hyderabad.	1. Warangal Circle. 2. Khammam Circle. 3. Hindupur Circle. 4. Cuddapah Circle. 5. Nandyal Circle. 6. Proddatur Circle 7. Guntur Circle. 8. Spl. Inv. Circle, Guntur. 9. Circle-III, Hydeabad. 10. Central Circle, Hyderabad. 11. Central Circle, Kakinada. 12. Central Circle, Vijayawada. 13. Nalgonda Circle. 14. Mahaboobnagar Circle. 15. Karimnagar Circle. 16. IAC (Assts) Range-III, Hyderabad. 17. Circle-II Hyderabad. 18. Circle-IV, Hyderabad.

1	2	3
4. Commissioner of Income-tax, (Appeals), Visakhapdtnam.		1. Srikakulam Circle. 2. Vizianagaram Circle. 3. Visakhapatnam Circle. 4. Spl. Imv. Circle, Visakhapatnam. 5. Salary Circle, Visakhapatnam. 6. Anakapalle Circle. 7. Circle-I, Kakinada. 8. Circle-II, Kakinada. 9. Rajahmundry Circle. 10. Amalapuram Circle. 11. Ralacole Circle. 12. Tanuku Circle. 13. Bhimavaram Circle. 14. Eluru Circle. 15. Circle-I, Vijayawada. 16. Circle-II, Vijayawada. 17. Spl. Inv. Circle, Vijayawada. 18. Machilipatnam Circle. 19. Gudivada Circle. 20. Bapatla Circle. 21. Tenali Circle. 22. Ongole Circle. 23. Nellore Circle 24. Guntur Circle. 25. Spl. Inv. Circle, Guntur.

Whereas the Income-tax Circle, Ward or district or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge. appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner or Income-tax (Appeals) of the charge from when that Income-tax Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 15-4-87.

[No. 7246/F. No. 261/8/87-IT/IT)]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1987

का. आ. 1984.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 6-2-1986 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 6585 (फा. सं. 261/2/86—आ. क. न्या.) में संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील) स्तम्भ (2) और स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर अथवा अतिकर या ब्याजकर में निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में अपना कार्य निर्वहण करेंगे, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी कार्य निर्वहण करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दे।

अनुसूची

क्र. सं.	अधिकार-क्षेत्र	आयकर वार्ड/परिमण्डल और जिले	आयकर के निम्न आयुक्तों के रेंज
1		2	3
1.	आयुकर आयुक्त (अपील), पुणे	आयकर आयुक्त, पुणे के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड और परिमण्डल।	पुणे रेंज—I, पुणे रेंज—II, पुणे रेंज—III, पुणे I कर—निर्धारण रेंज—I, पुणे। ठाणे। रेंज—I ठाणे। ठाणे रेंज—II ठाणे। कर-निर्धारण रेंज—II, पुणे।
2.	आयकर आयुक्त (अपील), नासिक।	आयकर आयुक्त, नासिक के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड और परिमण्डल।	नासिक रेंज, नासिक कर-निर्धारण रेंज, सिक औरंगाबाद रेंज, औरंगाबाद।
3.	आयकर आयुक्त (अपील) कोल्हापुर।	आयकर आयुक्त, कोल्हापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड और परिमण्डल	शोलापुर रेंज, शोलापुर कोल्हापुर रेंज, कोल्हापुर।

इस अधिसूचना के आधार पर, आयकर आयुक्त (अपील) नासिक का आयकर आयुक्त (अपील), कोल्हापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी अपील पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा और आयकर आयुक्त (अपील), पुणे, का आयकर आयुक्त (अपील) नासिक के क्षेत्राधिकार में आने वाली किसी भी अपील पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा।

जहां कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार-क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, अधिकार—क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार—क्षेत्र में आयकर परिमण्डल वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से अधिकार-क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त को अंतरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1987 से लागू होगी।

[सं० 7249/फा०सं 261/14/87-आ०का०न्या०]

New Delhi, 20th April, 1987

S.O. 1984.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)and in modification of the previous notification No. 6585 (F. No. 251/2/86-JTJ)dt. 6-2-86, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the Charges specified in Column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons, assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column (2) Column (3)thereof as are aggreived by any of the orders mentioned in Clauses (a) to (h) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

S. No.	Charges with	Income Tax Wards/ Circles and Districts	Range of IACs of Income-tax
1	2	3	4
1.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Pune.	All Wards & Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Pune.	Pune Range-I, Pune. Pune Range-II, Pune. Pune Range-III, Pune. Asstt. Range-I, Pune. Thane Range-I, Thane. Thane Range-II, Thane. Asstt. Range-II, Pune.
2.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Nasik.	All Wards and Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Nasik.	Nasik Range, Nasik. Asstt. Range, Nasik. Aurangabad Range, Aurangabad
3.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Kolhapur.	All Wards & Circles within the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Kolhapur.	Solapur Range, Solapur. Kolhapur Range, Kolhapur.

By virtue of this notification, the Commissioner of Income-tax (Appeals), Nasik shall cease to have any jurisdiction over any of the appeals falling in the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax (Appeals), Kolhapur and the Commissioner of Income-tax (Appeals), Pune shall cease to have any jurisdiction over any of the appeals falling in the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax, (Appeals), Nasik.

Whereas Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof stands transferred by this notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Commissioner of Income-tax of the charge from whom the Income-tax Circle, Ward, or District or Part thereof is transferred shall from the date of this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax of the charge to whom the said Circle, Ward or District or Part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-4-1987.

[No. 7249/F. No. 261/14/87-ITJ]

नई दिल्ली, 6 मई, 1987

का. आ. 1985—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उस संबंध में पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) विनिर्दिष्ट अधिकार-क्षेत्र के आयकर आयुक्त (अपील), स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर वार्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर अथवा अतिकर अथवा ब्याजकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में अपना कार्य निर्वहण करेगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (ज), कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर अधिनियम 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी कार्य निर्वहण करेंगे, जिनके लिये बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दे :

अनुसूची

आयकर आयुक्त (अपील) के अधिकार-क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	आयकर वार्ड/परिमण्डल/जिले	नि. स. आयुक्त (कर-निर्धारण) के रेंज
1	2	3
1. आयकर आयुक्त (अपील)-1, बम्बई	1. कंपनी परिमण्डल-1	1. नि. स. आ., कर-निर्धा. रेंज-1ए 2. नि. स. आ., कर-निर्धा. रेंज-1बी 3. ,, ,, ,, ,, रेंज-1सी
2. आयकर आयुक्त (अपील)-2, बम्बई	1. फिल्म परि. 2. कंपनी परि.-3 (सौंपे गये) 3. बी.एस.डी. (एस.) (सौंपे गये)	
3. आयकर आयुक्त (अपील)-3, बम्बई	1. आयकर अधिकारी, कंपनी परिमण्डल-6 (7) से (11) 2. कर-निर्धा. परि.-2 3. कर-निर्धा. परि.-2ए 4. ए-4 वार्ड 5. डी-2 वार्ड	
4. आयकर आयुक्त (अपील) 4, बम्बई	1. कंपनी परि.-2 2. विदेशी अनुभाग 3. विदेशी कंपनी रेंज 4. विदेशी कंपनी परि.-2	1. नि. स. आ., कर-निर्धा. रेंज-2ए 2. नि. स. आ., कर-निर्धा. रेंज-2बी 3. नि. स. आ., कर-निर्धा. रेंज-2सी

1	2	3
आयकर आयुक्त (अपील)-5, बम्बई	1. आयकर अधिकारी, कंपनी परि.-4 (1) से (5)	1. नि.स.आ., कर-निर्धा. रेंज-4ए 2. ,, ,, ,, रेंज-4बी 3. ,, ,, ,, ,, रेंज-4सी
6. आयकर आयुक्त (अपील)-6, बम्बई	1. आ.क.अधि. कपनी परि. 5(1) से (6) 2. कर-निर्धा. परि-5 3. विदेशी कंपनी परिमण्डल-1 4. विदेशी कंपनी रेंज-1	1. नि.स.आ., कर-निर्धा. रेंज-5ए 2. ,, ,, ,, रेंज-5बी 3. ,, ,, ,, रेंज-5सी
7. आयकर आयुक्त (अपील)-8, बम्बई	1. आयकर अधिकारी कंपनी परिमण्डल-3 (1) से (8)	
8. आयकर आयुक्त (अपील)-8, बम्बई	1. आयकर अधिकारी कंपनी परिमण्डल-6 (1) से (6)	
9. आयकर आयुक्त (अपील)-9, बम्बई	1. डी. 1 वार्ड 2. कर-निर्धारण परि.-7	1. नि.स.आ. कर-निर्धा. रेंज-8
10. आयकर आयुक्त (अपील)-10, बम्बई	1. सी-1 वार्ड 2. सी-2 वार्ड 3. सी-3 वार्ड 4. सी-5 वार्ड 5. पूना (सौंपे गये)	1. नि.स.आ., कर-निर्धा. रेंज-8ए
11. आयकर आयुक्त (अपील)-11, बम्बई	1. सर्वेक्षण परि.-1 2. सर्वेक्षण परि.-2 3. ई-वार्ड 4. जी-वार्ड 5. जी.ए.-वार्ड 6. कर-निर्धारण परि.-9	1. नि.स.आ. कर-निर्धा. रेंज-9 2. ,, ,, ,, रेंज-9ए 3. ,, ,, ,, रेंज-11 4. ,, ,, ,, रेंज-11ए 5. ,, ,, ,, रेंज-12 6. ,, ,, ,, रेंज-12ए
12. आयकर आयुक्त (अपील)-12, बम्बई	1. बी-1 वार्ड 2. बी-3 वार्ड 3. सी-4 वार्ड	
13. आयकर आयुक्त (अपील)-13, बम्बई	1. न्यास परिमण्डल 2. मार्कीट वार्ड 3. 10-वार्ड 4. एस.आर.आर.सी. 5. ए.वी. वार्ड 6. एस.बी.-1 7. एस.बी.-2	
14. आयकर आयुक्त (अपील)-14, बम्बई	1. कंपनी परिमण्यल-4 2. कंपनी परिमण्यल-5 3. बी.एस.डी. (एस.)	
15. आयकर आयुक्त (अपील)-15, बम्बई	1. बी. एस.डी. (ई) 2. बी.एस.डी. (डब्ल्यू.) 3. बी.एस. डी. (यू.) 4. बी-2 वार्ड 5. टी.डी. एस.	

1	2	3
16. आयकर आयुक्त (अपील)-16, बम्बई	1. आयकर अधिकारी, कम्पनी परि.-3 (9) से (15) 2. केन्द्रीय परि.-24 3. आयकर अधिकारी, कर-निर्धा. परि. (अब समाप्त किए गये)	1. नि.स.आ., कर-निर्धा. रेंज-10ए 2. नि.स.आ., कर-निर्धा.-रेंज-12 (ए) से (एफ)
17. आयकर आयुक्त (अपील)-17, बम्बई	1. ए-1 वार्ड 2. ए-2 वार्ड 3. ए-3 वार्ड 4. व्यवसायिक परि	1. नि.स.आ., कर-निर्धा. रेंज-6 (ए) से (ई)
18. आयकर आयुक्त (अपील)-18, बम्बई	1. सम्पदा शुल्क	

जहां कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड, जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार-क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार-क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड, जिला अथवा उसके किसी भाग में किये गये निर्धारणो से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, अधिकार-क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष पड़ी अपीलें जिनके अधिकार-क्षेत्र में आयकर वार्ड, परिमण्डल और जिला अथवा [illegible] अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से अधिकार-क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटाई जायेंगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना 1-5-1987 से लागू होगी।

[सं. [illegible]/फा.सं. 261/13/87-आ.क.न्या.]

New Delhi, 6th May, 1987

S.O. 1985.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Incme-tax Act, 1961 (43 of 1961) and, in supersession of all previous Notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax, (Appeals) of the Charges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or Sur-tax or Interest-tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in columns (2) & (3) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (1) of Section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964), and sub-section (1) of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

CIT(A) Charges with Headquarters	Income-tax Wards/Circles/Districts	Range of IAC, (Asstt.)
1	2	3
1. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-I, Bombay.	1. Companies Cir. I	1. IAC, Asstt. Range-I A 2. IAC, Asstt. Range-I B 3. IAC, Asstt. Range-I C
2. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-II, Bombay.	1. Film Circle 2. Companies Cir. III (assigned) 3. B.S.D. (S) (assigned)	
3. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-III, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. VI (7) to (11) 2. Asstt. Cir. II. 3. Asstt. Cir. II A 4. A-IV Ward. 5. D-II Ward.	
4. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-IV, Bombay.	1. Companies Cir. II 2. Foreign Section. 3. Foreign Co. Range. 4. Foreign Com. Cir. II	1. IAC, Asstt. Range-II A 2. IAC, Asstt. Range-II B 3. IAC, Asstt. Range-II C

(1)	(2)	(3)
5. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-V, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. IV (1) to (5)	1. IAC, Asstt. Range-IV A 2. IAC, Asstt. Range-IV B 3. IAC, Asstt. Range-IV C
6. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VI, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. V (1) to (6) 2. Asstt. Circle-V 3. Foreign Com. Cir. I. 4. Foreign Com. Range-I.	1. IAC, Asstt. Range-V A 2. IAC, Asstt. Range-V B 3. IAC, Asstt. Range-V C
7. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VIII, Bombay.	1. ITO, Company Cir. III (1) to (8)	
8. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-VIII, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. VI (1) to (6).	
9. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-IX, Bombay.	1. D-I Ward 2. Asstt. Cir. VII	1. IAC, Asstt. Range-VII
10. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-X, Bombay.	1. C-I, Ward 2. C-II Ward 3. C-III Ward 4. C-V Ward 5. Poona (assigned)	1. IAC, Asstt. Range-VIII A
11. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XI, Bombay.	1. Survey Cir. I 2. Survey Cir. II 3. E-Ward 4. G Ward 5. GA-Ward 6. Asst. Cir. IX.	1. IAC, Asst. Range-IX 2. IAC, Asstt. Range-XI A 3. IAC, Asst. Range-XI 4. IAC, Asstt. Range-XI A 5. IAC, Asstt. Range-XII 6. IAC, Asstt. Range-XII A
12. Commissioner of Income-tax, (Appeals)XII, Bombay.	1. B-I Ward 2. B-III Ward 3. C-IV Ward	
13. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XIII, Bombay.	1. Trust Circle. 2. Market Ward 3. X-Ward 4. N.R.R.C. 5. A-V Ward 6. S.B. I 7. S.B. II	
14. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XIV, Bombay.	1. Com. Cir. IV 2. Com. Cir. V 3. B.S.D. (S)	
15. Commissioner of Income-tax (Appeals)-XV, Bombay.	1. B.S.D. (E) 2. B.S.D. (W) 3. B.S.D. (N) 4. B-II Ward 5. T.D.S.	
16. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVI, Bombay.	1. ITO, Com. Cir. III (9) to (15) 2. Central Cir. XXIV 3. ITOs, Asst. Circle (Now dissolved)	1. IAC, Asstt. Range-X A 2. IAC, Asstt. Range-III (A) to (F).
17. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVII, Bombay.	1. A-I Ward 2. A-II Ward 3. A-III Ward 4. Prof. Circle.	1. IAC, Asstt. Range-VI (A) to (E).
18. Commissioner of Income-tax, (Appeals)-XVIII, Bombay.	1. Estate Duty.	

Whereas an Income-tax Circle, Ward, District or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or

part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income tax (Appeals) of the charge from whom the Income-tax Ward, Circle and District or Range or part thereof is transferred, shall from the date this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Commissioner, of-Income-tax (Appeals) of the charge to which the said Circle, Ward or District or Range or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-5-1987.

[No. 7270/F. No. 261/13/87-ITJ]

का. आ. 1986—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त और इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंज के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त आयकर के लिए निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर जिन पर क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (अपील) में निहित है, अनुसूची स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों, और/अथवा जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे ।

अनुसूची

क्र. सं.	प्रधान कार्यालयों सहित रेंज	आयकर परिमण्डल, वार्ड और जिले
1	2	3
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, ए-रेंज बम्बई ।	1. I-वार्ड 2. एन. आर. आर. सी. 3. व्यावसायिक परिमण्डल 4. डी. आर. सी. 5. ए-III वार्ड 6. कर-निर्धारित परिमण्डल-Iए 7. विदेशी कंपनी परिमण्डल-I 8. कंपनी परिमण्डल-I 9. कंपनी परिमण्डल-II 10. कर-निर्धारित परिमण्डल-I
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, बी-रेंज, बम्बई ।	1. न्यास कक्ष 2. कंपनी परिमण्डल-IV 3. बी-I वार्ड 4. बी-II वार्ड 5. फिल्म परिमण्डल 6. कंपनी परिमण्डल-III
3.	अपीलीय सहायक आयुकर आयुक्त, सी-रेंज, बम्बई ।	1. ए-I वार्ड 2. ए-II वार्ड 3. ए-IV वार्ड 4. ए-V वार्ड 5. बी-III वार्ड 6. मार्किट वार्ड 7. कंपनी परिमण्डल-IV 8. कंपनी परिमण्डल-VI 9. विदेशी अनुभाग 10. कर-निर्धारण परिमण्डल-VI
4.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, डी-रेंज, बम्बई ।	1. डी-I वार्ड
5.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, इ-रेंज, बम्बई ।	1. डी-I वार्ड 2. डी-II वार्ड 3. सी-IV वार्ड

1	2	3
6.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, एफ-रेंज, बम्बई ।	1. बी. एस. डी. (एन.) 2. एस. बी. I 3. एस. बी.—II 4. बी. एस. डी. (ई) 5. टी. डी. एस.
7.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, जी-रेंज, बम्बई ।	1. बी. एस. डी. (पश्चिमी) 2. बी. एल. डी. (दक्षिणी)
8.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, एच-रेंज, बम्बई ।	1. सर्वेक्षण परिमण्डल–I (पुरानी) 2. ई—वार्ड
9.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आई-रेंज, बम्बई ।	1. सर्वेक्षण परिमण्डल–II
10.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, जे–रेंज, बम्बई ।	1. जी.—वार्ड 2. जी. ए.—वार्ड 3. कर-निर्धारण रेंज—IX
11.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, के-रेंज, बम्बई ।	1. सी—III वार्ड
12.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, एल-रेंज, बम्बई ।	1. सी—II वार्ड 2. सी.—V वार्ड 3. सी—I वार्ड

जहां कहीं कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त से किसी दूसरे अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त को अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए करनिर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार-क्षेत्र से उक्त परिमण्डल/वार्ड/जिला अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-5-1987 से लागू होगी ।

[सं. 7271/फा. सं. 261/13/87–आ. क. न्या.]

S.O. 1986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it is that behalf and in supersession of all the previous notifications, in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in Column (1) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and/or Districts, specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income assessed to income-tax over which jurisdiction rests with Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S. No.	Ranges with Headquarters	Income-tax Circles, Wards and Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, A-Range, Bombay.	1. X-Ward. 2. N.R.R.C. 3. Professional Circle. 4. B.R.C. 5. A-III Ward 6. Asstt. Circle-II A. 7. Foreign Com Circle-I 8. Company Circle-I 9. Company Circle-II 10. Asstt. Circle-I.

1	2	3
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, B-Range, Bombay.	1. Trust Cell. 2. Company Circle-IV. 3. B-I Ward. 4. B-II Ward. 5. Film Circle. 6. Company Circle-III.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, C-Range, Bombay.	1. A-I Ward 2. A-II Ward 3. A-IV Ward 4. A-V Ward 5. B-III Ward 6. Market Ward 7. Company Circle-IB 8. Company Circle-VI 9. Foreign Section 10. Asstt. Circle-VI.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, D-Range, Bombay.	1. D-I Ward.
5.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, E-Range, Bombay.	1. D-I Ward 2. D-II Ward 3. C-IV Ward
6.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, F-Range, Bombay.	1. B.S.D. (N) 2. S.B. I 3. S.B. II 4. B.S.D. (E) 5. T.D.S.
7.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, G-Range, Bombay.	1. B.S.D. (West) 2. B.S.D. (South)
8.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, H-Range, Bombay.	1. Survey Circle-I (Old) 2. E-Ward.
9.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, I-Range, Bombay.	1. Survey Circle-II
10.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, J-Range, Bombay.	1. G-Ward. 2. GA-Ward 3. Asstt. Range-IX
11.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, K-Range, Bombay.	1. C-III Ward
12.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, L-Range, Bombay.	1. C-II Ward 2. C-V Ward 3. C-I Ward.

Whereas the Income Tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Appellate Assistant Commissioner of Income-tax to another Appellate Assistant Commissioner of Income-tax appeals arising out of the assessments made in that Income Tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax from whom the circle|ward|district is transferred, shall, from the date of this Notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-5-1987.

[No. 7271|F. No. 261|13|87-ITJ]

नई दिल्ली, 7 मई, 1987

का. आ. 1987:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर आयुक्त (अपील) पटियाला, आयकर आयुक्त (अपील) लुधियाना, आयकर आयुक्त (अपील) जालंधर, आयकर आयुक्त (अपील) अमृतसर और आयकर आयुक्त (अपील) जम्मू के संबंध में पहले से जारी की गई बोर्ड की अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ सं. (2) में विनिर्दिष्ट प्रभारों के आयकर आयुक्त (अपील) स्तम्भ (3) और स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर बोर्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर अधिकारी अथवा अतिकर अधिकारी अथवा व्याजकर से, निर्धारिती ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कार्य निर्वहण करेंगे जो आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) से (ज) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी ऐसे आदेश से व्यथित हुए हैं और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी कार्य निर्वहण करेंगे जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उप-धारा (2) के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें ।

अनुसूची

क्रम सं.	अधिकार क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	आयकर बोर्ड/जिला/परिमंडल	नि. म. आ. की रेंज
1	2	3	4
1.	आयकर आयुक्त (अपील); पटियाला	1. आयकर आयुक्त, पटियाला के क्षेत्राधिकार मे आने वाले पटियाला और लुधियाना में स्थित संपदा शुल्क परिमण्डलों सहित लुधियाना/पटियाला, खन्ना, बरनाला, संगरूर, और मलेर कोटला स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले । 2. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना के क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय परिमण्डल, पटियाला ।	1. नि. म. आ., पटियाला । 2 नि. म. आ. रेंज–I, II और III 3. नि. म. आ. (कर-निर्धा.) और 4. नि. म. आ. (कर-निर्धा.) लुधियाना । 5. नि. म. आ. (केन्द्रीय) रेंज-I और II, लुधियाना ।
2.	आयकर आयुक्त (अपील), चण्डीगढ़	1 आयकर आयुक्त, पटियाला के क्षेत्राधिकार मे आने वाले चण्डीगढ़, शिमला, सोलन, पालमपर, मण्डी स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल जिसमें चण्डीगढ़ का सम्पदा शुल्क परिमण्डल भी शामिल है । 2 आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना के क्षेत्राधिकार में आने वाले चण्डीगढ़ और करनाल के केन्द्रीय परिमण्डल । 3 आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक और आयकर आयुक्त, पटियाला के क्षेत्राधिकार में आने वाले जांच परिमण्डल, गुड़गाव, हिसार, रोहतक और यमुनानगर के सर्वेक्षण परिमण्डल । 4 आयकर आयुक्त, रोहतक (हरियाणा) के क्षेत्राधिकार में आने वाले सम्पदा शुल्क परिमण्डलो सहित सभी वार्ड/जिले/परिमण्डल ।	1. नि. म. आ., चण्डीगढ़ 2. नि. म. आ. (कर-निर्धा.), चण्डीगढ़ 1. नि. म. आ. (केन्द्रीय–I और II), लुधियाना । 1 आयकर आयुक्त, हरियाणा रोहतक के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी रेंज ।
3.	आयकर आयुक्त (अपील), लुधियाना ।	1. आयकर आयुक्त, जालन्धर के क्षेत्राधिकार मे आने वाले कपूरथला, होशियारपुर, मोगा, अबोहर, मंसा, फिरोजपुर, मुक्तसर, और भटिंडा के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले । 2. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्राधिकार में आने वाले लुधियाना क्षेत्र के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले ।	1 आयकर आयुक्त, जालंधर अर्थात् स्तम्भ 3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार मे आने वाले सभी क्षेत्र । 2. नि. म. आ. (केन्द्रीय) रेंज–I और II, लुधियाना ।
4.	आयकर आयुक्त (अपील), जालन्धर ।	1. आयकर आयकत, जालन्धर के क्षेत्राधिकार में आने वाले संपदा शुल्क परिमण्डलों सहित जालधर के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले । 2 आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) लुधियाना के क्षेत्राधिकार मे आने वाले जालधर क्षेत्र के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले ।	1 नि म. आ. रेंज–I और II, जालन्धर । 2. नि स. आ. (कर-निर्धा.), जालंधर रेंज-I और II, जालंधर । 3. नि म . आ. (केन्द्रीय), अमृतसर ।

1	2	3	4
5.	आयकर आयुक्त (अपील), अमृतसर।	1. आयकर आयुक्त, अमृतसर के क्षेत्राधिकार में आने वाले सहित अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर और तरनतारन स्थित सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले जिनमें संपदा शुल्क परिमण्डल भी शामिल हैं।	1. स्तम्भ 3 के स्थानों के संबंध में आयकर आयुक्त, अमृतसर के क्षेत्राधिकार में आने वाले नि. स. आयुक्तों की सभी रेंजें। 2. नि. स. आ. (कर-निर्धा.), अमृतसर।
		2. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना के क्षेत्राधिकार में आने वाले अमृतसर क्षेत्र के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले।	3 नि. स. आ (केन्द्रीय), अमृतसर।
6	आयकर आयुक्त (अपील), जम्मू।	1. आयकर आयुक्त, अमृतसर के क्षेत्राधिकार में आने वाले जम्मू, उधमपुर, पठानकोट और श्रीनगर के सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले।	1 स्तम्भ 3 में उल्लिखित स्थानों के संबंध में आयकर आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आने वाले नि. स आ. के रेंज।
		2. आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय परिमण्डल, श्रीनगर।	2 नि. स. आ. (केन्द्रीय) अमृतसर।

जहां कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक अधिकार क्षेत्र से किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में अन्तरित कर दिया गया हो वहां उस आयकर-परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व अधिकार क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें जिसके अधिकार क्षेत्र में आयकर परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से अधिकार क्षेत्र के उस आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना दिनांक, 15-4-1987 से लागू होगी।

[सं. 7272 /फा सं. 261/11/87-आ. क. न्या.]

New Delhi, the 7th May, 1987

S.O. 1987.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of Board's previous notifications issued earlier in respect of Commissioner of Income-tax (Appeals) Patiala, Commissioner of Income-tax, (Appeals), Chandigarh, Commissioner of Income-tax (Appeals), Ludhiana, Commissioner of Income-tax(Appeals), Jalandhar, Commissioner of Income-tax (Appeals), Amritsar and Commissioner of Income-tax (Appeals), Jammu, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax, (Appeals) of the charges specified in Col. No. (2) of the schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax, or sur-tax or Interest-tax, in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in Col. (3) and Col (4) thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) sub-section 11 of Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of Section 15 of the Interest Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of Section 246 of the Income-tax Act, 1961.

SCHEDULE

S. No.	Charge with Headquarters	Income-tax Wards/Distt./Circles.	Range of IAC
1	2	3	4
1	Commissioner of Income-tax (Appeals), Patiala.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Ludhiana, Patiala, Khanna, Barnala, Sangrur, Ropar, and Malerkotla including Estate-Duty Circles located at Patiala and Ludhiana within the jurisdiction of CIT, Patiala.	1. IAC, Range Patiala. 2 IACs, Range-I, II and III, Ludhiana. 3. IAC (Asstt.) Patiala and 4. IAC (Asstt.) Ludhiana.

1	2	3	4
		2. Central Circle, Patiala within the jurisdiction of CIT (Central), Ludhiana.	5. IAC (Central), Range-I & II Ludhiana.
2.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Chandigarh.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Chandigarh, Simla, Solan, Palampur, Mandi within the jurisdiction of CIT, Patiala including Estate Duty Circle, at Chandigarh.	1. IAC ,Chandigarh. 2. IAC (Asstt.) Chandigarh.
		2. Central Circles at Chandigarh and Karnal within the jurisdiction of CIT (Central) Ludhiana.	1. IAC (Central-I & II), Ludhiana
		3. Investigation Circles, Gurgaon, Karnal & Survey Circles at Chandigarh, Gurgaon, Hissar, Rohtak & Yamunanagar within the jurisdiction of CIT, Haryana, Rohtak & CIT, Patiala.	
		4. All Wards/Distt./Circles, including Estate Duty Circles within the jurisdiction of CIT, Rohtak (Haryana).	1. All Ranges within the jurisdiction of CIT, Haryana, Rohtak.
3.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Ludhiana.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Kapurthala, Hoshiarpur, Moga, Abohar, Mansa, Faridkot, Phagwara, Ferozepur, Muktsar and Bhatinda within the jurisdiction of CIT, Jalandhar.	1. All Ranges within the jurisdiction of CIT, Jalandhar vis-a-vis stations mentioned in Col. 3.
		2. All Wards/Circles/Distt. located at Ludhiana within the jurisdiction of CIT, (Central), Ludhiana.	2. IAC (Central) Range-I & II, Ludhiana.
4.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Jalandhar.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Jalandhar, including Estate Duty circles within the jurisdiction of CIT, Jalandhar.	1. IAC, Ranges-I & II, Jalandhar. 2. IAC (Asstt), Jalandhar, Range-I & II, Jalandhar.
		2. All Wards/Circles/Distt. located at Jalandhar within the jurisdiction of CIT (Central), Ludhiana.	3. IAC (Central), Amritsar.
5.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Amritsar.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Amritsar, Batala, Gurdaspur and Taran-Taran, including Estate Duty Circles, within the jurisdiction of CIT, Amritsar.	1. All IACs Ranges, within the jurisdiction of CIT, Amritsar with regard to the stations in Col. 3. 2. IAC (Asstt.) Amritsar.
		2. All Wards/Circles/Distt. located at Amritsar within the jurisdiction of CIT, (Central), Ludhiana.	3. IAC (Central), Amritsar.
6.	Commissioner of Income-tax, (Appeals), Jammu.	1. All Wards/Circles/Distt. located at Jammu, Udhampur, Pathankot and Srinagar within the jurisdiction of CIT, Amritsar.	1. IACs Ranges within the jurisdiction of CIT, Amritsar in respect of stations in Col. 3.
		2. Central Circle, Srinagar, within the jurisdiction of CIT (Central), Ludhiana.	2. IAC (Central), Amritsar.

Whereas the Income-tax Circles, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals, arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or Distt. or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the Charges from whom that Income-tax Circles, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said circle, ward or district or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 15-4-1987.

[No. 7272/F. No. 261/11/87—IJT]

नई दिल्ली, 15 मई, 1987

का.आ. 1988.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 24-2-87 की अधिसूचना सं. 7144 (फा. सं. 261/4/87-आ.क. (न्या.) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है।

I. क्रम सं. (1) स्तम्भ सं. 3 के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

क्र. सं.	रेंज तथा प्रधान कार्यालय	आयकर परिमंडल, वार्ड या जिले
1.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, 'ए' रेंज, मद्रास	8. अनिवासी/परिमण्डल, मद्रास 9. फिल्म परिमण्डल, मद्रास 10. टी.डी.एस. परिमण्डल, मद्रास

II. क्रम सं. (5), स्तम्भ सं. 3 के सामने निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

क्र. सं.	रेंज तथा प्रधान कार्यालय	आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिले
5	अपीलीय सहायक आयुक्त, "ई" रेंज, मद्रास	4. नगर परिमण्डल-5, मद्रास 5. कुड्डालोर, /परिमण्डल 6. पाण्डिचेरी परिमण्डल

III. क्रम सं. 7 और स्तम्भ (2) तथा (3) में इसके सामने की सभी प्रविष्टियों को हटा दिया जायगा।

IV. क्रम सं. 8, 9, 10 तथा 11 को क्रमशः 7, 8, 9 तथा 10 में पुनःअंकित किया जायगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1-6-87 से लागू होगी।

[सं. 7275/फा. सं. 261/21/87—आ.क.न्या.]

New Delhi, the 15th May, 1987

S.O. 1988:— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments to the Notification No. 7144 (F. No. 261/4/87-ITJ) dated 24-2-1987.

I. Against Sl. No. (1) Column No. 3, the following shall be added:

Sl. No.	Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards or Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Madras.	8. Non-Resident Circle, Madras. 9. Film Circles, Madras. 10. TDS Circles, Madras.

II. Against Sl. No. (5), Column No. 3, the following shall be added:

Sl. No.	Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards or Districts.
1	2	3
5.	Appellate Assistant Commissioner 'E' Range, Madras	4. City Circle-V, Madras. 5. Cuddalore Circle. 6. Pondicherry Circle.

III. Sl. No. 7 and all entries in Column No. (2) and (3) against it shall be deleted.

IV. Sl. No. 8, 9, 10 and 11 shall be renumbered as 7, 8, 9 and 10 respectively.

This Notification shall take effect from 1-6-1987.

[No. 7275/F. No. 261/21/87—ITJ]

का.आ. 1989.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीली सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त अपील के क्षेत्राधिकार में निहित है, उक्त अनसूची के स्तम्भ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में, आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपना कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र. सं.	रेंज	आयकर परिमण्डल/वार्ड/जिले
1.	अपीलीय सहायक, आयकर आयुक्त, जालंधर रेंज, जालंधर	1. जालंधर में कार्य कर रहे सभी परिमण्डल/वार्ड/जिले जिनमे केन्द्रीय परिमण्डल, विशेष परिमण्डल, जांच परिमण्डल तथा सर्वेक्षण परिमण्डल भी शामिल है। 2. होशियारपुर, फगवाड़ा, कपूरथला, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, भटिण्डा, अबोहर, मुक्तसर तथा मानसा में कार्य कर रहे सभी परिमण्डल/वार्ड/जिले जिनमें विशेष परिमण्डल तथा सर्वेक्षण परिमण्डल भी शामिल हैं।

जहां कहीं कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा भटिण्डा रेंज से जालंधर में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड, जिला अथवा उसके किसी भाग में दिए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व भटिण्डा रेंज के अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें जिसके अधिकार क्षेत्र से उक्त आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, अपीलीय सहायक आयुक्त, जालंधर रेंज, जालंधर द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

जहां किसी विशिष्ट स्थान के प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्ड, परिमण्डल तथा जिले एक अपीलीय सहायक आयुक्त को सौंपे गए हैं, वहां वह हाल ही में समाप्त इन प्रधान कार्यालयों के परिमण्डलों, वार्डों तथा जिलों के संबंध में भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे।

यह अधिसूचना 1-6-1987 से लागू होगी।

[सं. 7276/फा.सं. 261/79/87-आ.क.न्या.]

S.O. 1989:— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous Notification in this behalf, the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range specified in Column (2) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and Incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (3) thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (A):—

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles/Wards/Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Jalandhar Range, Jalandhar.	1. All Circles/Wards/Distt. Functioning at Jalandhar including Central Circles, Special Circles, Investigation Circles and Survey Circles. 2. All Circles/Wards/Distt. functioning at Hoshiarpur, Phagwara, Kapurthala, Moga, Faridkot, Ferozepur, Bhatinda, Abohar, Muktsar and Mansa in-including Special Circles and Survey Circles.

Whereas the Income-tax Circles, Wards and Districts or part thereof stands transferred by this Notification from Bhatinda Range to Jalandhar Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circles, Wards or District or part thereof pending immediately before the date of this Notification before the AAC, Bhatinda Range from which the Income-tax Circles. Ward or District or part thereof is transferred to and shall be dealt with by the A.A.C. Jalandhar Range, Jalandhar to whom the said Circles, Ward or District or part thereof is transferred.

Where all circles, wards or districts having headquarters, at a particular place have been assigned to an Appellate Asstt. Commissioner, he will have jurisdiction in respect of Circles, Wards and Districts at these headquarters since abolished also.

This notification shall take effect from 1-6-1987.

[No. 7276/F. No. 261/19/87—ITJ]

नई दिल्ली, 27 मई, 1987

का.आ. 1990—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिसंशोधन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद् द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	अपीलीय सहायक आयुक्त की रेंज	आयकर परिमण्डल, वार्ड तथा जिला
1	2	3
1	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त "क" रेंज, हैदराबाद।	1 परिमण्डल-1, हैदराबाद
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, "ख" रेंज, हैदराबाद।	1. करीम नगर परिमण्डल 2 खम्माम परिमण्डल 3 परिमण्डल-4, हैदराबाद 4 फिल्म परिमण्डल, हैदराबाद 5. केन्द्रीय परिमण्डल, हैदराबाद 6 कंपनी परिमण्डल, हैदराबाद 7 वेतन परिमण्डल, हैदराबाद
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, "ग" रेंज, हैदराबाद	1. परिमण्डल III, हैदराबाद
4.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त "घ" रेंज, हैदराबाद।	1. परिमण्डल-III हैदराबाद (परिमण्डल-II) 2. विशेष जांच परिमण्डल-I, हैदराबाद 3. विशेष परिमण्डल-I तथा III 4 सर्वेक्षण परिमण्डल, हैदराबाद 5. महबूब नगर परिमण्डल 6. निज़ामाबाद परिमण्डल 7. वारंगल परिमण्डल 8. निर्मल परिमण्डल 9. सांगरेड्डी परिमण्डल 10. विशेष जांच परिमण्डल 11 विशेष परिमण्डल, हैदराबाद 12. नाल गोंडा परिमण्डल।

जहां कहीं कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया गया हो वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीली सहायक आयुक्त के समक्ष विचाराधीन बड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना दिनांक 1-5-1987 से लागू होगी।

[सं. 7314/फा.स. 261/20/87-आ.क. न्या.]

New Delhi, the 27th May, 1987

S.O. 1990 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all the previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes, hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (2) of the Schedule below shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to Income-tax in the Income-tax circles, wards and districts specified in the corresponding entry in column No. 3 thereof excluding all persons and incomes assessed to Income-tax over which the jurisdiction vest in the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S. No.	Appellate Assistant Commissioner's Range	Income-tax Circle, Ward and District
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'A' Range, Hyderabad.	1. Circle-I, Hyderabad.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'B' Range, Hyderabad.	1. Karimnagar Circle. 2. Khammam Circle. 3. Circle–IV, Hyderabad. 4. Film Circle, Hyderabad. 5. Central Circle, Hyderabad. 6. Company Circle, Hyderabad. 7. Salary Circle, Hyderabad.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'C' Range, Hyderabad.	1. Circle–III, Hyderabad.
4.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, 'D' Range, Hyderabad.	1. Circle–II, Hyderabad (Circle–II). 2. Spl. Inv. Circle–I, Hyderabad. 3. Spl. Circle–I & III 4. Survey Circle, Hyderabad. 5. Mahaboobnagar Circle. 6. Nizamabad Circle. 7. Warangal Circle. 8. Nirmal Circle. 9. Sangareddy Circle. 10. Spl. Inv. Circle. 11. Spl. Circle, Hyderabad. 12. Nalgonda Circle.

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range, appellate arising out of assessments made in that circle, ward or district or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 1-5-1987.

[No. 7314/F. No. 261/20/87-ITJ]

का० आ० 1991 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1), धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 9, दानकर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अभिलंघन करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर/धनकर/दानकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय/धन/दान को छोड़कर जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) को तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमण्डलों, वार्डों और जिलों में आयकर/धनकर/दानकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय/धन/दान के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

रेंज तथा प्रधान कार्यालय	आयकर परिमण्डल वार्ड तथा जिले
1	2
1 अपीलीय सहायक, आयकर आयुक्त, रेंज–I, बंगलौर	1. परिमण्डल–I, बंगलौर 2 विदेश अनुभाग, बंगलौर 3 कम्पनी परिमण्डल–I में VII, बंगलौर 4 ट्रस्ट परिमण्डल, बंगलौर 5 फिल्म परिमण्डल, बंगलौर 6 बेलारी परिमण्डल, बेलारी 7. हॉस्पेट परिमण्डल, हॉस्पेट
2. अपीलीय सहायक, आयकर आयुक्त रेंज–II, बंगलौर।	1. परिमण्डल–II, बंगलौर 2. परिमण्डल–IV, बंगलौर 3 सर्वेक्षण परिमण्डल, बंगलौर 4. केन्द्रीय परिमण्डल, बंगलौर 5 जांच परिमण्डल, बंगलौर 6 मैसूर परिमण्डल, मैसूर 7 माण्डया परिमण्डल, माण्डया 8 हासन परिमण्डल, हासन 9. टुमकुर परिमण्डल, टुमकुर
3 अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज–III, बंगलौर।	1. परिमण्डल–III, बंगलौर 2 बेलन परिमंडल, बंगलौर 3 कोलार परिमण्डल, कौलार 4 चिकमगलूर परिमण्डल, चिकमगलूर 5 उडापी परिमण्डल, उडापी 6 कूर्ग परिमण्डल, मेरकर 7 मंगलौर परिमण्डल, मंगलौर 8 संपदाशुल्क एवं आयकर परिमण्डल, बंगलौर (आयकर/धनकर/दानकर के मामले) 9 रायचूर परिमण्डल, रायचूर 10 गुलबर्ग परिमण्डल, गुलबर्ग।
4 अपीलीय सहायक, आयकर आयुक्त, धारवाड रेंज, हुबली	1 हुबली परिमण्डल, हुबली 2 धारवाड़ परिमण्डल, धारवाड 3 गाड़ग परिमण्डल, गाडग 4 शिमोगा परिमण्डल, शिमोगा 5 चित्रदुर्ग परिमण्डल, चित्रदुर्ग 6 कारवांड परिमण्डल, कारवाड 7 देवगिरि परिमण्डल, देवगिरि 8 बीजापुर परिमण्डल, बीजापुर 9. बगलकोट परिमण्डल, बगलकोट 10. पणजी परिमण्डल, पणजी 11 मारगाव परिमण्डल, मारगाव 12 बेलगाम परिमण्डल, बेलगाम

2. जहां कहीं कोई आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपील इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष

विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से उक्त आयकर परिमण्डल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी, और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना दिनांक 1-6-1987 से लागू होगी।

टिप्पणी :—सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 4 की उपधारा 2-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-III, बंगलौर को, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा जारी की गई दिनांक 28-12-1982 की अधिसूचना सं० 59/82/फा०सं०/307 11/82-सं०शु० के अनुसार दिनांक 3-1-1983 से उन सम्पदा शुल्क अपीलों के संबंध में संपदा शुल्क अपीलीय नियंत्रक, बंगलौर के रूप में नियुक्त किया है जो संपदा शुल्क अपीलीय नियंत्रक [आयकर आयुक्त (अपील)-III, बंगलौर] के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। इस प्रकार संपदा शुल्क की उन अपीलों को छोड़कर जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार में आती है, सम्पदा शुल्क नियंत्रक, बंगलौर के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सहायक संपदा शुल्क नियंत्रकों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ की गई संपदा शुल्क अपीलें, अपीलीय सम्पदा शुल्क नियंत्रक, बंगलौर (अपीलीय सहायक आयुक्त रेंज-III, बंगलौर) के क्षेत्राधिकार में आएंगी।

[सं० 7315 /फा० सं० 261/23/87-आ०क०न्या०]

S.O. 1991 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) Section 9 of Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); Section 8 of the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958) and in supersession of all previous notifications in this regard the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all the persons and the Income/Health/gift assessed to income-tax/Wealth-tax/gift tax in the Income-tax Circle, Wards and Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding all persons and income/wealth/gift assessed to Income-tax/Wealth-tax/Gift-tax over which the jurisdiction vests with the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

S. No.	Ranges with Head Quarters	Income-tax, Circles, Wards & Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Bangalore.	1. Circle-I, Bangalore. 2. Foreign Section, Bangalore. 3. Company Circles-I to VII, Bangalore. 4. Trust Circle, Bangalore. 5. Film Circle, Bangalore. 6. Bellary Circle, Bellary. 7. Hospet Circle, Hospet.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II, Bangalore.	1. Circle-II, Bangalore. 2. Circle-IV, Bangalore. 3. Survey Circles, Bangalore 4. Central Circles, Bangalore. 5 Investigation Circle, Bangalore. 6. Mysore Circle, Mysore. 7. Mandya Circle, Mandya. 8. Hassan Circle, Hassan. 9. Tumkur Circle, Tumkur.
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-III, Bangalore.	1. Circle-III, Bangalore. 2. Salary Circle, Bangalore. 3. Kolar Circle, Kolar. 4. Chickmagalur Circle, Chickmagalur. 5. Udapi Circle, Udapi. 6. Coorg Circle, Mercar. 7. Mangalore Circle, Mangalore. 8 E.D. Cum-Income-tax Circle Bangalore (Income-tax/Wealth-tax/Gift-tax cases). 9. Raichur Circle, Raichur. 10. Gulbarga Circle, Gulbarga.

1	2	3
4.	Appellate Assisstant Commissioner of Income-tax, Dharwar Range, Hubli.	1. Hubli Circle, Hubli. 2. Dharwar Circle, Dharwar. 3. Gadag Circle, Gadag. 4. Shimoga Circle, Shimoga. 5. Chitradurga Circle, Chitradurga. 6. Karwar Circle, Karwar. 7. Davangere Circle, Davangere. 8. Bijapur Circle, Bijapur. 9. Bagalkot Circle, Bagalkot. 10. Panaji Circle, Panaji. 11. Margao Circle, Margao. 12. Belgaum Circle, Belgaum.

2. Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands trnsferred by this Notification from one range to another range, as appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before Appellate Assistant Commissioner of the range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date this notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said circles, ward or district or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-6-1987.

Note : In exercise of the powers conferred by sub-section 2A of Section 4 of 1953 (34 of 1953), the Central Government has appointed the Appellate Assistant Commissioner of Income-Tax, Range-III, Bangalore as the Appellate Controller of Estate Duty, Bangalore in respect of Estate Duty appeals over which the jurisdiction do not vest with the Appellate Controller or Estate Duty (Commissioner of Income-tax (Appeals)-III, Bangalore with effect from 3-1-1983 as per Notification No. 59|82|F. No. 307|11|82-ED dated 28-12-1982 issued by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi. Hence the Appellate Controller of Estate Duty, Bangalore (AAC Range-III, Bangalore) will have jurisdiction over estate duty appeals against orders passed by all Assistant Controller of Estate Duty within the jurisdiction of the Controller of Estate Duty Banagalore other than the Estate Duty appeal in respect of which the jurisdiction vests with the Commissioner of Income-tax (Appeals).

[No. 7315|F. No. 261|23|87-ITJ]

नई दिल्ली, 3 जून, 1987

का. आ. 1992.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इस संबंध मे सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओ का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) मे विनिर्दिष्ट रेंजो के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, आयकर मे निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय को छोड़कर, जो आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार मे निहित है, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलो, वार्डों और जिलों मे आयकर मे निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध मे अपना कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं०	रेंज	आयकर परिमण्डल/बोर्ड/जिले
1	2	3
1	अपीलीय सहायक आयकर, आयुक्त नागपुर रेंज, नागपुर	1. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, नागपुर 2. —तदैव—, क-वार्ड, नागपुर 3. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, नागपुर 4 —तदैव— ग-वार्ड, नागपुर 5 —तदैव— घ-वार्ड, नागपुर 6 —तदैव— ङ-वार्ड, नागपुर 7 —तदैव— च-वार्ड, नागपुर 8 —तदैव— छ-वार्ड, नागपुर 9 —तदैव— ज-वार्ड, नागपुर 10. अपर आयकर अधिकारी, ज-वार्ड, नागपुर

1	2	3
		11 आयकर अधिकारी, झ-वार्ड, नागपुर
		12 अपर आयकर अधिकारी, झ-वार्ड, नागपुर
		13 आयकर अधिकारी, ञ-वार्ड नागपुर
		14 —तदैव— ट-वार्ड, नागपुर
		15 —तदैव— ठ-वार्ड, नागपुर
		16. —तदैव— ड-वार्ड, नागपुर
		17 —तदैव— ढ-वार्ड, नागपुर
		18 —तदैव— त-वार्ड, नागपुर
		19 अपर आयकर अधिकारी, त-वार्ड, नागपुर
		20 आयकर अधिकारी, नगर परिमंडल, नागपुर
		21 आयकर अधिकारी, क-वार्ड, गोंडिया
		22 आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, गोंडिया
		23 —तदैव— क-वार्ड, चन्द्रपुर
		24 —तदैव— ख-वार्ड, चन्द्रपुर
		25 प्रथम आयकर अधिकारी, ट्रस्ट परिमण्डल, नागपुर
		26 द्वितीय आयकर अधिकारी, ट्रस्ट परिमंडल, नागपुर
		27 आयकर अधिकारी, ट्रस्ट एवं सपदा शुल्क परिमंडल, नागपुर
		28 सहायक सपदा शुल्क नियंत्रक, नागपुर
		29 आयकर अधिकारी, परिमंडल-1 (1), नागपुर
		30 —तदैव— परिमंडल-1(2), नागपुर
		31 —तदैव— परिमंडल-1(3), नागपुर
		32 —तदैव— परिमंडल-1(4), नागपुर
		33 —तदैव— परिमंडल-1(5) नागपुर
		34 —तदैव— परिमंडल-1(6), नागपुर
		35 —तदैव— परिमंडल-II(1), नागपुर
		36 —तदैव— परिमंडल-II(2), नागपुर
		37 —तदैव— परिमंडल-II(3), नागपुर
		38 —तदैव— परिमंडल-III(1), नागपुर
		39 —तदैव— परिमंडल-III(2), नागपुर
		40 —तदैव— परिमंडल-III(3), नागपुर
		41 —तदैव— परिमंडल-III(4), नागपुर
		42 —तदैव— परिमंडल-III(5), नागपुर
		43 आयकर अधिकारी, ट्रस्ट परिमंडल नागपुर
		44 प्रथम आयकर अधिकारी, वेतन परिमंडल, नागपुर
		45 द्वितीय —तदैव— सर्वेक्षण परिमंडल, नागपुर
		46 प्रथम आयकर अधिकारी सर्वेक्षण परिमंडल, नागपुर
		47 द्वितीय—तदैव— सर्वेक्षण परिमंडल, नागपुर
		48 तृतीय —तदैव— सर्वेक्षण परिमंडल, नागपुर
		49 प्रथम आयकर अधिकारी, कर-निर्धारण, नागपुर
		50 द्वितीय—तदैव— कर-निर्धारण नागपुर
		51 तृतीय —तदैव— कर-निर्धारण नागपुर
		52 प्रथम —तदैव—गोंडिया
		53 द्वितीय —तदैव—, गोंडिया
		54 आयकर अधिकारी, विदेश अनभाग, नागपुर
		55 आयकर अधिकारी गोंडिया
		56 —तदैव— भंडारा
		57 प्रथम आयकर अधिकारी, चन्द्रपुर
		58 द्वितीय आयकर अधिकारी, चन्द्रपुर
		59 अपर आयकर अधिकारी, परिमंडल-1(2), नागपुर।

1	2	3
2. अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, अकोला।		1. आयकर अधिकारी, क-वार्ड, अकोला
		2. अपर आयकर अधिकारी क-वार्ड, अकोला
		3. आयकर अधिकारी, ख-वार्ड, अकोला
		4. —तदैव— ग-वोर्ड, अकोला
		5. —तदैव— घ-वोर्ड, अकोला
		6. —तदैव— ङ-वोर्ड, अकोला
		7. —तदैव— क-वोर्ड, अमरावती।
		8. —तदैव— ख-वार्ड, अमरावती
		9 —तदैव— ग-वार्ड, अमरावती।
		10. —तदैव— घ-वार्ड, अमरावती।
		11. —तदैव— क-वार्ड, वर्धा।
		12. —तदैव— ख-वार्ड, वर्धा।
		13 —तदैव— यवत्मल
		14. —तदैव— ख-वार्ड, यवत्मल।
		15. सहायक सपदा शुल्क, नियंत्रक, अकोला।
		16. प्रथम आयकर अधिकारी, अकोला।
		17. द्वितीय —तदैव— अकोला।
		18. तृतीय —तदैव— अकोला।
		19. चतुर्थ आयकर अधिकारी, अकोला।
		20. प्रथम आयकर अधिकारी, अमरावती।
		21 द्वितीय —तदैव— अमरावती।
		22 तृतीय —तदैव— अमरावती।
		23. चतुर्थ —तदैव— अमरावती।
		24. अपर चतुर्थ आयकर अधिकारी, अमरावती।
		25. प्रथम आयकर अधिकारी, वर्धा।
		26. द्वितीय —तदैव— वर्धा।
		27. प्रथम आयकर अधिकारी, यवत्मल।
		28 द्वितीय —तदैव— यवत्मल।
		29. आयकर अधिकारी, खामगाव।
		30 आयकर अधिकारी, केन्द्रीय परिमंडल-I, नागपुर
		31 —तदैव— केन्द्रीय परिमंडल-II, नागपुर
		32 —तदैव— केन्द्रीय परिमंडल-III, नागपुर
		33 —तदैव— केन्द्रीय परिमंडल-IV, नागपुर
		34. आयकर अधिकारी, केन्द्रीय परिमंडल-क, नागपुर
		35. —तदैव— केन्द्रीय परिमंडल-ख, नागपुर
		36. —तदैव— केन्द्रीय परिमंडल-ग, नागपुर
		37 —तदैव— केन्द्रीय (जांच), अकोला
		38. —तदैव— (जांच) वर्धा।
		39. —तदैव— (जांच) यवत्मल।

जहां कहीं कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र से उक्त आयकर परिमंडल, वार्ड या जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त को अन्तरित की जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिमंडल, वार्ड और जिला अथवा उसका कोई भाग अन्तरित किया गया हो।

यह अधिसूचना दिनांक 28-4-1987 से लागू होगी।

[स. 7324 फा स. 261/25/87-आ. क. न्या]

New Delhi, the 3rd June, 1987

S.O. 1992 In exercise of the powers conferred in sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous notification in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellat Assistant Commissioners of Income-tax of the Ranges specified in column (1) of the Schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax in the Income-tax Circles/Wards/Districts specified in the corresponding entry in column (2) thereof excluding al persons and income assessed to Income-tax over which the jurisdiction vests in Commissioners of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax Circles/Wards/Districts
1	2	3
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Nagpur Range, Nagpur.	1. Income-tax Officer, A-Ward, Nagpur.
		2. –do– A-Ward, Nagpur.
		3. Income-tax Officer, B-Ward, Nagpur.
		4. –do– C-Ward, Nagpur.
		5. –do– D-Ward, Nagpur.
		6. –do– E-Ward, Nagpur.
		7. –do– F-Ward, Nagpur.
		8. –do– G-Ward, Nagpur.
		9. –do– H-Ward, Nagpur.
		10. Addl. Income-tax Officer, H-Ward, Nagpur.
		11. Income-tax Officer, I-Ward, Nagpur.
		12. Addl. Income-tax Officer, I-Ward, Nagpur.
		13. Income-tax Officer, J-Ward, Nagpur.
		14. –do– K-Ward, Nagpur.
		15. –do– L-Ward, Nagpur.
		16. –do– M-Ward, Nagpur.
		17. –do– N-Ward, Nagpur
		18. –do– P-Ward, Nagpur.
		19. Addl. Income-tax Officer, P-Ward, Nagpur.
		20. Income-tax Officer, City Circle, Nagpur.
		21. Income-tax Officer, A-Ward, Gondia.
		22. Income-tax Officer, B-Ward, Gondia.
		23. –do– B-Ward, Gondia.
		23. –do– A-Ward, Chandrapur.
		24. –do– B-Ward, Chandrapur.
		25. Ist Income-tax Officer, Trust Circle, Nagpur.
		26. –do– Trust Circle, Nagpur.
		27. Income-tax Officer, Trust cum-Estate Duty Circle, Nagpur.
		28. Asst. Controller of Estate Duty Nagpur.
		29. Income-tax Officer, Circle-I(1), Nagpur.
		30. –do– Circle-I(2), Nagpur.
		31. –do– Circle-I(3), Nagpur.
		32. –do– Circle-I(4), Nagpur.
		33. –do– Circle-I(5), Nagpur.
		34. –do– Circle-I(6), Nagpur.
		35. –do Circle-II(1) Nagpur.
		36. –do– Circle-II(2), Nagpur.
		37. –do– Circle-II(3) Nagpur.
		38. –do– Circle-III (1), Nagpur.
		39. –do– Circle-III(2), Nagpur.
		40. do– Circle-III(3), Nagpur.

1	2	3
		41. –do– Circle-III(4), Nagpur.
		42. –xo– Circle-III(5), Nagpur.
		43. –do– Trust Circle, Nagpur.
		44. 1st Income-tax Officer, Salary Circle, Nagpur.
		45. 2nd –do– Salary Circle, Nagpur.
		46. 1st Income-tax Officer, Survey Circle, Nagpur.
		47. 2nd –do– Survey Circle, Nagpur.
		48. 3rd –do– Survey Circle, Nagpur.
		49. 1st Income-tax Officer, Asstt. Nagpur.
		50. 2nd –do– Asstt. Nagpur.
		51. 3rd –do– Asstt. Nagpur.
		52. 1st –do– Gondia.
		53. 2nd –do– Gondia.
		54. Income-tax Officer, Foreign Section, Nagpur.
		55. Income-tax Officer, Gondia.
		56. –do– Bhandar.
		57. 1st Income-tax Officer, Chandrapur.
		58. 2nd Income-tax Officer, Chandrapur.
		59. Addl. Income-tax Officer, Circle I(2), Nagpur.
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Akola.	1. Income-tax Officer, A. Ward, Akola.
		2. Addl. Income-tax Officer, A-Ward, Akola.
		3. Income-tax Officer, B-Ward, Akola.
		4. –do– C-Ward, Akola.
		5. –do– D-Ward, Akola.
		6. –do– E-Ward, Akola.
		7. –do– A-Ward, Amravati.
		8. –do– B-Ward, Amravati.
		9. –do– C-Ward, Amravati.
		10. –do– D-Ward, Amravati.
		11. –do A-Ward, Wardha.
		12. –do– B-Ward, Wardha.
		13. –do– A-Ward, Yavatmal.
		14. –do– B-Ward, Yavatmal.
		15. Assistant Controller of Estate Duty, Akola.
		16. 1st Income-tax Officer, Akola.
		17. 2nd –do– Akola.
		18. 3rd –do– Akola.
		19. 4th –do– Akola.
		20. 1st Income-tax Officer, Amravati.
		21. 2nd –do– Amravati.
		22. 3rd –do– Amravati.
		23. 4th –do– Amravati.
		24. Addl. 4th –do– Amravati.
		25. 1st Income-tax Officer Wardha.
		26. 2nd –do– Wardha.
		27. 1st Income-tax Officer, Yavatmal.
		28. 2nd –do– Yavatmal.
		29. Income-tax Officer, Khamgaon.
		30. Income-tax Officer, Central Circlcle-I, Nagpur.
		31. –do– Central Circle-II, Nagpur.
		32. –do– Central Circle-III, Nagpur.
		33. –do– Central Circle-IV, Nagpur.

1	2	3
		34. Income-tax Officer, Central Circle-A, Nagpur.
		35. -do- Central Circle-B, Nagpur.
		36. -do- Central Circle, C, Nagpur.
		37 -do- (Investigation), Akola.
		38. -do- (Investigation), Wardha.
		39. -do- (Investigation), Yavatmal.

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range appeals arising out of assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date of this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 28-4-1987.

[No. 7324/F. No. 261/25/87-ITJ]

नई दिल्ली, 4 जून, 1987

शुद्धिपत्र

का.आ. 1993—दिनांक 15 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 7246(फा.सं. 261/8/87-आ.क.न्या.) देखें जिसमें आयकर आयुक्त (अपील), आंध्र प्रदेश के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है । क्र.सं. 3 पर उल्लिखित आयकर आयुक्त (अपील)-III हैदराबाद के क्षेत्राधिकार में से निम्नलिखित को हटाया जायेगा तथा मद संख्या 9 से 18 को क्रमानुसार 7 से 16 में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ।

हटाया जाये] "7. गण्टूर परिमण्डल

8. विशेष जांच परिमंडल, गुण्टूर"

यह शुद्धिपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1987 से लागू होगा ।

[सं. 7325/फा.सं. 261/8/87-आ.क.न्या]

के.पी. गांगुली,

विशेष कार्य अधिकारी (न्या.)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

New Delhi, the 4th June, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 1993.—Refer Notification No. 7246 (F. No. 261|8|87-ITJ) dated the 15 April, 1987 specifying jurisdiction of Commissioners of Income-tax (Appeals), Andhra Pradesh. In the jurisdiction of Commissioner of Income-tax (Appeals)-III, Hyderabad mentioned at S. No. 3 the following shall be deleted from the jurisdiction of C.I.T. (Appeals)-III, Hyderabad and items No. 9 to 18 shall be renumbered as 7 to 16 consecutively.

Delete "7 Guntur Circle

8 Spl. Inv. Circle, Guntur".

This comes into effect from 15th April, 1987.

[No. 7325/F. No. 261/8/87-ITJ]

K. P. GANGULI, O.S.D.(J)

Central Board of Direct Taxes

(सीमाशुल्क समाहर्ता का कार्यालय)

बंगलौर 6 मार्च, 1987

सीमाशुल्क

(अधिसूचना सं 1/87-सीमा)

का.आ. 1994.—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जे.पी. कौशिक, सीमाशुल्क समाहर्ता, कर्नाटक सीमाशुल्क समाहर्तालय, बंगलौर एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्ता, बंगलोर के दिनांक 18-3-1976 की अधिसूचना नं. 1/76 में निम्नप्रकार संशोधन करता हूं जैसे : उक्त बतायी गयी अधिसूचना की सारणी में क्रमांक 2 से सम्बन्धित प्रविष्टियों को छोड़ दिया जाये ।

[सी.न. VIII 8/48/106/86-सी 2/सीमा]

जे.पी. कौशिक, समाहर्ता

(Office of the Collector of Customs)

Bangalore, the 6th March, 1987

CUSTOMS

(Notification No. 1/87-Cus.)

S.O 1994.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Customs Act, 1962, I J. P. Kaushik, Collector of Customs, Karnataka Customs Collectorate, Bangalore, hereby make the following amendment in Notification of the Collector of Customs and Central Excise, Bangalore No. 1|76 dated the 18th March, 1976, namely :—

In the said Notification, in the Table, Sl. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

[C No VIII/48/106/86-C-2|Cus.]

J. P. KAUSHIK, Collector

(समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : मध्य प्रदेश)

इन्दौर, 17 जुलाई, 1987

अधिसूचना संख्या 8/87

का. आ. 1995:—मध्यप्रदेश समाहर्तालय के श्री आर. के. थावानी, अधिक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" 28-5-87 के अपरान्ह में शासकीय सेवा से स्वैच्छीक सेवानिवृत्त हुए ।

[प०सं० II(3)/3-गोप/87]

(Central Excise Collectorate, M.P.)
Indore, the 17th July, 1987

(NOTIFICATION NO. 8/87)

S.O. 1995.—Shri R. K. Thawani, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Central Excise Collectorate, Indore has voluntarily retired from the Government service in the afternoon of 28-5-1987.

[C. No. II(3)/3-Con/87]

(अधिसूचना संख्या 11/87)

का. आ. 1996.—समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इन्दौर के श्री मुस्ताफा खान, अधीक्षक समूह "ख" निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-6-87 के अपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए ।

[प. सं II (3)/3-गोप/87]

ना० राजा, समाहर्ता

TIFICATION NO. 11/87)

S O. 1996.—Shri Mustafa Khan, Superintendent, Central Excise Group 'B' of Indore Collectorate having attained the age of Superannuation retired from Government service on 30-6-87 in the afternoon.

[C No. II(3)/3-Con/87]

N. RAJA, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1987

का. आ 1997.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रंगलेप तथा संबंध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987* का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्—

"6. निरीक्षण फीस.—इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को प्रत्येक परेषण के पात-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए पर 50 पैसे की दर से फीस दी जाएगी ।"

[फाइल सं 6(26)/86-ई आई एंड ईपी]

एन० एस० हरिहरन, निदेशक

*पाद टिप्पण—मूल नियम का० आ० 308 तारीख 7-2-1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 8th August, 1987

S O. 1997.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987* namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987, for rule 6, the following rule shall be substituted namely :—

"6. Inspection fee—a fee at the rate of 50 paise for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules."

[F. No. 6(26)/86-EI&EP]

N S HARIHARAN, Director

Foot note—The principal rules were published vide S O. 308 dt 7-2-1987.

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

का आ 1998.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है । उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रम है, जिन्हें उक्त अधिनियम के भाग-क के अध्याय-III के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं।

[स. 16/12/86-एम.-3]

अधिसूचना स. 16/12/86—एम — III का अनुलग्नक

क्रम सं	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण संख्या
1.	मैसर्स कानपुर टैक्सटाइल्स लिमिटेड।	85/20, कपूरगंज, कानपुर	161/70
2.	मैसर्स एग्री प्रसीसन्स इंजीनियर्स लिमिटेड,	निकट आई. टी. आई. पो. ओ. कुबेरनगर/ सरदार नगर, अहमदाबाद-382340	2246/85

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 1998.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M-III]

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION NO. 16/12/86.M-III

Sl. No.	Name of the Undertakings	Registered Address	Registration No.
1.	M/s Cawnpore Textiles Limited.	85/20, Cooperganj Kanpur.	161/70
2.	M/s. Agro Precisions Implements Ltd.	Near ITI P.O. Kubernagar/ Sardarnagar, Ahmedabad-382340.	2246/85

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.आ. 1999.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण की अधिसूचना करती है। उक्त उपक्रम ऐसे उपक्रम हैं, जिन्हें उक्त अधिनियम के भाग-क के अध्याय-III के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं।

[सं. 16/12/86-एम-3]

एल.सी. गोयल, अवर सचिव

अधिसूचना सं. 16/12/86-एम.-3 का अनुलग्नक

क्रम सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण संख्या
1	2	3	4
1.	मै. मामली प्राइवेट लि.	नारंग हाउस, 34, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग बम्बई-400039	1482/80
2.	मै. सोमैया शुगर वर्क्स लि.	फाजलभाय बिल्डिंग, 45/47 महात्मा गांधी रोड, बम्बई-400023	1233/75
3.	मै. सोमैया केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,	फाजलभाय बिल्डिंग, 45/47, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-400023	1349/77
4.	मै. सकरवाडी शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, (अब सकरवाडी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड)	यूसुफ बिल्डिंग, 43, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, बम्बई, 23	1234/75
5.	मै. लक्ष्मीवाडी शुगर फैक्ट्री लिमिटेड	—यथोपरि—	1235/75

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 7th July, 1987

S.O. 1999.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

[No. 16/12/86-M-III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

ANNEXURE TO THE NOTIFICATION NO. 16/12/86-M. III.

Sl. No.	Name of the Undertakings	Regd. Address	Registration No.
1	2	3	4
1	M/s. Mamli Private Limited.	Narang House, 34, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay-400 039.	1482/80
2.	M/s. Somaiya Sugar Works Limited	Fazalbhoy Bldg., 45/47, Mahatama Gandhi Road, Bombay-400 023.	1233/75
3.	M/s. Somaiya Chemical Industries Limited.	Fazalbhoy Bldg., 45/47, Mahatama Gandhi Road, Bombay-400 023.	1349/77
4.	M/s. Sakarvadi Sugar Factory Limited (now Sakarvadi Trading Company Limited).	Yusuf Building, 43, Mahatama Gandhi Road, Fort Bombay-23.	1234/75
5	M/s. Lakshmiwadi Sugar Factory Limited.	-do-	1235/75

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 22 जुलाई 1987

का. आ. 2000—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्य किए जाने की संभावना है,

अत: केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी–1 (ई) III/जे जे आर/388–387, तारीख 5 मार्च, 1987 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्डस लि. (राजस्व विभाग) कोल एस्टेट सिविल लाईन्स नागपुर, 440001 या कलक्टर चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., कोल एस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर –440001 को भेजेंगे।

अनुसूची

दियूलवाड़ा ब्लाक वणी क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

क्र. सं	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	माजरी	4	भद्रावती	चन्द्रापुर	115.00	भाग
2	दियूलवाड़ा	4	भद्रावती	चन्द्रपुर	676.39	भाग
3.	कुणाद	28	भद्रावती	चन्द्रपुर	165.00	भाग
			योग		953.39 हैक्टर (लगभग) या 2355.92 एकड़ (लगभग)	

सीमा वर्णन

क—ख—ग रेखा बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और ग्राम माजरी और दियूलवाड़ा से होकर जाती है और बिन्दु "ग" से मिलती है।

ग—घ रेखा, ग्राम बिर्जासम और दियूलवाड़ा की सम्मिलित सीमा के साथ–साथ जाती है और बिन्दु "घ" से मिलती है।

घ—ङ रेखा ग्राम दियूलवाड़ा और चारगाव, कुणाद और चारगाव की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ङ" से मिलती है।

ङ—च रेखा, ग्राम कुणाद से होकर जाती है और बिन्दु "च" से मिलती है।

च—क रेखा, ग्रामा कुणाद दियूलवाड़ा, माजरी की बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" से मिलती है।

[सं. 43015/9/87 सी.ए.]

MINISTRY OF ENERGY)

(Department of Coal)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2000 — Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the schedule hereto annexed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan bearing No. C-1 (E) /III/JJR/388—387 dated the 5th March, 1987, of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 or at the Office of the Collector Chandrapur (Maharashtra) or at the Office of the Coal Controller-1, Council House, Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section -13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440 001 within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

DEULWADA BLOCK

WANI AREA

DISTRICT-CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Serial Number	Name of village	Patwari Circle Number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	MAJRI	4	Bhadravati	Chandrapur	115.00	Part
2.	DEULWADA	4	Bhadravati	Chandrapur	673.39	Part
3.	KUNAD	28	Bhadravati	Chandrapur	165.00	Part

Total area 953.39 hectares (approximately), or 2355.92 acreas (Approximately)

Boundary description :

A–B–C .. The line starts from point 'A' and passes through villages Majri and Deulwada and meets at Point 'C'.

C—D .. The line passes along the common boundary of villages Vijasan and Deulwada and meets at point 'D'.

D—E .. The line passes along the common boundary of Villages Deulwada and Chargaon, Kunad and Chargaon, and meets at Point 'E'.

E—F .. The line passes through village Kund and meets at point 'F'.

F—A .. The line passes along the outer boundary of villages Kunad, Deulwada, Majri and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/9/87-CA]

नई दिल्ली 24 जुलाई, 1987

का. आ. —2001 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास (अधिनियम ,1957 (1958 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 अप्रैल, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1674, तारीख 1 अप्रैल, 1985 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 25551.52 एकड़ (लगभग) या 10340.561 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार,, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 अप्रैल 1987 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

बहेराबांध ब्लाक

हासदेव क्षेत्र

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

क्र. सं.	ग्राम	पटवारी हलका सं.	समझौता सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5		6	7
1.	बहेराबांध	18	699	कोटमा	शहडोल	894.948	सम्पूर्ण
2.	कोरया	18	155	"	"	442.206	"
3.	माटाडाड	18	791	"	"	788.321	"
4.	डुंगरिया खुर्द	18	397	"	"	485.349	"
5.	भगता	18	769	"	"	361.346	भाग सम्पूर्ण
6.	जलसार	17	350	"	"	550.027	
7.	केवटार	17	163	"	"	600.538	'
8.	बबईटोला	17	467	"	'	382 111	'
9.	साजाटोला	17	973	"	"	666 052	"
10.	धानगांव	19	425	"	"	1471.304	"
11.	कुदरी	19	115	"	'	166.766	"
12.	बछौली	19	723	"	"	796 873	"
13.	बैनीबहरा	19	751	"	"	461.143	"
14.	बेलगांव	19	755	"	"	553 333	"
15.	लोहसरा	21	929	"	"	80.232	भाग सम्पूर्ण
16.	कनापाग	21	84	"	"	206.110	सपूर्ण
17.	सोभनाटोला	21	982	"	"	11.107	"
18.	डुंगरिया कला	21	398	"	"	625.937	"
19.	मैन टोना	21	847	"	"	484 529	
20.	मोहरी उर्फ मोहरी खुर्द	21	877	"	"	312 320-	भाग
				कुल क्षेत्र		10340 561	हैक्टर (लगभग)
				या		25551 52	एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन

क—ख रेखा, बिन्दु "क" से प्रारम्भ होती है और केवई नदी के पूर्वी तट के साथ साथ जाती है और कोरया और कोठी ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख—ग रेखा, कोरया, केवटार और बहेराबांध की ग्रामों की उत्तर सीमा के साथ साथ जाती है, तब साजाटोला ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग—घ	रेखा घबई टोला ग्राम की पूर्वी सीमा और जलसार, बलगांव और बछोली ग्रामों की उत्तरी पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
घ—ङ	रेखा बछोली और थानगांव की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।
ङ—च	रेखा; थानगांव ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है, तब मोहरी खुर्द और सिगुड़ी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और "बिन्दु" "च" पर मिलती है।
च—छ	रेखा, मोहरी खुर्द बिजुरी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और मोहरी खुर्द, लोहसरा और भगता ग्रामों से होकर जाती है, तब केनापारा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
छ—क	रेखा केनापारा, डुंगरिया कला और मैनटोला ग्रामों की दक्षिणी सीमा के साथ साथ जाती है, और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/1/85 सी ए]

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2001 :—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 1674 dated the 1st April, 1985 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 20th April, ,1985 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in land measuring 25551.52 acres (approximately), or 10340.561 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended thereto as also in the Schedule hereto annexed;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) 7 of the said Act has been given;

Now therefore in excercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act the Central Government hereby specified a further period of one year commencing from the 20th April, 1987 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said land or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

BAHERABANDH BLOCK

HASDEO AREA

DISTRICT SHADHOL (MADHYA PRADESH)

Serial Number	Village	Patwari Halka Number	Settlement number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baherabandh	18	699	Kotma	Shahdol	894.948	Full
2.	Koraya	18	155	Kotma	Shahdol	442.206	Full
3.	Bhatadand	18	791	Kotma	Shahdol	788.321	Full
4.	Dongaria Khurd	18	397	Kotma	Shahdol	485.349	Full
5.	Bhagta	18	769	Kotma	Shahdol	361.345	Part
6.	Jalsar	17	350	Kotma	Shahdol	550.027	Full
7.	Keotar	17	163	Kotma	Shahdol	500.538	Full
8.	Dhabaitola	17	467	Kotma	Shahdol	382.111	Full
9.	Sajatola	17	973	Kotma	Shahdol	666.062	Full
10.	Thangaon	19	425	Kotma	Shahdol	1471.304	Full
11.	Kudri	19	115	Kotma	Shahdol	166.766	Full
12.	Bachhauh	19	723	Kotma	Shahdol	796.873	Full
13.	Benibahara	19	751	Kotma	Shahdol	461.143	Full
14.	Belgaon	19	755	Kotma	Shahdol	553.333	Full

1		2			3	
15. Lohsara	21	929	Kotma	Shahdol	80.232	Part
16. Kenapara	21	84	Kotma	Shahdol	206.110	Full
17. Sobhnatola	21	982	Kotma	Shahdol	111.107	Full
18. Dongaria-Kala	21	398	Kotma	Shahdol	625.937	Full
19. Maintola	21	847	Kotma	Shahdol	484.529	Full
20. Mahuwari Alias Mahauwari Khurd	20	877	Kotma	Shahdol	312.320	Part

Total areas : 10340.561 hectares (approximately), or
25551.52 acres (approximately).

BOUNDARY DESCRIPTION :—

A—B Line starts from point 'A' and passes along the eastern bank of river Kewai and meets on the common boundary of villages Koraya and Kothi at Point 'B'.

B—C Line passes along the northern boundary of villages Korya, Keotar and Baherabandh, then proceeds along the north-western boundary of village Sajatola and meets at point 'C'.

C—D Line passes along the eastern boundary of village Dhabaitola and north-eastern boundary of villages Jalsar, Belgaon and Bachhauli and meets at points 'D'.

D—E Line passes along the eastern boundary of villages Bachhauli and Thangaon and meets at point 'E'.

E—F Line passes along the southern boundary of village Thangaon, then proceeds along the common boundary of villages Mahuwari Khurd and Sigudi and meets at point 'F'.

F—G Line passes along the common boundary of villages Mahuwari Khurd, Bijuri, proceeds through villages Mahuwar Khurd, Lohsara and Bhagra, then along the eastern boundary of village Kenapara and meets at point 'G'

G—A Line passes along the southern boundary villages Kenapara, Dongaria Kala and Maintola and meets at the starting point 'A'.

[No. 43015/1/85-CA]

का.आ. 2002.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसची में उल्लिखित भमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र में रेखांक का निरीक्षण साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (राजस्व अनुभाग) सीपत रोड, बिलासपुर-495001 के कार्यालय में या कलक्टर, सुदरगढ़ (उड़ीसा) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, 1–काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, सहायक संपदा प्रबंधक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., सीपत रोड, बिलासपुर, को भेजेंगे।

अनुसूची

गोपालपुर एक्सटेन्शन ब्लाक आई बी वैली

कोलफील्ड जिला सुन्दरगढ़, (उड़ीसा)

रेखांक सं. एस. ई. सी. एल./बीएसपी/
जी.एम. (परियोजना)/5
दिनांक 10 जनवरी, 1987
(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि)

क्र.सं.	मौजा ग्राम	बन्दोबस्त संख्यांक	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	टिकिलीपारा	15	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	1743.85	पूर्ण
2.	सियारमल	17	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	862.34	पूर्ण
3.	गोपालपुर	19	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	140.67	भाग
4.	तुमुलिया	75	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	2381.32	पूर्ण
5.	करलीकछर	76	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	511.94	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
6.	कुनकाडा	77	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	542 82	पूर्ण
7.	बंकीबहल	78	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	836.33	पूर्ण
8	बलिंगा	79	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	1234.64	पूर्ण
9.	गर्जनबहल	89	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	798.35	पूर्ण
10.	बंगरुकेला	90	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	1055 96	पूर्ण
11.	किरिपसिरा	91	हेमगिरी	सुन्दरगढ़	1681 11	पूर्ण
12.	जपतीजंगल				420 00	

कुल क्षेत्र 12209 33 एकड़ (लगभग)

या

4941.05 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन.

ट-ट1-ट-2-ट-3	रेखा "ट" बिन्दु के प्रारंभ से होती है, जो ग्राम झपुरुंगा, तुमुलिया, उपतीजंगल का एक त्रिसंगम बिन्दु है, और ग्राम तुमुलिया की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-3" पर मिलती है ।
ट-3-ट-4-ट-5	रेखा, ग्राम बंगरुकेला की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-5" पर मिलती है ।
ट-5,ट-6,ट-7-ट-8, ट-9, ट-10	रेखा भागतः ग्राम किरिपसिरा की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ भागतः दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-10" पर मिलती है ।
ट-10-ट-11-ट-12	रेखा गर्जनबहल और बलिंगा ग्रामों की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-12" पर मिलती है ।
ट 12 ट-13-ट-14, ट-15, ट-16	रेखा बलिंगा, बंकीबहल, टिकिलीपारा ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ट-16" पर मिलती है ।
ट-16-ग-ख	रेखा सरदेगा ग्राम की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।
ख-क-द-घ-ङ-ण	रेखा सरदेगा ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और नाले की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गोपालपुर ग्राम के बीच में से गुजरती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है ।
ण-ड-ड	रेखा गोपालपुर ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और नाले की दक्षिणी सीमा के साथ उसी ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।
ड-ठ-ट	रेखा सियारमल, तुमुलिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा के साथ जाती है और "ट" के प्रारम्भिक बिन्दु पर मिलती है ।

[सं. 43015/10/87-सी.ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

S O 2002:—WHEREAS it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The plan of the area covered by this notification can be inspected at the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495001 or at the office of the Collector, Sundargarh (Orissa) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street Calcutta. All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Assistant Estate Manager, South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, Bilaspur within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

GOPALPUR EXTENSION BLOCK

IB VALLEY COALFIELD

DISTRICT SUNDARGARH (ORISSA)

Plan No SECL/BSP GM (PROJ)/5

Dated 10th January, 1987

(showing land notified for prospecting)

Sl. No.	Name of village	Settlement Number	Tahsil
1.	Tikilipara	15	Hemgiri
2	Siarmal	17	Hemgiri
3.	Gopalpur	19	Hemgiri
4.	Tumulia	75	Hemgiri
5.	Karlikachhar	76	Hemgiri
6.	Kulada	77	Hemgiri
7.	Bankibahal	78	Hemgiri
8.	Balinga	79	Hemgiri
9.	Garjanbahal	89	Hemgiri
10.	Bangurukela	90	Hemgiri
11.	Kiripsira	91	Hemgiri
12.	Japtijangal	—	—

District	Area in acres	Remarks
Sundargarh	1743 85	Full
Sundargarh	862.34	Full
Sundargarh	140 67	Part
Sundargarh	2381.32	Full
Sundargarh	511.94	Full
Sundargarh	542.82	Full
Sundargarh	836.33	Full
Sundargarh	1234.64	Full
Sundargarh	798.35	Full
Sundargarh	1055.96	Full
Sundargarh	1681.11	Full
—	420 00	—

Total : 12209.33 acres (approximately), or 4941 05 hectares (approximately)

Boundary Description

K-K1-K2 K3.	Line starts from point 'K' which is a trijunction point of Villages Jhupurunga, Tumulia, Japtijangle and passes long the Southern boundary of Village Tumulia and meets at point "K3".
K3-K4-K5.	Line passes along southern boundary of Village Bangurukela and meets at point "K5".

K5-K6-K7 K8-K9-K10.	Line passes partly along the western boundary, partly along south eastern and northern boundary of Village Kiripsira and meets at point "K10".
K10-K11-K12.	Line passes along the eastern boundary of Villages Gaijanbahal and Balinga and meets at point "K12".
K12-K13-K14-K15-K16.	Line passes along the northern boundary of Villages Balinga, Bankibahal, Tikilipara and meets at point "K16".
K16-C-B	Line passes along the northern boundary of Village Sardega and meets at point "B".
B-A-R O-P-O.	Line passes along the western boundary of Village Sardega and proceeds through Village Gopalpur along the northern boundary of nallah and meets at point "O".
O-N-M-	Line passes along the western boundary of Village Gopalpur and proceeds through the same village along the southern boundary of nallah and meets at point "M".
M-L-K.	Line passes along the western boundary of Villages Siarmal, Tumulia and meets at the starting point "K".

[No. 43015/10/87—CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

का.आ. 2003—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में डा. के. गोविन्दन नायर, मंगलया, करमाना, त्रिवेंद्रम, को केरल राज्य दन्तचिकित्सकों के भाग "क" में रजिस्ट्रीकृत दन्त चिकित्सकों द्वारा 25 फरवरी, 1987 से डा. बालाकृष्णन नायर के स्थान पर भारतीय दन्त चिकित्सक परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 430 तारीख 24 जनवरी, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "धारा 3 के परन्तुक के साथ पठित खण्ड (क) के अन्तर्गत निर्वाचित" शीर्ष के अधीन क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"10. डा. के. गोविन्दन नायर	निर्वाचित केरल दन्तचिकित्सक परिषद्	25-2-82

[संख्या बी. 12013/1/87-पी.एम.एस.]

जी.जी.के. नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, 30th June, 1987

S.O. 2003 —Whereas in pursuance of clause (a) of section 3 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Dr. K. Govindan Nair, Mangalya, Karamana,Trivandrum has been elected to be a member of the Dental Council of India by the Dentists registered on Part 'A' of the Kerala State Dentists with effect from the 25th February, 1987, Vice Dr. K. Balakrishnan Nair;

Now, therefore, in pursuance of clause (a) of section 3 read with sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 430 dated the 24th January, 1984 namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (a) read with the proviso to section 3", for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"10. Dr. K. Govindan Nair Elected Kerala 25-2-1987".

Dental Council

[No.V. 12013/1/87-PMS]

G. G. K. NAIR, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

का.आ. 2004:—केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, दिनांक 13 मार्च, 1976 (का.आ. 1053) की अधिसूचना का भागत. उपांतर करते हुए और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य

अधिकारी होने के नाते, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह भी निदेश देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, (लेटर प्रैस यूनिट), मिन्टो रोड, नई दिल्ली	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली स्थित प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय (लेटर प्रैस यूनिट) मिन्टो रोड, नई दिल्ली, के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी स्थान, जिनमें भूमि और भवन भी सम्मिलित है ।

[फाइल सं. 70(2)/86-ए-5]

नत्थू सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, 7th July, 1987

S.O. 2004 :—In partial modification of notification dated the 28th February, 1976 (S.O. 1053) published in the Gazette of India, dated the 13th March, 1976 and in exercise of the powers coferred by section 3 of the Public Premises Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officers of the Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act and further directs that the said officer shall exerise the powers confered and perform the duties imposed, on Estate Officers, by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of the officer	Categories of publicfpremises and local limits of jurisdiction
1	2
Manager, Government of India Press (Letter-Press Unit), Minto Road, New Delhi.	Public premises including Land and Buildings under the administrative control of the Manager Government of India Press (Letter Press Unit), Minto Road, New Delhi, situated in the Union Territory of Delhi.

[F. No. 70 (2)/86—A 5]

NATTHU SINGH, Under Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 29 जुलाई, 1987

का. आ. 2005 :—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3, उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 582 तारीख 17-6-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत . केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

पूरकवाद सूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	चक नं	पुराना नं.	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरेया	औरेया	खजुहा	146	1/3 मि. 29/1 मि. 29/2 मि.	1-35
				150	28 मि.	0-02

1	2	3	4	5	6	7
				280	28 मि.	0-22
				222	27 मि.	0-59
					31 मि.	
					30 मि.	
				चकरोड	27 मि.	0-03
					39 मि.	
					32 मि.	0-03
				240	27 मि.	0-10
				307	27 मि.	0-37
					39 मि.	
					39 मि.	
				चकरोड	39 मि.	0-03
				326	39 मि.	0-56
					38 मि.	
				66	41/2 मि.	0-75
					42 मि.	
					43 मि.	
				बाग	41/2 मि.	0-15
				80	43 मि.	0-03
					44 मि.	
				213	44 मि.	0-01
				रास्ता	280 मि.	0-12
				217	240 मि.	0-15
					230 मि.	
				42	230 मि.	0-12
						4-63
इटावा	औरेया	औरेया	खजुहा	चकरोड	230 मि.	0-02
				28	230 मि.	10-00
				3	231 मि.	0-10
				चकरोड	230 मि.	0-02
					239 मि.	
				121	229 मि.	0-93
					228	
				286	223 मि.	1-05
					226/2 मि	
				चकरोड	225 मि.	0-02
					226/2 मि	
				नाली	225 मि.	0-02
					217 मि.	
				83	225 मि.	0-01
				245	217 मि.	0-85
					226/2 मि	
				रास्ता	216 मि.	0-07
				95	213 मि.	0-90
					210 मि.	
					211 मि.	
					212 मि.	
				चकरोड	178 मि.	0-03
				161	178 मि.	0-03
				283	178 मि.	
					177/2 मि	0:50
					179 मि.	

1	2	3	4	5	6	7
				179	177/1 मि. 177/2 मि. 176/1 मि.	1-27
				115	176/2 मि.	0-22
						6-74
				रास्ता	173/3 मि.	0-18
					172/2 मि.	0-37
				नाला	160	0-07
					37	11-99

[सं. O—14016/430/84-जी. पी.]

MINISTRY OF PETROLEUM AND N.G.

New Delhi, the 29th July, 1987

S.O. 2005.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 582 dated 17-6-87 under sub-section (i) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of the Section 6, of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Chak No.	Old No.	Area in Acre
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	146	1/3M 29/1M 29/2 M	1-35
				150	28M	0-02
				280	28M	0-22
				222	27M 31M 30M	0-59
				Chakrod	27M 39M	0-03
					32M	0-03
				240	27M	0-10
				307	27M 39M	0-37
				Chakrod	39M	0-03
				326	39M 38M	0-56
				66	41/2M 42M 43M	0-75

1	2	3	4	5	6	7
	Bagh				41/2M	0–15
				80	43M	
					44M	
				213	44M	0–01
				Rasta	280M	0–12
				217	240M	0–15
					230 M	
				42	230M	0–12
						4–63
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	Chakrod	230M	00–00
				28	230M	00–00
				3	231M	0–10
				Chakrod	230M	0–02
					231M	
				121	229M	0–93
					228M	
				286	223M	1–05
					226/2M	
				Chakrod	225M	0–02
					226M	
				Nali	225M	0–02
					217M	
				83	225M	0–01
				245	217M	0–55
					226M	
				Rasta	216 M	0–07
				95	213M	0–09
					210M	
					211M	
					212M	
				Chakrod	178M	0–03
				161	178M	0–03
				283	178M	
					177/2M	0–50
					179M	
				179	171/1M	1–27
					177/2M	
					176/1M	
				115	176/2M	0–22
						6–74
Etawah	Auraiya	Auraiya	Khajuha	Rasta	173/2M	0–18
					172/2 M	0–37
				Nali	160	0–07
					37	11–99

[No. O–14016/430/84 GP]

का. आ. सं. 2006.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 583 तारीख 17-6-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

पूरकवार सूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	चक नं.	पुराना नं.	क्षेत्रफल एकड़ में
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरेया	औरेया	पीपरपुर	—	4	0-08
				—	5	0-12
				—	6	0-06
				—	3	0-25
				—	28/2	0-58
				नाली	29/1	0-03
				19	29/2	1-10
					30	
					31/1	
					31/2	
					33 मि.	
				443	33 मि.	0-12
				चकरोड	33 मि.	0-02
				नाली	34 मि.	0-01
				—	1	0-30
				—	35	0-02
				217	34/1 मि.	0-27
					34/2 मि.	
					34/3 मि.	
				114	34/3 मि.	0-26
				83	34/3 मि.	0-01
				रास्ता	34/3 मि.	0-03
				387	40 मि.	0-25
					41 मि.	
				389	41 मि.	0-20
				चकरोड	41 मि.	0-01
				रास्ता	42 मि.	0-03
				—	24	0-02
				295	51/2/1 मि.	0-68
					51/1 मि.	
				284	51/1 मि.	0-12
				332	50/2	0-65
				नाली	93 मि.	0-03
				—	94	0-02
				290	93/1 मि.	1-08
				381	93/1 मि.	0-75
					93/3 मि.	
					624/93	
				नाली	93/2 मि.	0-02
				22	84 मि.	0-15
					624/93	
				71	84 मि.	0-15
					624/3 मि.	
				नाली	84 मि.	0-02
				—	83/1	0-02

1	2	3	4	5	6	7
				—	83/2	0-20
				—	81	0-18
				—	85/1	0-20
				—	85/2	0-06
				रास्ता	73	0-10
				11	187 मि	0-60
				108	187 मि.	0-15
				43	187 मि	0-22
					186 मि	
				220	186 मि.	0-02
				चकरोड	187 मि.	0-10
					189/1 मि.	
					188 मि.	
				417	187 मि.	0-15
					188 मि.	
					189/1 मि.	
				चकरोड	189/1	0-02
				253	189/1 मि.	0-75
					189/2 मि.	
					189/3 मि.	
					196/1 मि.	
					196/2 मि.	
					196/3 मि.	
				385	196/1 मि.	0-56
					196/2 मि.	
					196/3 मि.	
				रास्ता	197मि.	0-04
				—	198/1 मि.	0-09
				173	236 मि.	0-55
				नाली	236 मि	0-02
				127	236 मि.	0-05
				रास्ता	235 मि.	0-03
				278	235 मि	0-25
				231	235 मि.	0-10
				240	235 मि.	0-10
				चकरोड	235 मि.	0-15
				88	237 मि.	0-04
					235 मि.	
				258	235 मि.	0-10
					237 मि.	
				364	237 मि.	1-80
					235 मि.	
				—	267	0-04
				—	266	0-12
				—	268/1	0-06
				—	268/2	1-30
				—	269	0-12
				—	271	0-55
				—	272	0-50
				—	157	0-04
				स. यो. 68		16-92

नोट.—स्तम्भ 5 में /-1 चिन्ह दर्शाये गये है वह चकबाहर समझा जाये ।

[सं. O-14016/437/84-जी. पी.

S.O. 2006.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G., S.O. 583 dated 17-6-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Chak No.	Old No.	Area in acre
1	2	3	4	5	6	7
Etwah	Auraiya	Auraiya	Piparpur	—	4	0–08
				—	5	0–12
				—	6	0–06
				—	3	0–25
				—	28/2	0–58
				Nali	29/1	0–03
				19	29/2	1–10
					30	
					31/1	
					31/2	
					33 M	
				443	33 M	0–12
				Chakrod	33 M	0–02
				Nali	34 M	0–02
				—	1	0–30
				—	35	0–02
				217	34/1 M	0–27
					34/2 M	
					34/3 M	
				114	34/3 M	0–26
				83	34/3 M	0–01
				Rasta	34/3 M	0–03
				387	40 M	0–25
					41 M	
				389	41 M	0–28
				Chakrod	41 M	0–01
				Rasta	42 M	0–03
				—	24	0–02
				295	51/2/1 M	0–68
					51/1 M	
				284	51/1 M	0–12
				332	50/2 M	0–65
				Nali	93 M	0–03
				—	94	0–02
				290	93/1 M	1–08
				381	93/1 M	0–75
					93/3 M	
					624/93	
				Nali	93/2 M	0–02
				22	84 M	0–15
					624/93	

1	2	3	4	5	6	7
Etwah	Auraiya	Auraiya	Piparpur (Contd.)	71	84 M 624/3 M	0–15
				Nali	84 M	0–02
				—	83/1	0–02
				—	83/2	0–20
				—	81	0–18
				—	85/1	0–20
				—	85/2	0–06
				Rasta	73	0–10
				11	187 M	0–60
				108	187 M	0–15
				43	187 M 186 M	0–22
				220	186 M	0–02
				Chakrod	187 M 189/1 M 188 M	0–10
				417	187 M 188 M 189/1 M	0–15
				Chakrod	189/1	0–02
				253	189/1 M 189/2 M 189/3 M 196/1M 196/2M 196/3M	0–75
				385	196/1 M 196/2M 196/3 M	0–56
				Rasta	197 M	0–04
				—	198/1 M	0–00
				173	236 M	0–55
				Nali	236 M	0–02
				127	236 M	0–05
				Rasta	235 M	0–03
				278	235 M	0–25
				231	235 M	0–18
				240	235 M	0–10
				Chakrod	235 M	0–15
				88	237 M 235 M	0–04
				258	235 M 237 M	0–10
				364	237 M 235 M	1–80
				—	267	0–04
				—	266	0–12
				—	268/1	0–06
				—	268/2	1–30
				—	269 271	0–12 0–55
				—	272	0–50
				—	157	0–04
				68		16–92

[No.O-14016/437/84-G.P.]

का.आ. 2007.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 684 तारीख 17-6-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	चक सं.	प्लाट सं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	लहोखर	—	15 मि.	0-40
				—	16 मि.	0-95
				—	60 मि.	0-08
				चकरोड़	16 मि.	0-02
				127	16 मि.	0-10
				चकरोड़	59 मि.	0-02
				199	59 मि.	0-45
					55 मि.	
				292	55 मि.	0-30
				20	55 मि.	0-40
					56 मि.	
				चकरोड़	55 मि.	0-02
					56 मि.	
				49	55 मि.	0-02
					54 मि.	
				217	53 मि.	0-20
					54 मि.	
					56 मि.	
				181	53 मि.	0-35
					56 मि.	
				—	52/1	0-07
				—	52/2/1	0-43
				33	26 मि.	0-20
					52/2/2 मि.	
				352	49/2 मि.	0-15
				रास्ता	40 मि.	0-01
				नाली	39 मि.	0-25
				160	38/2 मि.	0-22
				16	38/2 मि.	0-20
				106	30/2 मि.	0-53
				—	29 मि.	0-42
				चकरोड़	33 मि.	0-08
					30 मि.	
				54	33 मि.	0-03
				318	30 मि.	0-17
				नाली	243	0-03
				ऊसर	179/2	0-07
				नाली	174 मि.	0-01

1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	लहोखर	249	174/मि.	0-50
					175 मि.	
					173 मि.	
				246	173 मि.	0-07
				ऊसर	193 मि.	0-08
				ऊसर	194 मि.	0-10
				—	196 मि.	0-68
				नाली	199 मि.	0-02
				•8	199 मि.	0-40
				ऊसर	201 मि.	0-53
				सड़क	295 मि.	0-12
				ऊसर	315/1/1	0-50
				—	315/1/2	0-03
				369	316	0-01
				नाली	317	0-03
				बंजर	320/6/1/6	0-12
				नाली	320/6/1	0-03
				—	320/6/2	0-13
				—	320/1/1	0-30
				—	320/3/1	0-25
				384	320/4/1	0-27
					320/4/2	
				390	320/2	0-30
				नाली	320/6/5	0-03
				नहर	312 मि.	0-12
				नाली	311/4/4	0-03
				—	311/4/1	0-05
				—	311/5/1	0-22
				—	311/6/1	0-33
				—	311/7/1	0-33
				—	311/8	0-33
				—	311/9	0-03
				60		18-84

नोट:-स्तम्भ 5 मे दर्शाए गए "ऊसर या डेम"को चक बाहर समझा जाए।

[सं. O-14016/321/84-जी.पी.]

S.O. 2007.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and N.G. S.O. 584 dated 17-6-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government ,hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Chak No.	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lahokhar	—	15 M	0-40
					16 M	0-95
				—	60 M	0-08
				Chakrod	16 M	0-02

1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lahokhar	127	16 M	0–10
				Chakrod	59 M	0–02
				199	59 M	0–45
					55 M	
				292	55 M	0–30
				70	55 M	0–40
					56 M	
				Chakrod	55 M	0–02
					56 M	
				49	55 M	00–02
					54 M	
				217	53 M	0–20
					54 M	
					56 M	
				181	53 M	0–35
					56 M	
				–	52/1	0–07
				—	52/2/1	0–43
				33	26 M	0–20
					52/2/2	
				352	49/2	0–15
				Rasta	40 M	0–01
				Nali	39 M	0–25
				160	38/2 M	0–22
				16	38/2 M	0–20
				106	38/2 M	0–53
				—	29 M	0–42
				Chakrod	33 M	0–08
					30 M	
				54	33 M	0–03
				318	30 M	0–17
				Nali	243	0–03
				Usher	179/2	0–07
				Nali	174	0–01
				249	174 M	0–50
					175 M	
					173 M	
				246	173 M	0–07
				Ushar	193 M	0–08
				Ushar	194 M	0–10
				—	196 M	0–68
				Nali	199 M	0–02
				8	199 M	0–40
				Ushar	201 M	0–53
				Road	295 M	0–12
				Ushar	315/1/1	0–50
				—	315/1/2	0–03
				369	316	0–01
				Nali	317	0–03
				Banjar	320/6/1/6	0–12
				Nali	320/6/1	0–03
				—	320/6/2	0–13
				—	320/1/1	0–30
				—	320/3/1	0–25

1	2	3	4	5	6	7
				384	320/4/1 329/4/2	0-27
				390	320/2	0–30
				Nali	320/6/5	0–03
				Nahar	212 M	0–12
				Nali	311/1/4	0–03
				—	311/4/1	0–05
				—	311/1/1	0-22
				—	311/5/1	0–33
				—	3.1/1/1	0–33
				—	311/8	0–33
				—	311/9	0-01
				60		18–84

Note : —It is understood that "Ushar and Dish" shown under Col. 5 out of Chak

[No. O-14016/321/84-GP]

का. आ. 2008—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधूना	बिधूना	कैथाना	169	0–08	
				296	0–03	
				1130	0–04	
				1129	0–07	
				1051	0–08	
				298	0–10	
				6	0–40	

[सं.O-14016/03/84-जी पी

S.O. 2008.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interett that for the transport of Petroleum from H. B. J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of use therein ;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd., H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow 226019 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementry Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Keaiwa	169	0–08
				296	0–03
				1130	0–04
				1129	0-07
				1051	0–08
				298	0–10
				6	0–40

[No. O-14016/03/84-GP]

का. आ. 2009.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ 226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	कौजरी	508	0–10	
				1098	0–03	
				2	0–13	

[सं. O–14016/647/84-जी पी]

S.O. 2009.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Kainjri	508	0-10
				1098	0-03
				2	0-13

[No. O. 14016/647/87-G.P.

का. आ 2010.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ 226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	लखनो	870	0-23	

[सं O-14016/02/85—जी पी]

S.O. 2010.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Lakhno	870	0-23

[No.-O-14016/02/85-G.P.]

का. आ. 2011—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ 226019 यू पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	नौली	50	0–20	
				1	0–20	

[स O-14016/429/84-जी.पी]

S.O 2011.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B. J Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Nauli	50	0–20
				1	0–20

[No O. 14016/429/84-G.P.]

का आ 2012 --यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

जिला	तहसील	परगना	मौजा	प्लाट सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	लखनापुर	140	1 मि. 6 मि.	0-29
				431	1 मि 2 मि. 4 मि. 5 मि.	0-36
				68	2 म. 3 मि. 4 मि.	0-20
				89	3 मि. 4 मि. 12 मि. 13 मि.	0-44
				132	12 मि. 13 मि. 14 मि., 15 मि.]	0-22
				204	14 मि 15 मि. 16 मि. 17 मि. 18 मि.'	0-35
				105	18 मि 19 मि.	0-11

1—97

[सं O-14016/322/84-जी.पी.]

S.O. 2012.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Supplementary Case (Schedule)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Lakhnapur	140 1 M 6 M	0-29
				431 1 M 2 M 4 M 5 M	0-36
				68 2 M 3 M 4 M	0-20

1	2	3	4	5	6	7
				89	3 M 4 M 12M 13 M	0-44
				122	12 M 13 M 14 M 15 M	0-22
				204	14 M 15 M 16 M 17 M 18 M	0-35
				105	18 M 19 M	0-11
				7		1-97

[No. O-14016/322/84-G.P.]

का. आ. 2013—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
इटावा	बिधूना	बिधूना	जगन्नाथपुर	182	0-03	

[सं. ओ-14016/392/84-जी.पी]

S.O. 2013.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)
H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6 7
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Bhagwantpur	182	0-03

[No. O-14016/392/84/G.P.]

का. आ. 2014—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच बी जे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधूना	बिधूना	नवादा बाद	53	0-22	
				49/4	0-29	
				44/1	0-05	
				44/2	0-02	
				44/3	0-02	
				41/1	0-10	
				41/2	0-08	
				81/1	0-05	
				39	0-34	
				83	0-14	
				426/2	0-19	
				462/3	0-07	
				186	0-17	
				47	0-04	
				42	0-06	
				54	0-05	
				187	0-07	
				188	0-03	
				423	0-02	
				511/2	0-07	
				511/3	0-05	
				85/1	0-05	
				304/2	0-17	
				23	2-31	

[सं. ओ-14016/389/84-जी पी.]

S.O. 2014.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land by the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building 22, Station Road. Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Nawada Dado	53	0–22
				49/4	0–29
				44/1	0–05
				44/2	0–02
				44/3	0–02
				41/1	0–10
				41/2	0–08
				81/1	0–05
				39	0–34
				83	0–14
				426/2	0–13
				462/3	0–07
				186	0–17
				47	0–04
				42	0–06
				54	0–05
				187	0–07
				188	0–05
				423	0–02
				511/2	0–07
				511/3	0–05
				85/1	0–05
				504/2	0–17
				23	2–31

[No. O-14016/389/84-G.P.

का.आ. 2015.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
3	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	अलीपुर	342	0–10
				344	0–06
				346	0–10
				352	0–08
				4	0–34

[सं. ओ-14016/398/84-जी.पी.]

S.O. 2015.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H.B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Alipur	342	0–10
				344	0–06
				345	0–10
				352	0–08
				4	0–34

[No. 14016/398/84-G.P.]

का. आ. 2016.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी जे तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	बहादुरपुर सहार		
				52	0–09
				54	0–05
				58	0–10
				71	0–10
				92	0–06
				97	0–02
				98	0–02
				7	0–44

[स. ओ-14016/399/84-जी.पी.]

S.O. 2016.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H B to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Bahadur Pur Sahar	52	0–09
				54	0–05
				58	0–10
				71	0–10
				92	0–06
				97	0–02
				98	0–02
				7	0–44

[No. O-14016/399/84-G.P.]

का. आ. 2017—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	चांदा	13	0-04
				15	0-11
				14	0-03
				8	0-09
				5	0-04
				5	0-31

[सं. ओ-14016/393/84-जी.पी.]

S.O. 2017.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6 7
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Chando.	13	0-04
				15	0-11
				14	0-03
				8	0-09
				5	0-04
				5	0-31

[No. O-14016/393/84-G.P.]

का.आ. 2018.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच बी ज तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि., विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
इटावा	बिधूना	बिधूना	उसरहा	622	0-15
				720	0-36
				722	0-07
				590	0-10
				614	0-18
				591	0-14
				587	0-12
				800	0-03
				799	0-01
				798	0-02
				725	0-22
				726	0-03
				721	0-05
				881	0-03
				14	1 61

[सं. ओ-14016/390/84-जी.पी.]

S.O. 2013.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H B to J in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H B J Pipline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Usraha	622	0–15
				720	0–36
				722	0–07
				590	0–10
				614	0–18
				591	0–14
				587	0–12
				800	0–03
				799	0–01
				798	0–02
				725	0–22
				726	0–03
				721	0–05
				881	0–03
				14	1–51

[No. O-14016/390/84-G.P.]

का.आ.सं.—2019 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत।

अनुपूरक भाव अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधूना	बिधूना	धरमंगदपुर	428	0-32	
				438	0-03	
				461	0-05	
				1150	0-03	
				1151	0-08	
				1198	0-22	
				1199	0-30	
				1199	0-10	
				1260/6	0-09	
				434	0-15	
				447	0-12	
				1148	0-03	
				1208	0-03	
				13	1-55	

[सं० ओ-14016/01/85-जी.पी.]

S.O. 2019.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22 Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLIMENTARY CASE (SCHDULE)

I.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Dharmangad -Pur	428	0-32	
				438	0-03	
				461	0-05	
				1150	0-03	
				1151	0-08	
				1198	0-22	

1	2	3	4	5	6	7
				1199	0-30	
				1199	0-10	
				1260/6	0-09	
				434	0-15	
				447	0-12	
				1148	0-03	
				1208	0-03	
				15	1-55	

[No. O-14016/01/85-G.P.]

का.आ.सं. 2020—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 4 5 4

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज-पाईपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें प्रयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप, बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईपलाईन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधूना	बिधूना	मझोखमील	710	0-07	
				719	0-01	
				776	0-35	
				774/9	0-05	
				774/7	0-01	
				774/8	0-02	
				767/5	0-31	
				768	0-08	
				764	0-03	
				765	0-02	
				715	0-04	
				755	0-03	
				12	1-02	

[सं० ओ-14016/396/84-जी.पी.1]

S.O. 2020.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to T. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Marokh meet	710	0-07
				719	0-01
				776	0-35
				774/9	0-05
				774/7	0-01
				774/8	0-02
				767/5	0-31
				768	0-08
				764	0-03
				765	0-02
				715	0-04
				755	0-03
				12	1-02

[No. O-14016/396/84-G.P.]

का.आ. 2021—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनो को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनसची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि म उपयाग आधकार का अजन) आधानयम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019, यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

एच.बी.जे. गैस पाईपलाईन प्रोजेक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	बिधुना	बिधुना	हरवंशपुर	452	0-22	
				437	0-17	
				70	0-04	
				50	0-13	
				43	0-07	

1	2	3	4	5	6	7
				35	0-10	
				24	0-27	
				439	0-05	
				94	0-08	
				9	1-13	

[सं. ओ-14016/394/84-जी.पी.]

S.O. 2021.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B to J in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

SUPPLEMENTRY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Bidhuna	Bidhuna	Harbanshpur	452	0-22
				437	0-17
				70	0-04
				50	0-13
				43	0-07
				35	0-10
				24	0-27
				439	0-05
				94	0-08
				9	1 13

[No O-14016/394/84-G.P.]

का आ स 2022—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित म यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदश म एच बी जे तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि म उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि म उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि म हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि विकासदीप बिल्डिंग, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ-226019, यू पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम ।

अनुपूरक वाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईप लाईन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	सेहूद	72	0-08	
				251	0-60	
				252	0-75	
				219	0-01	
				227	0-01	
				225	0-05	
				205	0-04	
				172	0-05	
				122	0-27	
				119	0-14	
				165	0-20	
				176	0-18	
				228	0-06	
				73	0-06	
				74	0-16	
				15	2-66	

[सं. ओ-14016/327/84-जी.पी]

S.O. 2022.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H B. to I. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22. Station Road, Lucknow-226019 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.P.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Sehud	72	0-08
				251	0-60
				252	0-75
				219	0-01
				227	0-01
				225	0-05
				205	0-04
				172	0-05
				122	0-27
				119	0-14
				165	0-20
				176	0-18
				228	0-06
				73	0-06
				74	0-16
				15	2-66

[No. O.-14016/327/84-G.P.]

का.आ. 2023.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एच.बी.जे. तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. विकासदीप, बिल्डिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत ।

अनुपूरक बाद अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाईपलाईन प्रोजैक्ट

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
इटावा	औरैया	औरैया	दौलतपुर	728	0–02	
				727	0–02	
				703	0–18	
				702	0–23	
				701	0–38	
				700	0–58	
				695	0–05	
				651	0–05	
				1056	0–06	
				1057	0–12	
				1035	0–05	
				1074	0–01	
				210	0–09	
				217	0–10	
				215	0–16	
				735	0–06	
				729	0–14	
				718	0–18	
				667	0–10	
				624	0–04	
				623	0–16	
				621	0–07	
				1012	0–10	
				1027	0–18	
				1028	0–16	
				1038	0–11	
				1055	0–04	
				1031	0–04	
				1037	0–06	
				1069	0–05	
				1073	0–09	
				1111	0–07	
				32	3–75	

[सं. ओ-14016/330/84-जी.पी.]

S.O. 2023.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to J. in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B. J. Pipeline Project, Vikas Deep Building, 22, Station Road, Lucknow-226019 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Daulatpur	728	0-02
				727	0-02
				703	0-18
				702	0-23
				701	0-38
				700	0-58
				695	0-05
				651	0-05
				1056	0-06
				1057	0-12
				1035	0-05
				1074	0-01
				210	0-09
				217	0-10
				215	0-16
				735	0-06
				729	0-14
				718	0-18
				667	0-10
				624	0-04
				623	0-16
				621	0-07
				1012	0-10
				1027	0-18
				1028	0-16
				1038	0-11
				1055	0-04
				1031	0-04
				1037	0-06
				1069	0-05
				1073	0-09
				1111	0-07
				32	3-75

[No. G. 14016/330/84-G.P.]

का॰ आ॰ 2024.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ एच॰ बी॰ जे॰ परियोजना लखनऊ 226021 यू॰ पी॰ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक संशोधित प्रस्ताव

एच॰ बी॰ जे॰ गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं॰	क्षेत्रफल	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	फतेहपुर रोशनाई	848	2–0–5	
				852	0–1–0	
				878	0–18–0	
				880	2–1–0	
				881	0–15–0	
				887	0–3–10	
				964	0–4–0	
				965	0–5–15	
				886	0–1–5	
				889	0–1–0	
				888	0–2–0	
				890	0–1–0	
				891	0–2–0	
				892	0–1–0	
				893	0–2–5	
				898	0–1–0	
				899	0–1–0	
				900	0–2–0	
				905	0–0–1	
				906	0–1–15	
				907	0–1–15	
				911	1–3–0	
				908	0–5–0	
				913	0–1–10	
				914	0–0–10	
				915	1–13–0	
				919	0–16–05	
				918	0–0–5	
				922	0–0–10	
				923	0–0–10	
				912	0–0–2	
				933	0–0–3	
				927	1–12–5	
				928	0–6–0	
				929	0–6–10	
				822	0–3–10	
				818	0–8–0	
				862	0–9–0	
				861	0–9–0	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
कानपुर देहात	मकबरपुर	मकबरपुर	फतेहपुर रोशमाई	817		1-6-0	
				816		0-2-10	
				813		2-1-0	
				814		0-2-0	
				684		0-1-0	
				729		0-3-0	
				690		0-7-10	
				689		0-6-10	
				686		0-9-10	
				687		0-12-0	
				686		0-2-10	
				685		0-0-3	
				695		0-0-2	
				692		0-1-0	
				694		1-4-10	
				682		0-0-15	
				681		0-0-15	
				557		0-0-15	
				558		1-5-0	
				552		0-3-0	
				556		0-2-10	
				559		1-10-0	
				560		0-17-10	
				561		0-0-5	
				551		0-1-0	
				550		0-19-0	
				485		0-9-10	
				567		0-0-10	
				566		0-0-10	
				578		1-14-10	
				577		0-0-5	
				575		0-6-0	
				576		1-3-0	
				571		1-14-0	
				572		1-2-0	
				416		0-5-0	
				418		0-0-5	
				417		0-5-0	
				419		0-4-0	
				404		1-4-0	
				48		1-1-5	
				47		0-14-10	
				49		0-1-0	
				46		0-1-0	
				50		0-8-0	
				44		2-0-15	
				45		0-8-0	
				333		0-2-10	
				334		0-4-02	
				335		0-2-10	
				342		0-13-0	
				343		0-0-10	
				344		0-10-0	
				341		0-2-10	
				340		0-0-15	
				345		0-1-0	
				346		0-0-5	

[सं० O-14016/320/84जी पी)]

S.O. 2024.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B J Pipeline Project, Lucknow-226021 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Bigha
1	2	3	4	5	6
Kanpur Dehat	Akbarpur	Akbarpur	Fatehpur Roshnai	848	2-0-5
				852	0-1-0
				878	0-18-0
				880	2-1-0
				881	0-15-0
				887	0-3-10
				964	0-4-0
				965	0-5-15
				886	0-1-5
				889	0-1-0
				888	0-2-0
				890	0-1-0
				891	0-2-0
				892	0-1-0
				893	0-2-5
				898	0-1-0
				899	0-1-0
				900	0-2-0
				905	0-0-1
				906	0-1-15
				907	0-1-15
				911	1-3-0
				908	0-5-0
				913	0-0-10
				914	0-0-10
				915	1-13-0
				919	0-16-05
				918	0-0-5
				922	0-0-10
				923	0-0-10
				912	0-0-2
				933	0-0-3
				927	1-12-5
				928	0-6-0
				929	0-6-10
				822	0-3-10
				818	0-8-0
				862	0-9-0
				861	0-9-0
				817	1-6-0
				816	0-2-10
				815	2-1-0

1	2	3	4	5	6
Kanpur Dehat	Akbar Pur	Akbar Pur	Fatehpur	814	0-2-0
			Roshnai	684	0-1-0
				729	0-3-0
				690	0-3-10
				689	0-6-10
				688	0-9-10
				687	0-12-0
				686	0-2-10
				685	0-0-3
				695	0-0-2
				692	0-1-0
				694	1-4-10
				682	0-0-15
				681	0-0-15
				557	0-0-15
				558	1-5-0
				552	0-3-0
				556	0-2-10
				559	1-10-0
				560	0-17-10
				561	0-0-5
				551	0-1-0
				550	0-19-0
				485	0-9-10
				567	0-0-10
				566	0-0-10
				578	1-14-10
				577	0-0-5
				575	0-6-0
				576	1-3-0
				571	1-14-0
				572	1-2-0
				416	0-5-0
				418	0-0-5
				417	0-5-0
				419	0-4-0
				404	1-4-0
				48	1-1-5
				47	0-14-10
				49	0-1-0
				46	0-1-0
				50	0-8-0
				44	2-0-15
				45	0-8-0
				333	0-2-10
				334	0-4-0
				335	0-2-10
				342	0-13-0
				343	0-0-10
				344	0-10-0
				341	0-2-10
				340	0-0-15
				345	0-1-0
				346	0-0-5

[No O. 14016/320/84-G P.]

का. आ. 2025.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. च बी. जे. परियोजना लखनऊ 2260020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुपूरक (संशोधित) प्रस्ताव

एच० बी० जे० गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
लपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	विनायकपुर	1549	0—0—10	
				1548	0—1—0	
				1762	0—2—0	
				1758	0—7—00	
				1517	0—1—0	
				1516	0—16—0	
				1515	0—7—0	
				1514	0—13—0	
				1512	0—12—5	
				1513	0—2—10	
				1510	0—12—0	
				1509	0—12—0	
				1503	0—0—15	
				1508	0—0—1	
				1765	0—0—2	
				1506	1—1—0	
				1504	0—2—0	
				1507	1—17—0	
				2109	0—2—10	
				2108	1—13—5	
				2111	0—1—0	
				2114	2—5—0	
				2107	0—7—0	
				2115	0—2—10	
				2116	0—16—4	
				2119	0—17—11	
				2118	0—10—15	
				2120	0—9—10	
				2121	0—3—15	
				2140	0—11—15	
				2123	0—16—5	
				2124	0—17—5,	
				2095	0—4—5	
				2125	0—1—10	
				2094	0—18—15	
				2089	0—12—0	
				2090	0—12—5	
				2085	0—17—10	

1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	विनायकपुर	2086	0-13-10	
				2081	0-2-0	
				2080	0-17-3	
				2078	0-4-5	
				2079	0-14-0	
				2266	0-13-10	
				2269	0-8-12	
				2270	0-2-15	
				1615	0-0-10	
				1552	1-8-0	
				1553	0-6-0	
				1554	0-8-0	
				1555	0-5-0	
				1610	0-2-0	
				1609	0-1-10	
				1607	0-17-0	
				1606	0-4-10	
				1602	0-1-10	
				1603	0-6-10	
				1551	0-3-0	
				1604	1-3-0	
				1573	0-6-10	
				1574	0-9-0	
				1590	0-1-0	
				1578	0-13-10	
				1579	0-4-10	
				1580	0-2-10	
				1581	1-1-0	
				1582	0-5-0	
				1269	1-8-0	
				1186	1-7-0	
				1228	0-1-10	
				1187	1-10-10	
				1188	0-1-0	
				1225	0-12-0	
				1224	0-18-0	
				1215	0-11-0	
				1222	0-19-0	
				1223	0-17-0	
				1221	0-3-0	
				1220	0-5-0	
				1219	0-6-10	
				1217	0-18-0	
				1601	0-2-0	
				1572	0-1-0	

[स O-14016/349/84-जी -पी.]

S.O. 2025.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from H. B. to I in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H. B. J. Pipeline Project, Lucknow-226001 U P .
Station Road, Lucknow-226019 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SUPPLEMENTARY CASE (SCHEDULE)

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acrs	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar Pur	Akbar Pur	Visayak Pur	1549	0-0-10	
				1548	0-1-0	
				1762	0-2-0	
				1758	0-7-0	
				1517	0-1-0	
				1516	0-16-0	
				1515	0-7-0	
				1514	0-13-0	
				1512	0-12-5	
				1513	0-2-10	
				1510	0-12-0	
				1509	0-12-0	
				1503	0-0-15	
				1508	0-0-1	
				1765	0-0-2	
				1506	1-1-0	
				1504	0-2-10	
				1507	1-17-0	
				2109	0-2-10	
				2108	1-13-5	
				2111	0-1-0	
				2114	2-5-0	
				2107	0-7-0	
				2115	0-2-10	
				2216	0-16-4	
				2119	0-17-11	
				2118	0-10-15	
				2120	0-9-10	
				2121	0-3-15	
				2140	0-11-15	
				2123	0-16-5	
				2124	0-17-5	
				2095	0-4-5	
				2125	0-1-10	
				2094	0-18-15	
				2089	0-12-0	
				2090	0-12-5	
				2085	0-17-10	
				2086	0-13-10	
				2081	0-2-0	
				2080	0-17-3	
				2078	0-4-5	
				2079	0-14-0	
				2266	0-13-10	
				2269	0-8-12	
				2270	0-2-15	
				1615	0-0-10	
				1552	1-8-0	
				1553	0-6-0	

1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar Pur	Akbar Pur	Visayak Pur	1554	0-8-0	
				1555	0-5-0	
				1610	0-2-0	
				1609	0-1-10	
				1607	0-17-0	
				1606	0-4-10	
				1602	0-1-10	
				1603	0-6-10	
				1551	0-3-0	
				1604	1-3-0	
				1573	0-6-10	
				1574	0-9-0	
				1590	0-1-0	
				1578	0-13-10	
				1579	0-4-10	
				1580	0-2-10	
				1581	1-1-0	
				1582	0-5-0	
				1269	1-8-0	
				1186	1-7-0	
				1228	0-1-10	
				1187	1-10-10	
				1188	0-1-0	
				1225	0-12-0	
				1224	0-18-0	
				1215	0-11-0	
				1222	0-19-0	
				1223	0-17-0	
				1221	0-3-0	
				1220	0-5-0	
				1219	0-6-10	
				1217	0-18-0	
				1601	0-2-0	
				1572	0-1-0	

[No. O. 14016/349/84-G.P.]

का० आ० 2026:—यतः, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ 227E तारीख 21-3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम छावनी	तेहसील गुना	जिला गुना	राज्य : मध्यप्रदेश
अनु०क्र०		खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हे०में)
1		2	3
1.		985	0.56.
2.		986	0.29
3		1000	0.63
4		1002	0.77
5.		1003	0.13

	2	4
	982	0 184
	980	0 653
	981	0 562
	926	0 281
	777	0.054
	778	0.032
	779	0 022
	780	0 556
	781	0.065
	889	0.038
	891	0.011
	888/1/3	0.205
	888/2	0.356
	888/1/2	0. 605
	993	0.086
	888/3/1	0.140
	896	0.367
	899/1 क	0.588
	979	0.108
	893	0.022
कुल योग		7.339

[सं० O. 14016/599/87जी० पी०)]

.O. 2026.—Whereas by notification of the Government of ia in the Ministry of Petroleum & N.G. S.O. 227E date 3-87 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in id) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government decd its intention to acquire the right of user in the lands cified in the schedule appended to that notification for pose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section of Section 6 of the said Act, submitted report to the vernment.

And further where the Central Government has, after sidering the said report, decided to acquire the right of r in the lands specified in the schedule appended to this ification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by subtion (1) of the section 6 of the said Act, the Central vernment hereby declares that the right of user in the d lands specified in the schedule appended to this notiition hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by subtion (4) of that section, the Central Government directs it the right of user in the said lands shall instead of vesin Central Government on this date of the publication of s declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

H.B.J. GAS PIPELINE PROJECT

Village : Chhavni Distt. : Guna Tehsil : Guna M.P.

SCHEDULE

S.No	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	985	0 562
2.	986	0 297
3.	1000	0 637
4	1002	0 778
5	1003	0 130
6	982	0.184
7.	980	0.653
8.	981	0 562
9.	926	0 281
10.	777	0 054
11.	778	0.032
12.	779	0.022
3.	780	0 556
4.	781	0 065
5.	889	0 038
6	891	0 011
7	888/1/3	0 205
8.	888/2	0 356
9.	888/1/2	0.605
20.	993	0.086
21.	888/3/1	0.140
22.	896	0.367
23.	899/1K	0.588
24.	979	0.108
25.	893	0.022
	TOTAL	7.339

[No. O-14016/599/87/G.P.]

का० आ० 2027—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 228 ई तारीख 21-3-1987 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : मुहालपुर तहसील : गुना जिला : गुना राज्य : मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनु क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हे)
1	2	3
1-	12/1	0.03
2-	12/3	0.605
3-	10/2	0.162
कुल योग		0.799

[सं ओ -14016/600/87-जी पी]

S.O. 2027.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 228E date 21-3-87 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Muhalpur Tehsil : Guna Distt. : Guna M.P.

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	12/1	0.032
2.	12/3	0.605
3.	10/2	0.162
	TOTAL	0.799

[No. O-14016/600/87—G.P.]

का. आ. 2028.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ सं 229 ई तारीख 21-3-1987 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित कर का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच बी जे गैस पाइन लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : सिमरासा तहसील : गुना जिला : गुना राज्य : मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनु क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हे० में)
1	2	3
1.	363	0.043
2.	364	0.085
3.	365/1	0.994
4.	359	0.756
5.	358	0.410
6.	357	0.356
7.	356/2	0.216
8.	355	0.637
9	381/2	0.302
10.	381/4	0.248
11	384	0.405
12	392	0.659
13	421/1	0 016
14.	421/3	0.016
15.	404/1	0.400
16.	404/2	0.130
17.	403/2-3	0.567
18.	232	0.270
19.	383	0.011
20.	352	0.022
21.	398/1	0.248
22.	398/2	0.292
कुल योग		7.063

[सं. ओ. 14016/601/87-जी पी]

राकेश कुमार, उप सचिव

ह०/—

सक्षम प्राधिकारी

गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि.

गुना

S.O. 2028.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O 229E date 21-3-87 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

H.B.J. GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Singwasa Tehsil : Guna Distt. : Guna M.P.

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	363/	0.043
2.	364	0.065
3.	365/1	0.994
4.	359	0.756
5.	358	0.410
6.	357	0.356
7.	356/2	0.216
8.	355	0.637
9.	381/2	0.302
10.	381/4	0.248
11.	384	0.405
12.	392	0.659
13.	421/1	0.016
14.	421/3	0.016
15.	404/1	0.400
16.	404/2	0.130
17.	403/2-3	0.567
18	232	0.270
19	383	0.011
20.	382	0.022
21	398/1	0.248
22	398/2	0.292
	TOTAL	7.063

COMPETENT AUTHORITY
Gas Authority of India Ltd. Guna.
Sd./
[No. O—14016/601/87-G.P.]
RARKESHh KACKER. Dy Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.आ 2029—हज समिति नियमावली, 1963 के खंड 14 के अनुसार भारत सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत केन्द्रीय सरकार के अधिकारी श्री सईद मोहम्मद कमालुद्दीन सुभानी की, जो बम्बई में हज समिति के कार्यकारी अधिकारी थे, प्रतिनियुक्ति 22 मई, 1987 के अपराह्न से समाप्त की जाती है, जब उन्होंने कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ा था।

[सं. एम (हज)-118/1/5/85]
जे.आर. दुग, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2029.—In exercise of the powers vested in the Government of India in terms of Section 14 of the Haj Committee Rules, 1963, the deputation of Shri Syed Md. Kamaluddin Subhani, an officer of the Central Government, as Executive Officer, Haj Committee, Bombay is hereby terminated with effect from the afternoon of 22nd May, 1987 when he relinquished charge of the post of Executive Officer.

[No. M(Haj)/118-1/5/85]
J. R. DUGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

का० आ० 2030—राजनियक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, रियाद में सहायक श्री के.के. कक्कड़ को 16 मई, 1987 से कौंसुली एजेण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[टी- 4330/2/87]

New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 2030.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri K. K. Kakkar, Assistant in the Embassy of India, Riyadh to perform the duties of Consular Agent with effect from 16th May, 1987.

[T 4330/2/87]

का.आ. 2031—राजयनिक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, मोजाम्बिक में सहायक श्री सुभाष चन्द्र चावला को 8 जून, 1987 से कौंसुली एजेण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[टी 4330/2/87

S.O. 2031.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oath and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Subhash Chander Chawla, Assistant in the Embassy of India, Mozambique to perform the duties of Consular Agent with effect from 8th June, 1987.

[T 4330/2/87]

का.आ. 2032.—राजनयिक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, मस्कत मे सहायक श्री ओ पी मेहता को 18 मई, 1987 से कौंसुली ऐजन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[टी -4330/2/87]

S.O. 2032.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereb, authorise Shri O. P. Mehta, Assistant in the Embassy of India, Muscat, to perform the duties of Consular Agent with effect from 18th May, 1987.

[T-4330/2/87]

का.आ. 2033.—राजनयिक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस अधिनियम, 1948 (1948 का 41वा) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का सहायक हाई कमीशन, कैन्डी मे सहायक सर्वश्री आर. सलवम और एल. कृष्णामूर्ति दोनों को 18 मई, 1987 से कौंसुली ऐजण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[टी-4330/2/87]

S.O. 2033.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise S/Shri R. Selvam and L. Krishnamurthy both assistants in the Assistant High Commission of India, Kandy to perform the duties of Consular Agents with effect from 18th May, 1987.

[T-4330/2/87]

का.आ. 2034.—राजनयिक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, ब्रीजीलिया मे सहायक श्री आर.पी. कौशिक को 9 जून, 1987 से कौंसुली ऐजण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[टी 4330/2/87]

S.O. 2034.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. P. Kaushik, Assistant in the Embassy of India, Brasilia to perform the duties of Consular Agent with effect from 9th June, 1987.

[T-4330/2/87]

का.आ. 2035.—राजनयिक और कौंसलीय अधिकारी (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, दोहा में सहायक श्री वी. के. मोंगा को 25 जून, 1987 से कौंसुली ऐजण्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

(टी-4330/2/87)

ज.एस पण्डे उप-सचिव (कौंसुली)

S.O. 2035.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers' (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri V. K. Monga, Assistant in the Embassy of India, Doha to perform the duties of Consular Agent with effect from 25th June, 1987.

[T-4330/2/87]

J. S. PANDE, Dy. Secy. (Consular)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1987

सार्वजनिक सूचना

का. आ 2036.—दिनांक 6-1-87 को भारत के राजपत्र, भाग-3 उपखण्ड (ii) असाधारण में प्रकाशित समसंख्यक सार्वजनिक सूचना का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली मुख्य योजना/जोनल योजना मे निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधन के संबंध मे कोई आपत्ति हो या उसके संबंध मे कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर लिखित रूप मे सचिव, दिल्ली विकास-प्राधिकरण, विकास सदन, बी ब्लाक, आई. एन. ए, नई दिल्ली को भेज दें। आपत्ति करने या सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे ।

संशोधन—

"लगभग 0 44 हेक्ट. (1.1-एकड़) क्षेत्र, जो जोन एफ-3 मे महरौली रोड के साथ लगता है और जो अनुमोदित जोनल योजना/विकास योजना मे आंशिक रूप से (0 08 हेक्ट०) हरित के लिए और आंशिक रूप से (0.36 हेक्ट) "सरकारी और अर्द्ध सरकारी सुविधाओं" (स्कूल) के लिए निर्दिष्ट है और जो उत्तर मे हरित क्षेत्र, पूर्व मे शैक्षणिक उपयोग, दक्षिण मे 9 मीटर चौडी सडक तथा पश्चिम मे 60 मीटर भूमिधिकार के महरौली रोड से घिरा हुआ है, के भूमि उपयोग को "व्यावसायिक" (स्थानीय खरीददारी उपयोग) में बदलने का प्रस्ताव है ।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला प्लान निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्यशील दिवसों को उपनिदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, छटी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय मे उपलब्ध होगा ।

[स. एफ. 3(123)/83-एम. पी.]

जनक जुनेजा, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 8th August, 1987

PUBLIC NOTICE

S.O. 2036.—In supersession of public notice of even no. published in the Gazette of India, Part-II section-3 sub-section (ii) Extra-Ordinary on 6-1-87, the following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, is hereby published for

public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection or suggestion in writing to the Secretary Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi within a period of thirty days from the date of issue of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :—

"The land use of an area, measuring about 0.44 ha. (1.1 acre) abutting Mehrauli Road in zone F-3, earmarked in the approved Zonal Plan|Development Plan partly (0.08) for green area and partly (0.36ha.) for 'public and semi-public facilities' (School) and bounded by green area in the Noth, educational use in the Fast, 9 mtrs. wide road in the South and 60 mtrs. R|W road Mehrauli Road in the West is proposed to be changed to 'Commercial' (Local Shopping Use)."

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th floor, I.P. Estate, New Delhi, on all working days within the period referred to above.

[No. F. 3(123)|83-MP]

JANAK JUNEJA, Secy.

Delhi Development Authority

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.आ. 2037.—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम IX) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 3-4-1986 को बड़ोदरा मंडल के देवदी और जंखाव स्टेशनों के बीच 246 उप माल एवं पेसेंजर गाड़ी के इंजन और बोगियों के पटरी से उतर जाने से उत्पन्न सभी दावों पर कार्रवाई करने के लिए एतद्द्वारा श्री ए.के. शाह, सेवा निवृत्त जिला जज, नानपुरा, सूरत को तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 87/ई(ओ)/II/1/3)]

सतीश मोहन वैश, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2037.—In exercise of the powers conferred by Section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890) the Central Government hereby appoints Shri A. K. Shah, retired District Judge, Nanpura, Surat as ad-hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of derailment of engine and bogies of 246-UP Goods-cum-passenger train between Devdi and Zankavav stations of Vadodara division on 3rd April, 1986. His Headquarters willl be at Surat.

[No. 87/E(O)II/1/3]

S. M. VAISH, Secy., Railway Board

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1987

का.आ. 2038.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने मुलाना, बहिटा, छछरौली, साहा, हंडेसरा, मठेहरी, लाडू, दादुपुर, खारवन, नाहरपुर, बिलासपुर तथा मुस्सिम्बल मुसलमानान टेलीफोन केन्द्र, हरियाणा, सर्किल, में दिनांक 1-8-1987 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-13/87-पी.एच.बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 20th July, 1987

S.O. 2038.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-8-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Mullana, Bihta, Chhachhrauli, Saha, Handesra, Matheri, Laru, Dadupur, Kharwan, Naharpur, Bilaspur and Mussimbal Musalmanan Telephone Exchanges under Haryana Telecom. Circle.

No. 5-13 87-PHB]

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

का.आ. 2039.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने कुरुमन्डूर टेलीफोन केन्द्र, तमिल नाडु सर्किल, में दिनांक 1-8-1987 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-1/87-पी एच बी]

पी. आर. करडा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

New Delhi, the 23rd July, 1987

S.O. 2039.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specifies 1-8-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kurumandur Telephone Exchange, Tamil Nadu Telecom. Circle.

[No 5-1|87-PHB]

P. R. KARRA, Asst Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1987

का.आ. 2040.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, आकाश कीनारी कोयलरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या -1, धनबाद, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd July, 1987

S.O. 2040.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government industrial tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Akash Kinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 17th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 34 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Akash Kinaree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 10th July, 1987

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour has, by Order No. L-20012(482)/82-D.III (A) dated, the 5th May, 1983, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Akash Kinaree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Ltd., Dhanbad in regularising 102 Contractor's workmen and not regularising Shri Sheo Shanker Singh, Munshi of the same contractor, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the management, shorn of unnecessary details is as follows :

The management of Akash Kinaree Colliery which comprises of non-coking coal mines was taken over by the Central Government with effect from 31-1-1973 and ultimately the said colliery was nationalised with effect from 1-5-1973. The erstwhile management of the colliery engaged several contractors including Sri Laljee Singh to perform various types of jobs and the contractors concerned used to execute jobs assigned to them by engaging workmen of their own. The new management established immediately after take over of the colliery abolished the contract system and decided to execute all works by engaging its own workmen. While doing so the management took into consideration several factors and decided the requirement of various types and categories of workmen for executing the contractual jobs departmentally.

The management recruited workmen on its roll from amongst the contract workers already working in the colliery. The contractors used to employ temporary and casual workmen to execute different types of contract works; none of them were on permanent roll and no one was employed continuously and the contract works were mostly temporary or casual. The new management selected the workmen of the contractors according to the need of the management and recruited them under its direct employment, and these workmen were regularised and put on permanent rolls. Several workmen of various contractors approached the new management for employment; but it was not possible for the new management to recruit all the workmen of all the contractors. The management recruited and regularised some of the contractors' workers depending upon the need. It is absured to suggest that because the management recruited and regularised about 100 contract workmen, it should recruit and regularise all the workmen working under the contractors. The management has every right to recruit the number of workmen required and it cannot be compelled to recruit and regularise all workmen without any need. The concerned workmen was a Munshi of the contractor. He was attached to the contractor and was doing his job wherever the contractor used to depute him. He was not confirmed to any particular type of contract work in any particular colliery. His relationship with the contractor was different from other ordinary unskilled or skilled workers. It is alleged that the workmen concerned has raised the dispute after the lapse of period of 9 years with some ulterior motive.

3. The case of the concerned workman is as follows :

Sri Laljee Singh was the lease holder of Quarry No. 6 of North Teturia Section of Akashkinaree Colliery. He had engaged 103 workmen for running the mine and raising coal. The concerned workmen had been working as permanent Munshi at Quarry No. 6. He as well as the other workmen had been working under the direct control and supervision of the colliery management and necessary equipment/implement was being supplied by the management. But the management used to disburse the wages of the concerned workman through intermediaries of Laljee Singh which was nothing but legal camoufledge to deprive the workmen of their legitimate claim. All the 103 workmen become employees of Akashkinaree colliery on and from appointed date, i.e. 1-5-1973 after the Nationalisation Act. The concerned workman had rendered continuous service and put in more than 190/240 days attendance in each calendar year and in the preceding twelve months prior to his stoppage from work. The management abruptly stopped him from rendering service with effect from 14-5-1973 without any chargesheet and without assigning any reason. He protested immediately against the illegal and arbitrary action of the management, but he was advised to wait as the matter was under active consideration of the higher echelon of the management but nothing come out and ultimately the union raised the industrial dispute. During the conciliation proceeding the management assured the union for amicable settlement and on the assurance of the management the union withdraw the dispute. The management moved note-sheet under intimation to the concerned workman; the note-sheet was forwarded and recommended by the Personnel Manager and General Manager of the Area. But in spite of the aforesaid fact the management did not allow him to resume his duty and the union again raised the dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad. It is alleged that due to adamant attitude of the management the conciliation proceeding ended in failure and the present reference was made. It is further alleged that the action of the management in not regularising the concerned workman was illegal, arbitrary, unjustified and against the principle of natural justice. Under the circumstances the workman has prayed that the management be directed to regularise him in service with effect from 14-5-1973 by reinstating him with full back wages.

4. In his rejoinder to the written statement of the management the concerned workman has denied and disputed each and every fact as stated in the written statement of the management. The concerned workman has asserted that he was attached to the contractor and that he was not at the back and call of the contractor. He has also asserted that his relationship with the alleged contractor was not also different from ordinary unskilled and skilled workmen.

5. In its rejoinder to the written statement of the workman concerned the management has further stated that it is incorrect to suggest that Quarry No. 6 was given on lease to Laljee Singh and that it is also incorrect to suggest that 103 workmen were engaged by Sri Singh for running the mine and raising coal. Sri Laljee Singh was one of the contractors of the colliery and he was paying wages to his own workmen. Since the concerned workman was the Munshi of the contractor himself and since there was no need for employment of the Munshi the management did not recruit him. It has been denied that the concerned workman put in 190/240 days of attendance in each calendar year and in the preceding twelve months before nationalisation.

6. The management has examined only one witness in this reference, but laid no documentary evidence. On the other hand, the workman concerned examined himself and introduced in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-7.

7. Admittedly, North Tentuliya and North Akashkinari were two separate collieries and the management of both the collieries was take over by the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 and vested in the Central Government on and from the appointed day, i.e., 31-1-73. It transpires from the evidence of MW-1, Surendra Singh, that five small collieries were amalgamated and constituted a composite colliery styled Akashkinari colliery after the management of the collieries were taken over by the Central Government with effect from 31-1-1973. There is no evidence on record to dis-place or dis-prove this fact. It is also admitted position that Akashkinari colliery was nationalised under the provisions of Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 which came into force on the 1st day of May, 1973.

8. The management has contended that one Satdeb Singh was the lease-holder of North Tentuliya and North Akashkinari collieries which new form part and parcel of Akashkinari colliery. On the other hand, the workman has contended that Laljee Singh was the lease-holde. of North Tentuliya colliery which included Quarry No. 6. None of the parties have produced before me documents in support of their respective contentions. Hence I consider that the claim of both the parties arrayed are unsustainable in so far as the lease-holder's interest of the said colliery is concerned. On the contrary it appears from the schedule of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 and Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 that Khimji Dessa and Co., Katrasgarh and Debram Ramji, Katrasgarh were respectively the owners of North Akashkinari Colliery and North Tentuliya Colliery. WW-1 Sheo Shankar Singh the concerned workman has stated that Debram Ramji was the owner of North Tentuliya colliery and Laljee Singh was the lease-holder of Quarry No. 6 of the said colliery for the specific purpose of raising the coal. But this statement of his is not supported by documents or other cogent evidence. It has been asserted by the management that Laljee Singh was the contractor engaged and he used to engage workmen as and when work was available. In the present reference the concerned workmen has been described as Munshi of the same contractor whose workmen numbering 102 were regularised by the management of M/s. B.C.C. Ltd. It transpires from evidence that 103 workmen including the concerned workman were employed by Laljee Singh in the quarry and that all of them excepting the concerned workman were employed or departmentalised. This position also buttressed by Office Note of the management dated 14-8-1981 Ext. W-1. Thus, the inescapable conclusion is reached that this concerned workman was a Munshi of the contractor Laljee Singh and that Laljee Singh had a work force of 103 workmen including the concerned workman of whom all except the concerned workman have been regularised or departmentalised. It is asserted by the workmen that these work force of Laljee Singh was engaged in the mining operation and that all of them worked under the direct control and supervision of the colliery management. The management has denied that Laljee Singh was a lease-holder but has not denied in specific terms that the work force of Laljee Singh was not employed in mining operation. All that the management has stated is that all of them were employed on casual basis and that they were employed and when work was available. But MW-1 Surendra Singh has himself stated that the contractors workmen were employed on contractual basis and not on casual basis. On the other hand, the evidence of WW-1 Sheo Shankar Singh firmly establishes the fact that the entire work force of Laljee Singh comprised of 103 workmen including himself were employed in the quarry and that excepting himself all other workmen were employed as stone cutter, earth cutter, coal cutter etc. and that the workmen used to work in groups and it was his duty to keep their attendance, out-put of every group with regard to raising of coal, earth and stone, to supply working implements to the workmen and various other jobs. Nothing has been elicited from him in cross-examination to dis-prove the fact. Thus I come to the conclusion that the entire work force of Laljee Singh, a contractor, was employed in Quarry No. 6 for mining operation in the aforesaid coal mine.

9. It has been contended by Sri B. Joshi that there is no scope for the Tribunal to hold in view of the terms of reference that the concerned workmen and the work force of Laljee Singh were the employees of the colliery in question. On the other hand, Sri D. Mukherjee, authorised representative of the concerned workmen has laboriously submitted that the entire work force of Laljee Singh including the concerned workmen were the employees of the colliery in question. In support of his contention Sri D Mukherjee has cited before me the case reported in 1963 (II) LLJ 447 (Basti Sugar Mills Ltd. Vs. Ram Ujagar and others). In that case it has been held that the words used in the definition of "workmen" in Sec. 2(z) of the Industrial Disputes Act are themselves sufficiently wide to bring in persons doing work in an industry whether the employment was by the management of by the contractor of the management. Besides this the other conclusion reached in the above decision do not apply to the facts and circumstances of the present case. Sri D. Mukherjee has also cited the decision reported in 1978 Lab. I.C. 1964—AIR 1978 SC 1410 (Hussainbhai, Petitioner Vr. The Alath Factory Tezhilali Union and others, Respondent). In that decision it has been held by Hon'ble Supreme Court that :

> "Where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact the employer. He has economic control over the workers' subsistence, skill and continued employment. If he, for any reason checkes off, the worker is, virtually, laid off. The presence of intermediate contractors with whom alone the workers have immediate or direct relationship or contract is of no consequence whom, on lifting the veil or looking at the conspectus of factors governing employment, it is found, though dropped in different perfect paper arrangement, that the real employer is the management, not the immediate contractor."

In the present case the work force of Laljee Singh, a contractor, was engaged for mining operation in the coal mine in question. The evidence of MW-1, the concerned workman lends firm support to this position. That being so, it must be held that the entire work force of Laljee Singh were in fact the work force of the erstwhile management.

10. Even if this position remains in a fluid stage the case of the management does not get any succour. Chapter V of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 has made proivsions relating to employees of coal mines and Section 14 of the Act runs as follows :

> "14. Employment of certain employees to continue.
>
> (1) Every person who is a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 and has been immediately before the appointed day in the employment of a coal mine shall become and from appointed day, an employee of the Central Government or, as the case may be of the Government company in which the right, title and interest of such

mine have vested under this Act, and shall hold office or service in the coal mine with the same rights to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the rights in relation to such coal mine had not been transferred to, and vested in, the Central Government or the Government company, as the case may be, and continue to do so unless and until his employment in such coal mine is duly terminated or until his remuneration, terms and conditions of employment are duly altered by the Central Government or the Government company. . . . ."

This provision envisages for employment of every person in the employment of a coal mine. The word "employ" means 'to give work to' and the word 'employment' means act of employing; that which engages or employs' (Chambers Twentith Century Dictionary—Impression 1962). The evidence on record establishes the fact that the entire work force of Laljee Singh was in the employment of the coal mine in question immediately before the appointed day i.e. 1-5-1973. The Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Act, 1986 has not amended the provisions of Section 14 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, but a new Section i.e. Section 14 has been substituted by this Amendment Act for Section 14 of the earlier Act. Thus it is evident that in view of the provisions of Section 14(1) of the Coal Mines (Nationalisation) Act, the entire work force of Laljee Singh is entitled to get employment under the new management.

11. Admittedly 102 out of 103 of the work force have been departmentalised or regularised. The management has taken the plea that there was requirement for their srevices. They have taken the plea also that since the services of the Munshi was not required by the new management his case was not considered.

12. It appears from the evidence of the concerned workman that since 1968 till 13-5-1973 he worked regularly and at a stretch in the quarry of North Tentuliya colliery and that before dispensing with his services he was not afforded any opportunity to ascertain why his services were dispensed with nor was any reason assigned for dispensation with his service. There is no dispute that he worked in the quarry till 13-5-1973 i.e. even after Coal Mines (Nationalisation) Act came into force. But his services were not required by the management on the plea that there was no requirement for his service. The position taken by the management is merely ipse dixit and not supported by any cogent evidence. No evidence is garnered on record on the side of the management to evince what was the requirement of the management at the relevant time and what services were available to the management in the category of Munshi. That being so, the plea of management that there was no requirement for the service of the Munshi is not supported by any cogent evidence. Hence the plea of the management in this respect must ounder on the ground.

13. The workman concerned has stated that the service he was rendering for the colliery corresponds to the duties of the scale of pay of Clerk Grade III under the new management. This position has not been disputed by the management.

14. Considering all these facts and circumstances I come to the conclusion that the concerned workman is entitled to be employed under M/s. Bharat Coking Coal Ltd. as Clerk Grade III and the scale available therefore with effect from 14-5-1973 with full back wages. Hence an award is passed holding that the action of the management of Akashkinari colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in not regularising the concerned workman in service is not justified. The concerned workman, Sheo Shankar Singh, be reinstated in service as Clerk Grade III with the scale of pay attached thereto with effect from 14-5-1973 with full back wages. The reference is answered accordingly. The parties are to bear their own cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/482/82-D.III(A)]

का.आ. 2041—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बासुदेव कोलयरी, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या -1, धनबाद के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2041.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Basdeopur Colliery of M/s Bharat Coking Coal Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 23 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Besdeopu Colliery of M/s. B.C.C.Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate and Shri B. M. Lall, Dy. Chief Personnel Manager, Bhagaband Area of M/s. B.C.C.L.

For the Workmen.—Shri Chandra Mouli Sharma, Organising Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dhanbad, dated the 6th July, 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012(307)/83-D.III(A) dated, the 11th April, 1984 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that S/Shri Ramagya Yadav, Biseswar Mahato, Ramdhani Ram, Bindeshwar Bhuiya and Sidheswar Bhuiya should be treated by the management of Basdeopur Colliery of Bharat Coking Coal Limited as regular workmen with payment of wages in category-I is justified ? If so, to what relief are the said workmen entitled and from what date ?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/307/83 D.III(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of Reference No. 23 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bansdeopur colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd; P.O Kusunda, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workman

Joint Compromise Petition of the Employers and Workmen.

The above mentioned employer and workmen beg to submit jointly as follows :—

(1) That the employers and workmen have jointly negotiated the matter directly as covered by the aforesaid reference with a view to coming to a mutually acceptable and amicable settlement.

(2) That as a result of such direct negotiations, the parties have arrived at a settlement on the following terms:—

(a) That S/Sri Ramagya Yadav, Ramdhani Ram Bisheswar Mahato, Sidheswar Bhuiya and Bineshwar Bhuiya, the workmen concerned who have put in 240 and more days of attendance would be offered employment by the Management as Miners/Loaders without any back wage.

(b) That the Union concerned, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh will certify the Photographs of these workers in regard to their genuineness and that workers concerned will also file affidavits to the same effect. The said certificate and affidavit will also testify that the persons concerned are the real workers concerned in the aforesaid reference.

(c) That on fulfilment of the provisions referred to in clauses (a) & (b) above, the dispute referred to this Honble Tribunal would stand finally resolved and that this Hon'ble Tribunal will be requested to pass an award accordingly.

(3) That the provisions of clauses (a) and (b) above having been fulfilled the five workers covered by the aforesaid reference have already been provided employment by the Management as Miner/Loaders in Balihari Colliery of Bharat Coking coal Ltd, and they have started working in that capacity.

In view of the above, the employers and the workmen most respectfully pray that the Hon'ble Tribunal may be please dispose of the reference in terms of the joint compromise petition.

(Chandra Mouli Sharma)
Organising Secretary
Rashtriya Colliery Mazdoor
For and Behalf of Workmen

(Brij Mohan Lall)
Dy. Chief Personnel Manager
Bhagaband Area (Now P.B. Area)
For and on Behalf of Employer.

का आ 2042—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भागाबन्ध क्षेत्र, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या-1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2042.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhagaband Area of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th July, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 74 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhagaband Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen.—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 1st July, 1987

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012-(153)/83-D.III(A), dated, the 10th October, 1983 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the action of the management of Bhagaband Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad in not promoting Shri R. A. Rai Grade-I Clerk to Special Grade while promoting his juniors is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2 The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

[No. L-20012/153/83-D.III(A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF THE CENTRAL INDUSTRIAL DISPUTE RULES OF THE I.D. ACT

PRESENT :

Management representatives :

1. Shri T. N. Yadav, RCMS.
2. Shri P. Mahraj, Dy. P. M.

Union/Workmen representatives

1. Shri T. N. Yadav, RCMS.
2. Shri R. A. Rai, Area Office.

SHORT RECITAL OF THE CASE

RCMS raised an industrial dispute over non-grant of Clerical Grade Special to Shri R. A. Rai who is said to be superseded by S/Shri T. C. Prasad an dS. S. Thakur. This dispute culminated in Reference No. 74/83 which is pending before the Industrial Tribunal No. 1. During the pendency of the reference, the case was discussed between the parties and after lengthy discussions it is agreed as under :

TERMS OF SETTLEMENT

(1) Shri R. A. Rai is promoted with effect from 1-3-1980 i.e. the date Shri T. C. Prasad was promoted in Clerical Grade Special. He will get notional seniority from 1-3-1980 and monetary benefit will accrue to him from the date of reference i.e. from 10-10-1983.

(2) There is no subsisting dispute and the dispute stands settled finally.

(3) Copy of the settlement will be filed before the Industrial Tribunal No. 1 with the prayer from both the parties for acceptance of the settlement in full and final settlement of the above Reference before the Hon'ble Tribunal.

Signature of the parties:

(B. M. Lall)	(T. N. Yadav)
Personnel Manager Bhagaband Area,	Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh
(P. Mahraj)	(R. A. Rai)
Dy. Personnel Manager Bhagaband Area.	Bhagaband Area Office

Witness :

Sd/- Illegible.

Co : Presiding Officer, Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad.

Co. : ALC (C), Dhanbad.

Co. : Central Labour Commissioner (C), New Delhi.

Co : General Manager (Personnel), BCCL, Koyla Bhawan.

Co : General Manager, Bhababand Area.

Co : Shri R. A. Rai, Bhagaband Area Office.

Co : Finance Manager/Dy. Manager (Admn.) Bhagaband Area.

Part of the Award

Sd-/ Illegible

अध्यासी अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक, न्यायाधिकरण संख्या-1, धनबाद

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1987

शुद्धिपत्र

का.आ. 2043:—भारत सरकार श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या 815 दिनांक 6 मार्च, 1987 भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(ii) में दिनांक 21 मार्च 1987 को प्रकाशित क्रम संख्या नं. 2 में "नार्दन" को "नार्थ" पढ़ा जाये ।

[संख्या एस-35019(3)/87-एस.एस.-II]

New Delhi, the 23rd July, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 2043.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 815 dated the 6th March, 1987, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 21st March, 1987, in serial No. 2 for "Northern" read "North".

[No. S-35019(3)/87-SS.II]

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का. आ. 2044—मैसर्स माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया लि.), 467, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर—302013 (आर. जे./2519) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4577 तारीख 22-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 17-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 16-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजिक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, फिर पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सभी सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस.-35014/225/83-पी. ए. 2/एस. एस.-2]

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2044.—Whereas Messrs Modern Food Industries (India) Limited, 467 Vishwa Karma Industrial Area, Jaipur-302013 (RJ/2519) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 4577 dated the 22-11-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17-12-1986 upto and inclusive of the 16-12-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme., including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas, an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Reigonal Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Reigonal Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/225/83 [F II S II]

का०आ० 2045:—मैसर्स दी कराण इन्वाध्य बैंक लि० बी. नं. 21, कत्तर–2 नामित नागर (टी एन /4177) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3982 तारीख 1-10-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 22-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 21-10-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिलनाडू को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस 35014/177/83-पी. एफ. 2/एस. एस-2]

S.O. 2045.—Whereas Messrs The Karur Vysya Bank Limited, P.B. No. 21, Karur-2 Tamil Nadu (TN/4177) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3982 dated the 1-10-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 22-10-1986 upto and inclusive of the 21-10-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas, an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No S-35014/177/83-PF.II-SS II]

का. आ. 2046—मैसर्स दी कन्याकमारी जिला को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., अरलवेमोझी, तामिलनाडु-62930 (टी. एन/5610) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों की उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हे कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) अधीन अनुज्ञेय है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 2085 तारीख 18-4-1983 के अनुसरण में और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 7-5-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 6-5-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते है, तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप मे वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देह रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा मे सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तामिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निश्चित तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बकाया राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/83/83-पी. एफ. 2/एस एस-2]

S. O. 2046.—Whereas Messrs The Kanyakumari District Co-operative Spinning Mills Limited, Aralvaimazhis, Tamil Nadu-62930 (TN/5610) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provient Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premimum, in enjoymnt of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Depdsit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 2085 dated the 18-4-1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 7-5-1986 upto and inclusive of the 6-5-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/83/83-PF.II-SS.II]

का.आ. 2047.—मैसर्स इन्डस्ट्रियल डिवैलपमैन्ट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि., सरदार पटेल हाल, भुवनेश्वर (ओ. आर./294) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3713 तारीख 15-9-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 1-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 30-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 3(क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6 यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/161/82-पी. एफ. 2/एस. एस.-2]

S.O. 2047.—Whereas Messrs Industrial Development Corporation of Orissa Limited, Sardar Patel Hall, Bhubaneshwar (OR|294) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3713 dated the 15-9-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-10-1986 upto and inclusive of the 30-9-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group I surance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of acconuts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and where any amendment is likely to affect adversely the interst of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving the approval, give a reasonable opportunity to the employers to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomiinees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/161/82-PF-II-SS-II]

का. आ. 2048—मैसर्स जेबरायल इन्डिया लि., एम-304, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुन्द, बाम्बे-400081 (एम. एच./5817) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3505 तारीख 18-9-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 2-10-1985 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 1-10-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/152/82-पी.एफ.-2/एस. एस.-2]

S.O. 2048.—Whereas Messrs Gabrial India Limited S-304, Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund, Bombay-400081 (MH/5817 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of primum, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3505 dated the 18-9-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 2-10-1985 upto and inclusive of the 1-10-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, Direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of acconuts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissiner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/152/82-PF.II-SS II]

का. आ. 2049.—मैसर्स फैनर (इंडिया) लि., 19/21 मनोहर दास स्ट्रीट, जी. पी. ओ. के सामने, बम्बई-400001 (एम. एच./14567) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 29 तारीख 6-12-1982 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 1-1-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 31-12-1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्रा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पटट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/348/82-पी. एफ. 2/एस एस-2]

S.O. 2049.—Whereas Messrs Fenner (India) Limited, 19/21, Manohardas Street, Opp. GPO, Bombay-400081 (MH/14567), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of primum, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefit admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 29, dated the 6-12-1982 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 7-1-1986 upto and inclusive of the 31-12-1988.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, Direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of acconuts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the said features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits amissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident dent Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased memebers who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No S-35014/348/82-PF II SS.III

का. आ. 2050.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स दा प्रिन्टर्स इंजिनियरिंग कंपनी, प्लाट नं. 27ए, सैक्टर-25, बल्लभगढ़ ।

2. मैसर्स हरमन डीजल सर्विस, हम्बो हाउस रनधीर लेन, करनाल और इसकी 224 अरबन एस्टेट II, हिसार स्थित शाखा ।

3. मैसर्स रिसर्च-एन-सेल्स सेंटर, एम—2 इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत और इसका 1—62, कनाट सर्कस, नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय ।

4. मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास ग्राम सेवली पोस्ट आफिस राई कस्बा सोनीपत और इसका करोल बाग, नई दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय तथा अलग-अलग जगह स्थित 10 शाखाएं ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एस – 35019(27)/87 – एस एस–2]

S.O. 2050.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. The Printers Engineering Company, Plot No. 27-A, Section 25, Ballabgarh.
2. M/s. Harman Diesel Service, Hambo House, Randhir Lane, Karnal including its branch at 224, Urban Estate-II, Hissar.
3. M/s. Research-N-Sales Centre, M-2, Industrial Area, Sonepat including its Head Office at 1-62, Connaught Circus, New Delhi.
4. M/s. Haryana Sheet Glass Limited, Village Sevli, Post Office Rai, District Sonepat, including its Registered Office at Karol Bagh, New Delhi and ten branches at different places.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019 (27)/87-SS-II]

का. आ. 2051.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :—

1. मैसर्स टिफिन रूम "स्पेशल ब्यूरो भारत सरकार" इंडस्ट्रियल अशुरेन्स बिल्डिंग द्वितीय मंजिल चर्च गेट, बम्बई-20।

2. मैसर्स अडवरटाईजिंग कन्सेशनरीज प्राईवेट लिमिटिड, 602 मेकर चैम्बर, 5 नारिमन प्वाईंट, बम्बई-21।

3. मैसर्स टावर इंशोरेन्स एंड रिइन्शोरेन्स सर्विसिज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 7/5 मेकर चैम्बरस, 5 नारिमन प्वाईंट, बम्बई-21।

4. मैसर्स अशवनी कुमार एंड कंपनी, 4ए, क्रीम चैम्बर्स प्रथम मंजिल अम्बालाल दोषी मार्ग (हमाम स्ट्रीट) फोर्ट, बम्बई-23।

5. मैसर्स त्रिमूर्ति ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राईवेट लिमिटेड, शाले बिल्डिंग, 28 बैंक स्ट्रीट, बम्बई-23।

6. मैसर्स डिपार्टमैन्ट्स स्टाफ कैन्टीन कन्ट्रोलर्स आफ डिफेन्स अकाउंट नेवी (नाभी), कपरेज रोड, बम्बई-39।

7. मैसर्स श्री ज्योतीर लिंग पाणी, परवता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कुशिरे तालुक पन्हाला जिला, कोल्हापुर।

8. मैसर्स आर जे असोसिएटस (इंजीनियर्स) प्राईवेट लिमिटिड, एक्सेल स्टेट, एस वी रोड, गोरे गांव (पश्चिम) बम्बई-62 और इसका बम्बई-54 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय तथा बम्बई-21 स्थित एक यूनिट ।

9. मैसर्स स्मृति इंटर प्राइजिज (फैक्ट्री) 51, सिद्धपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट मासराती लेन कुर्ला, बम्बई-70 और इसकी बम्बई-36 स्थित शाखा ।

10. मैसर्स अलडाड फर्मा प्लांट 235 जवाहर को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट कामटे और इसका बम्बई-50 स्थित प्रशासनिक कार्यालय ।

11. मैसर्स श्री सीडस प्राईवेट लिमिटेड, मोन्धा पोस्ट आफिस, मोन्धा रोड, औरंगाबाद-1 और इसकी (1) हैदराबाद (2) जयपुर (3) आरमूर (आंध्र प्रदेश) (4) लातूर (5) बेलरी (6) इंदौर स्थित छः शाखाएं ।

12. मैसर्स श्री नारायण आरगनिक्स प्राइवेट लिमिटिड प्लाट नं. 70 तलोजा जिला रायगढ़ और इसका 9 महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग, नागिनदास मास्टर रोड, एक्सटेन्शन फोर्ट, बम्बई-23 स्थित कार्यालय ।

13. मैसर्स आरट्रीए कन्सलटेन्ट कपनी लिमिटिड द्वितीय मंजिल शीयाट महल, 463, डा. अनीबसन रोड, बम्बई-25 ।

14. मैसर्स रीलको पेपर प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटिड, बम्बई-31 और इसका 7 कुम्बरा स्ट्रीट, बेलार्ड स्टेट, बम्बई-38 स्थित कार्यालय ।

15. मैसर्स आफिस आफ दी ट्रस्टीज पारसी पंचायत फंड्स एंड प्रापर्टीज, 209 दादा भाई नौरोजी रोड, फोर्ट

बम्बई-1 और इसकी (1) खरेघाट कालोनी ह्युग्स रोड बम्बई (2) पारूख धर्मशाला (3) डूंगरवाडी (4) पारसी पंचायत की अलग-अलग कालोनियों में स्थित शाखाएं ।

16. मैसर्स गैसको सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटिड गैसको हाऊस ए–30 आभीमनसरी सोसाइटी, पासान रोड, बी बी नं. 2, एन सी एल पोस्ट पूना–8 ।

17. मैसर्स भोलानाथ इंजिनियरिंग वर्क्स युनिट नं. 11 केमब्रोस इंडस्ट्रियल स्टेट सोनापुर लेन आफ एल बी एस मार्ग, भान्डुप, बम्बई-78 ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एस०–35018(2)/87 – एस० एस० 2]

S.O.2051.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Tiffin Room Special Bureau Government of India Industrial Assurance Building, 2nd Floor, Charch Gate, Bombay-20.
2. M/s. Advertising Concessionaries Private Limited, 602, Maker Chamber No. 5, Nariman Point, Bombay-21.
3. M/s. Tower Insurance and Reinsurance Services (India) Private Limited. 7/5. Maker Chambers, 5, Nariman Point, Bombay-21.
4. M/s. Ashwini Kumar and Company, 4-A, Karim Chambers, First Floor Ambalal Doshi Marg (Hamam Street) Fort, Bombay-23.
5. M|s. Trimurti Travel and Tours Private Limited, Shale Building, 28, Bank Street, Bombay-23.
6. M/s. Departmental Staff Canteen. CO (Nevy), (Nabhi) Cooperage Road, Bombay-39.
7. M/s. Shree Jyotir Ling Pani Purvathaseva Shakari Sanstha Maryadit, Kushire, Taluka Panhala, District, Kolhapur.
8. M/s. R. J. Associates (Engineers) Private Limited, Excel Estate, S. V. Road, Goregaon (W) Bombay-62, including its Registered Office, at Bombay-54 and Bombay-21.
9. M/s. Smirti Enterprises (Factory) 51, Sidhpura, Industrial Estate, Masrani Lane, Kurla, Bombay-70 including its branch at Bombay-36.
10. M/s. Allied Pharma Plot 235, Jawahar Co-op. Industrial Estate, Kamothe Panvel, Kolaba, including its branches at Bombay-50.
11. M/s. Shree Seeds Private Limited, Mondha Road, Aurangabad, including its six branches at (1) Hyderabad (2) Jaipur (3) Armoor (A.P.) (4) Latur (5) Bellary (6) Indore (M.P.).
12. M/s. Shri Narayan Organics Private Limited, Plot No. J170, M.I.D.C., Industrial Estate Taleja District Raigad-8 including its offices at 9, Maharashtra State Co-operative Bank Building Nagindas Master Road, Extension Fort, Bombay-23.
13. M/s. Austrind Consultants Company Limited, Second Floor, Ceat Mahal, 463, Dr. Annie Besant Road, Bombay-25.
14. M/s. Reelco Paper Products Private Limited Cross Road, Wadala, Bombay-31, including its office at Bombay-38.
15. M|s. Office of the Trustees of the Parsi Panchayat Funds and Properties, 209, Dadabhai Naroji Road, Fort, Bombay-1 including its branches (1) Khareghat Colony Huges Road, Bombay, (2) Parukh Dharamshala (3) Doongerwadi (4) Different Colonies of Parsi Punchayat.
16. M/s. Gaco Systems India Private Limited, Gaco House, A-30, Abhimanshree Society, Pashan Road, B. B. No. 2, NCL Post, Poona-8.
17. M|s. Bholanath Engineering Works, 11, Kembros Industrial Estate, Sonapur Lane, Off L.B.S. Marg, Bhandup, Bombay-78.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35018(2)/87-SS-II]

का. आ. 2052—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटिड, (भारत सरकार का एक उपक्रम संचार मंत्रालय) कनिष्का प्लाजा, तृतीय मंजिल 19 अशोक रोड, नई दिल्ली–1 और इसका (1) पंजीकृत कार्यालय और दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय खुर्शीद लाल भवन, जनपथ नई दिल्ली-50 (2) बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय टेलीफोन भवन, कोलाबा बम्बई–5 तथा (3) दिल्ली और बम्बई स्थित दूसरे कार्यालय और स्थापन;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एस०–35019(31)/87 – एस. एस० 2]

S.O. 2052.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

M/s. Mahanagar Telephone Nigam Limited, (A Government of India Enterprises, Ministry of Communications), Kanishka Plaza 3rd Floor, 19 Ashoka Road, New Delhi-1, including its (1) Registered Office and Delhi Circle Office at Khursheed Lal Bhawan, Janpath, New Delhi-50 (2) Bombay Circle Office at Telephone Bhawan, Colaba, Bombay-5 and (3) the attached offices establishments in Delhi and Bombay.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019 (31)/87-SS II]

का.आ. 2053:—मैसर्स फैडरेशन आफ इंडिया चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, फैडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-1 (डी.एल./3553) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4585 तारीख 28-11-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 17-12-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 16-12-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के

हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/285/83-पी एफ 2/एस एस-2]

S.O. 2053.—Whereas Messrs Federation of India, Chambers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001 (DL/3553) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4585 dated the 28th November, 1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 17th December, 1986 upto and inclusive of the 16th December, 1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/285/83-PF. II-SS. II]

का.आ. 2504 —मैसर्स, नेशनल इन्स्ट्रूमैण्टस लि., 1/1 राजा एस.सी. मलिक रोड, कलकत्ता-32 (डब्ल्यू बी./1752) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 318 तारीख 6-1-1984 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 28-1-1987 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 27-1-1990 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/302/83-पी.एफ. 2/एस एस-2]

S.O. 2054.—Whereas Messrs National Instruments Limited, 1/1, Raja S. C. Mullick Road, Calcutta-32 (WB/1752) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 318 dated the 6th January, 1984 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 28th January, 1987 upto and inclusive of the 27th January, 1990.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employees, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance to benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of sum assured to the nominee or the Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014/302/83-PF II-SS-II]

का.आ. 2055.—मैसर्स यूनिवर्सल इण्डस्ट्रीज, 23, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरा भोपाल (एम.पी./2073), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1959 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम से किसी सदस्य के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी से विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[संख्या एफ-35104(66)87-एसएस-2]

S.O. 2055.—Whereas Messrs Universal Industries, 23, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal, (MP/2073) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and due the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

JNo S 35014/66/87-SS. III

का.आ. 2056.—पैसर्स आर्डेम कैमीकेल्स, 37-ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा, भोपाल (एम पी/2030) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों आदि भी है, होने वाले सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक/वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(67)87-एस एस 2]

S.O. 2056.—Whereas Messrs. Modern Fabricators, 37-A, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023, (MP/2050) (hereinafter referred to as the said establshment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specied in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regonal Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(67)/87-SS.II]

का. आ. 2057.—मैसर्स दि एम. पी. स्टैट माइनिंग कारपोरेशन लि., प्लाट नं. 229, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (एम. पी./1445) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का (1952 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014/(68)/87 -एस. एस.-2]

S.O. 2057.—Whereas Messrs. The M. P. State Mining Corporation Limited, Plot No. 229, Zone 1, Maharana Pratap Nagar, Bhopal (M.P./1445) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insura ce Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(68)/87-SS.II]

का.आ. 2058 :—मैसर्स पिको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकलज लि., लूमिनेयर सेन्टर, पी–65, तारा टोला रोड, कलकत्ता–700088 (डब्ल्यू. बी./15706) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधीन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो,

नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014 (69) 87-/एस. एस-2)]

S.O. 2058.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited, Luminaire Centre, P-65, Tara Tolla Road, Calcutta-700088 (WB/15706) (hereinafter referred to as the establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said estblishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(69)/87-SS.II]

का. आ. 2059.—मैसर्स—एम. पी. उर्जा, विकास निगम, 10, "बी" ब्लोक, जी. टी. बी. कम्पलैक्स, भोपाल-462003, (एम. पी./5186) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकें स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी अतिक्रम की दशा उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014(70)87-एस. एस.-2]

S.O. 2059.—Whereas Messrs M. P. Urja Vikas Nigam Limited, "B" Block G.T.B. Complex, Bhopal (MP/5186) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employeee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legel heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014/70/87-SS.II]

का. आ. 2060.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स रामी एण्ड कम्पनी, 61 मदुराई रोड, तिरूचिरापल्ली-8
2. मैसर्स सुपर शेपर्स, डी-57 एण्ड 58 डवलपमेंटस, इन्डस्ट्रियल स्टेट थुवाकुडी तिरूचिरापल्ली-15
3. मैसर्स प्रभात बिविंग फैक्ट्री पोस्ट बाक्स 73, राधवेन्द्रा चेरिपर स्ट्रीट कोमरापालायाम-183, सेलम कस्बा
4. मैसर्स श्री विद्या मन्दिर हायर सैकडरी स्कूल आनन्द अमरामम मिथानूर रोड, सेलम-4
5. मैसर्स मुथ्थु कुमार इन्जिनियरिंग वर्क्स रामलिंगपुरम पोस्ट आफिस करीपट्टी (वाया सेलम-6)
6. मैसर्स आर राजन इण्डियन आयल कारपोरेशन डीलर 108, वैकटेसापुरम पेरूमवालूर त्रिची कस्बा
7. मैसर्स त्रिची इंजीनियरिंग वर्क्स डी-118, डवलपड प्लाट स्टेट धुवा कुडी, त्रिची-15
8. मैसर्स श्री लक्ष्मी विलासम प्रेस, मद्रास ट्रंक रोड, 8ए न्यू कालोनी संतूर
9. मैसर्स श्री लक्ष्मी बार्डिंग वर्क्स, 8वीं न्यू कालोनी संतूर-203
10. मैसर्स मैपको सचनैक इंजीनियरिंग कालेज, शिवाकाशी-124

11 मैसर्स श्री कृष्णकुमार काटन प्रेसिंग फैक्ट्री, 65, वालीपालायाम रोड, विचुर-601

12 मैसर्स एच. एम. हाजी मूसा, 1/69 गोदाम स्ट्रीट, मद्रास-1

13. मैसर्स पी एण्ड आई सर्विस आफ इण्डिया नं. 48, राजाजी सलाए तृतीय मंजिल, मद्रास-1

14. मैसर्स दी तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास इकोनोमिक डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., नं. 807 (पांचवीं मंजिल) अन्नासलाए, मद्रास-2

15 मैसर्स दी तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास इकोनिमक डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि., नं. 807 (पांचवीं मंजिल) अन्नासलाए, मद्रास-2

16. मैसर्स फुल्लर के० सी०पी० लि., 183 माऊन्ट रोड, मद्रास-6

17 मैसर्स इलैक्ट इन्जिनियर्स नं. 2, मुथायल रेड्डी स्ट्रीट, एलेन्दूर, मद्रास-16

18. मैसर्स मद्रास डाक लेबर बोर्ड वूमेन वैलफेयर एसोसिएशन, एम. डी. एल. बी. हाउसिंग कालोनी, टोंडीआरपैट, मद्रास-81

19 मैसर्स अयप्पा सिक्यूरिटी ब्यूरो (प्राइवेट) लि., 12, बालाजी एवेन्यू तिरूमलाए रोड, प्रथम स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-17

20. मैसर्स लक्ष्मी इलैक्ट्रीकल एन्टरप्राइजिज, 1 बैंक स्ट्रीट, लक्ष्मीपुरम क्रोमपट्टु, मद्रास-44

21. मैसर्स जैनी अपारेल्स, 44, प्रकाशन, एलाए, मद्रास-108

22. मैसर्स बाला जी सर्विसेस सेन्टर, 176 रेलवे कालोनी, मुदराई-10

23. मैसर्स कन्सोलीडेटिड पब्लिशिंग (प्राइवेट) लि., 308 नेहरू नगर, मद्रास-96 और इसका नं. 7, 5, क्राम स्ट्रीट सी आई टी कालोनी, मयलापुर, मद्रास-4 स्थित प्रशासनिक कार्यालय

24. मैसर्स कनारा एडवरटाईजिंग सर्विस, 15 जूल चर्च रोड मद्रास-4 और इसकी (1), 19/2 अन्धेरी रोड बंगलौर-27 (2) हिलफोर्ट रोड, हैदराबाद-4 (3) गोपाल-प्रभु रोड, कोचिन-35 स्थित शाखाएं

25 मैसर्स स्वीजवरो इन्स्ट्रूमेन्ट (प्राइवेट) लि., 169 सिडको इन्डस्ट्रीयल स्टेट मद्रास-98 और इसकी नं. 14 थानीथाकाचलम रोड, टी नगर, मद्रास-17 स्थित शाखा

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थानों को लागू करती है।

[संख्या एस.-35019(28)/87-एम. एस.-2)]

S.O. 2060.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Rasi and Company, 61, Madurai Road, Tiruchirapalli-8.

2. M/s. Super Shapers, D-57 and 58 Developments Industrial Estate, Thuvakudi, Tiruchirapalli-15.

3. M/s. Prabath Weaving Factory, Post Box 73, Ragavendra Chariar Street, Komarapalayam-183, Salem District.

4. M/s. Sri Vidya Mandir Higher Secondary School, Anand Asramam, Meyyanur Road, Salem-4.

5. M/s. Muthukumar Engineering Works, Ramalingapuram Post Office Karipetty (Via), Salem-6.

6. M/s. R. Rajan, Indian Oil Corporation Dealer, 108, Vemkatesapuram, Perambalur, Trichy.

7. M/s. Trichy Engineering Works, D-118 Developed Plot Estate, Thuvakudi, Trichy-15.

8. M/s. Sree Lakshmi Vilasam Press, Madras, Trunk Road, 8A New Colony, Sattur.

9. M/s. Sree Lakshmi Binding Works, 8-B, New Colony, Sattur-203.

10. M/s. Mepco Schlenk Engineer College, Sivakasi-124.

11. M/s. Sri Krishna Kumar Cotton Pressing Factory, 65, Valipalayam Road, Triuppur-601.

12. M/s. H. M. Hajee Moosa, 1/69, Godown Street, Madras-1.

13. M/s. P and I Services of India, No. 48, Rajaji Salai 3rd Floor, Madras-1.

14. M/s. The Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation Limited, No. 807, (V Floor) Anna Salai, Madras-2.

15. M/s. The Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation Limited, No. 807, (V Floor) Anna Salai, Madras-2.

16. M/s. Fuller K. C. P. Limited, 183, Mount Road, Madras-6.

17. M/s. Eltech Engineers No. 2, Muthial Reddy Street Alandur, Madras-16.

18. M/s. Madras Dock Labour Board Women's Welfare Association, M.D.L.B. Housing Colony Tondiarpet, Madras-81.

19. M/s. Ayyappa Security Bureau (Private) Limited, 12, Balaji Avenue, Thirumalai Road, 1st Street, T. Nagar, Madras-17.

20. M/s. Lakshmi Electrical Enterprises, 1, Tank Street, Lakashmipuram Chrompet, Madras-44.

21. M/s. Jeni Apparels, 44, Prakasm Salai Madras-108.

22. M/s. Balaji Service Centre, 176, Railway Colony, Madurai-10.

23. M/s. Consolidated Publishing (Private) Limited, 388, Nehru Nagar, Madras-96, including its Administrative Office at No. 7, 5th Cross Street, C.I.T. Colony, Mylapore, Madras-4.

24. M/s. Kanara Advertising Service, 15, Iuz Church Road, Madras-4 including its branches at (1) 19/2 Andree Road, Bangalore-27, (2) Hill Fort Road, Hyderabad (3) Gopala Prabhu Road, Cochin-35.

25. M/s. Swizbro Instruments (Private) Limited, 169, SIDCO, Industrial Estate, Madras-98, including its branch at No. 14, Thanickachalam Road, T. Nagar, Madras-17.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[No. S-35019(28)/87-SS.II]

का. आ. 2061.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स जनरल यूटीलिटी टैकनीकल सर्विस, 1.10.216, अशोक नगर, हैदराबाद-1
2. मैसर्स बैनसन इन्डस्ट्रीयल सिक्यूरिटी कन्सलटैन्टस, 107 पार्क लेन, सिकन्द्राबाद-3
3. मैसर्स पब्लिक स्कूल मुव्वालायनी, पालम, विशाखापट्टनम-17

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एम.-35019(30)/87-एम. एस.-2]

S.O. 2061.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. General Utility Technical Services, 1.10.216, Ashok Nagar, Hyderabad.
2. M/s. Banson Industrial Security Consultants, 107 Park Lane, Secunderabad-3.
3. M/s. Public School Muvvalavani Palam, Visakha-Patnam-17.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[S. 35019(30)/87-SS.II]

का. आ. 2062.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स लवली रबर इन्डस्ट्रीज, 163/170 गलोब कालोनी, इन्डस्ट्रीयल एरिया जालन्धर
2. मैसर्स पंजाब लेबर वैलफेयर बोर्ड, 731, फेस-3 बी आई मोहाली
3. मैसर्स पंजाब होरटीकल्चर कारपोरेशन लिमिटेड, एस. सी. ओ. नं. 309-310 सैक्टर 35-बी, चण्डीगढ़
4. मैसर्स ऐवट कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 7 ग्रीन पार्क, जालन्धर शहर और इसकी ग्राम गाजीपुर जालन्धर स्थित शाखा
5. मैसर्स स्पीडवेज टायर सर्विस, जी टी रोड, जालन्धर और इसकी मालरकोटला रोड, खन्ना स्थित शाखा

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है ।

[संख्या एस.-35019(29)/87-एस. एम.-2]

S.O. 2062.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Lovely Rubber Industries, 163/170 Globe Colony, Industrial Area, Jallandhar.
2. M/s. Punjab Labour Welfare Board, 731, Phase 3BI, Mohali.
3. M/s. Punjab Horticulture Corporation Limited, SCO No. 309-310 Sector 35-B, Chandigarh.
4. M/s. Avet Chemicals (Private) Limited, 7, Green Park, Jalandhar City, including its branch at Village Gazipur, Jalandhar.
5. M/s. Speedways Type Service, G. T. Road, Jalandhar, including its branch at Malerkotla Road, Khanna.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above-mentioned establishments.

[S. 35019(29)/87-SS.II]

शुद्धि-पत्र

का.आ. 2063 :—भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 3 जनवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 39 दिनांक 16 दिसम्बर, 1986 की दूसरी पंक्ति में ("एम. एच./3449" के स्थान पर (एम. एच./4349)" पढ़ें ।

[संख्या एम. 35014(276)/86-एम. एस.-2]

CORRIGENDUM

S.O. 2063.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 39, dated 16th December, 1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd January, 1987, in line 3 for "(MH/3449)" read "MH/4349".

[No. S-35014(276)/86-SS.II]

का.आ. 2064:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की

जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त हों, अर्थात् :—

"जिला आनन्तपर में आनन्तपुर राजस्व मण्डल के आनन्तपुर टाऊन की नगर सीमाओं और राजस्व ग्राम पापमपेट, कल्कालापप्पल्ली, ए-नारायणपुरम सोमा नाडोडी, और आनन्तपुर ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/23/87-एस.एस-1]

S.O. 2064.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The areas within the Municipal limits of Anantapur Town and also the revenue villages of papampet, Kakkalapalli, A-Narayanapuram, Somanododdi and Anantapur rural in Anantapur revenue mandal in Anantapur District."

[No. S-38013/23/87 SS-I]

का. आ. 2065:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र मे प्रवृत्त हों, अर्थात् :—

"रंगा रेड्डी जिले में मडचल राजस्व मण्डल के राजस्व ग्राम मेडचल गुन्डुलापोचम्पाल्ली और कन्दला कोई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/26/87-एस-एस-1]

S.O. 2065.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The area within the revenue Villages of Medchal Gundlapochampalli and Kandiakoi under Medchal revenue mandal in Ranga Reddy District."

[No. S-38013/26/87-SS.I]

679 GI/87—16

का. आ. 5966:—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त कि जा चुकी है] के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला मदक में पारनचरू राजस्व मण्डल के राजस्व ग्राम मथान्गी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

[संख्या एस-38013/24/87-एस.एस.-1]

S.O. 2066.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"The area within the revenue village of Muthangi under Patancheru revenue mandal in Medak District."

[No. S-38013/24/87-SS. I]

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का.आ. 2067 :—मैसर्स ट्रावनकोर टिटानियम प्राडैक्टस लि., कोचवली, तिवेन्द्रम-695021 (के.आर./167) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिय जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरला को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप मे वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरला के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(93)/87-एस.एस.-2]

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 2067.—Whereas Messrs. Travancore Titanium Products Limited, Kochuveli, Trivandrum-695021 (KR/167) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employee than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits of the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/93/87-SS-II]

का. आ. 2068—मैसर्स मैकमेट इंडिया प्रा. लि. 27—बी, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता—700016 (डब्लू. बी./24973) और इसकी इसी कोड नं. के अंतर्गत आने वाली शाखाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायगा।

4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का य उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उप-

लब्ध फायदों से अधिक अनुकूल हो जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते । बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014 (92)/87-एसएस-2]

S.O. 2068.—Whereas Messrs Macmet India Private Limited, 27-B, Camac Street, Calcutta-700016 (WB/24973) and its branches covered under the same code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is ligely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/92/87-SS-II]

का०आ० 2069.—मैसर्स भोपाल दुग्ध संघ सहकारी मर्यादित हबीबगंज भोपाल (एम.पी./3305) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होने बीमा वायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का

संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(91)/87-एसएस-2]

S.O. 2069.—Whereas Messrs Bhopal Dugdh Sangh Sahakari Manjadit Hobibganj, Bhopal (MP/3305) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such focilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the, Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of he Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/91/87-SS-II]

का. आ. 2070.—मैसर्स रासी सिमेन्ट लि., पो. बो. नं. 1805, 1-10-125, अशोक नगर हैदराबाद (अ. प्र.) (ए. पी./12877) और (ए. पी./13143) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधिन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हैदराबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदों से अधिक अनकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014(90)/87-एस. एस.-2]

S.O. 2070.—Whereas Messrs Rassi Cement Limited, P.B. No. 1805, 1-10-125, Ashok Nagar, Hyderabad (A.P.) (AP/12877 and AP/13143) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall imediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessory premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is ligely to affect adversely the Interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/90/87-SS-II]

का. आ. 2071.—मैसर्स प्रैस्टीज फिड्ज मिल्ज, 30, ज्योरा कम्पाऊड, इन्दौर (एम. पी./3821) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक/वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम, निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार-नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम. 35014(89)/87-ए,म एस० -2]

S.O. 2071.—Whereas Messrs. Prestige Feed Mills, 30, Jaora Compound, Indore (MP/3821) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

679 GI/87—17

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts able approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/89/87-SS-II]

का. आ. 2072—मैसर्स जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी (म प्र) (एम/पी./1090) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे

उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशि भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे कियेगये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माम के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(88)/87-एस.एस-2]

S.O. 2072.—Whereas Messrs Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Shivpuri (MP) (MP/1090) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses, involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provindent Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is ligely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reason able opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme, but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/88/87-SS-II]

का.आ. 2073 :—मैसर्स–टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., 7, बड स्ट्रीट, कलकत्ता (डब्ल्यू.बी./14964) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध सुविधाओं में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन, के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत, होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के छः मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/87/87-एस. एस-II

S.O. 2073.—Whereas Tea Trading Corporation of India Limited, 7, Wood Street, Calcutta-700016 (WB/14964) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses, involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibilty for payment of assurance benefits to the nommees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemptibn, shall be that of the employer

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nommee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

[No S 35014/87/87-SS II]

का आ 2074 —मैसर्स रवि इन्जीनियरिंग वर्क्स प्लाट न 3, इण्डस्ट्रीयल ऐस्टेट, गोविन्दपुरा भोपाल (एम पी /5271) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिय जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सदाय किय बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओ का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमे सशोधन किया जाय, तब उस सशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसख्या की भाषा म उसकी मख्य बातो का अनुवाद स्थापन के सूचनापटट पर प्रदर्शित करेगा ।,

5 यदि कोई ऐसा कमचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा मे सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी सशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा किसी सशोधन स कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पोलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते; बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(86)/87-एस.एस-II]

S.O. 2074.—Whereas Messrs Ravi Engineering Works, Plot No. 3, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal (MP/5271) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charge etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme, are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/86/87-SS.II]

का. आ. 2075.—मैसर्स क्वालिटी इन्जिनियरिंग एण्ड इन्सूलेशन प्रोडक्ट, 71-ए, इण्डिस्ट्रयल एस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (एम. पी./2056), (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 की 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्यों के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा, स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों का विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/(85)/87-एस. एस-2]

S.O. 2075.—Whereas Messrs Quality Engineering & Insulation Product, 71-A Industrial Estate, Govindpura, Bhopal-462023(MP/2056) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immeiately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No S-35014/85/87-SS II]

का. आ. 2076.—मैसर्स-दि जोधपुर सेन्ट्रल को. औ. बैंक लि., मनिहार का हत्था, मन्डोर रोड, जोधपुर-342006, (आर. जे/840), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन दिया है।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप का फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और

उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(84)/87-एस. एस.-2]

679GI/87—18

S.O. 2076.—Whereas, Messrs The Jodhpur Central Co-operative Bank Limited, Manji Ka Hatha, Mandor Road, Jodhpur-342006 (RJ/840) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved b the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(84)/87 SS.II]

का. आ. 2077.—; मैसर्स पहवा इण्डस्ट्रीज, ए-17 से 20 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, जोधपुर (आर.जे./1895), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाये प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओ का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों मे कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(83)/87-एस.एस-2)]

S.O. 2077.—Whereas Messrs, Pahwa Industries, A-17 to 20 Industrial Estate, Jodhpur (RJ/1895) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/83/87-SS. II]

का.आ. 2078.—मैसर्स न्यू इरा इण्टरप्राइज, 23-बी, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरी भोपाल-462023 (एम. पी./3649) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन

रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4 नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उप सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(82)/87-एस.एस-2)]

S.O. 2078.—Whereas Messrs, New Era Enterprise, 23-B, Industriaf Estate, Govindpura, Bhopal Pin. Code 462023 (MP|3649) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct

under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/82/87-SS-II]

का.आ. 2079.—मैसर्स—जोधपुर बार्ड्स, 16-बी, 111, हैवी इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर (आर जे./2944) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप

से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014

S.O. 2079.—Whereas Messrs, Jodhpur Wires, 16-B-III, Heavy Industrial Area, Jodhpur (RJ|2944) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

[No. S-35014/ 81)/87-SS III]

का. आ. 2080.—मैसर्स—तमिल नाडु को-ओपरेटिव स्टेट लैड डिवलपमेंट बैंक लि., मद्रास-600004 और इसकी इसी कोड नं. के अन्दर आने वाली सभी शाखाएं (टी-गन-/4152) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमे संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक द्वारा स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(80)/87-एस.एस.-2]

S.O. 2080.—Whereas Messrs Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Limited, Madras-600004 (TN/4152) and its branches covered under the same code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance, premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(80)/87-SS-II]

का० आ० 2081:—मैसर्स राजा एग्रो सर्विस सेन्टर, गाईन एरिया, सिमोगा 577201 (के० एन०/7872) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय, समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/79/87-एम०एस-2]

S.O. 2081.—Whereas Messrs Raja Agro Service Centre, Garden Area, Simoka-577201 (KN|7872) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A)) of Section 17 of

the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Governemnt hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance, Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feautres thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as

already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No S. 35014/79/87-SS. II]

का० आ० 2082.—मैसर्स दि साऊथ इण्डियन एक्सपोर्ट कं० प्रा० लि० मैसूर बैंक बिल्डिंग, 231, एन०एस०सी० बोस रोड, मद्रास (टी०एन०/2313) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप धारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उक्त की मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मद्रास के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014(78)87 एस०एस०-2]

S.O. 2082.—Whereas Messrs The South Indian Export Company Private Limited, Mysore Bank Building, 231, N.S. C. Bose Road, Madras-600001 (TN/2313) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that

he benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by ub-section (2A) of section 7 of the said Act and subject to he conditions specified in the Schedule annexed hereto, he Central Governemnt hereby exempts the said establishment rom the operation of all the provisions of the said Schems or a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall ubmit such returns to the Regional Provident Fund Com-nissioner Tamil Nadu and maintain such accounts and rovide such facilities for inspection, as the Central Govern-nent may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under lause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said ct, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the roup Insurance Scheme, including maintenance of accouts, ibmission of returns, payment of insurance premia, transfer f accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne y the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the tablishment, a copy of the rules of the Group Insurance cheme as approved by the Central Government and, as id when amended, alongwith a translation of the salient atures thereof, in the language of the majority of the nployees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the mployees' Provident Fund or the Provident Fund of an tablishment exempted under the said Act, is employed in s establishment, the employer shall immediately enrol him a member of the Group Insurance Scheme and pay neces-ry premium in respect of him to the Life Insurance Cor-oration of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits ailable to the employees under the Group Insurance cheme appropriately, if the benefits available to the em-oyees under the said Scheme are enhanced, so that the nefits available under the Group Insurance Scheme are ore favourable to the employees than the benefits admis-ble under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu-nce Scheme, if on the death of an employee the amount yable uder this Scheme be less than the amount that ould be payable had employee been covered under the id Scheme, the employer shall pay the difference to the gal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance heme, shall be made without the prior approval of the gional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu d where any amendment is likely to affect adversely the terest of the employees, the Regional Provident Fund ommissioner shall before giving his approval, give a reaso-ble approval give a reasonable opportunity to the em-oyees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said es-blishment do not remain covered under the Group Insu-ice Scheme of the Life Insurance Corporation of India as eady adopted by the said establishment, or the benefits the employees under this Scheme are reduced in any nner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the emium etc. within the due date, as fixed by the Life urance Corporation of India, and the policy is allowed lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for pyment of assu-rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014/78/87-SS. II]

का०आ० 2033 — मैसर्स यूनाइटिड इलक्ट्रिकल्स, 17-डी, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा भोपाल (एम०पी०/4892) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन, बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/77/87-एस. एस-2]

S.O. 2083.—Whereas Messrs. United Electricals, 17-D, Industrial Area, Govind Pura, Bhopal (MP|4892)) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 7 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feautres thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas on employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits avaiable under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be pavable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014|77|87-SS. II]

का. आ. 2084.—मैसर्स टेस्ला ट्रांसफार्मरज प्रा. लि., 30-बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (एम. पी./2057) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदें बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदें उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (76)/87-एस.एस-2]

S.O. 2084.—Whereas Messrs. Tesla Transformers Private Limited, 30-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (MP|2057) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient feautres thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the bene available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014|76|87-SS. II]

का. आ. 2085:—मैसर्स-पिकी इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि., 7 जस्टीस चन्दरा मदावरोड, कलकत्ता-20 (डब्लू. बी./5179) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों, का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचन[illegible] पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका

है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस–35014 (75)/87–एस. एस-2]

S.O. 2085.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals, Limited, 7, Justice Chandra Modhab Road, Calcutta-700020 (W.B./5179) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establismenht are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(75)/87-SS.II]

का. आ. 2086:—मैसर्स सुपर स्पिनिंग मिल्स लि., ए-यूनि हिन्दुपुर, आन्ध्र प्रदेश (ए. पी./2678) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (74) 87-एस. एस-2]

S.O. 2086.—Whereas Messrs Super Spinning Mills Limited, A-Unit Kirikera-Hindupur, Andhra Pradesh (AP/2678) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government may, from time to time, direct under from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Andhra Pradesh, and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insur- opportunity to the employees to explain their point of view.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceasd members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(74)/87-SS.II]

का आ 2087:—मैसर्स गोमथी स्पीनर्ज बंगारूपलम 517416, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश (ए. पी /13177) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीस वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपेक्षित अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014 (73) 87-एस. एस-2]

S.O. 2087.—Whereas Messrs Gomathy Spinner Bangarupalyam-517416, Chittoor Distt, Andhra Pradesh (AP/13177) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of, all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of daftult, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(73)/87-SS.II]

का.आ. 2088.—मैसर्स समृद्धा इन्डस्ट्रीज, 6/1, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म प्र) (एम. पी./1624) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है :

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा

[संख्या एस-35014 (72)/87-एस. एस -2]

S.O. 2088.—Whereas Messrs Narmada Industries, 6/1, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal (M.P.) (MP/1624) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employee in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure

prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S. 35014(72)/87-SS.II]

का.आ. 2089.—मैसर्स डेवी एशमोर इन्डिया लि., 6 ए, मिडलटन स्ट्रीट कलकत्ता 700001 (डब्ल्यू. बी./11265) और इसकी शाखाएं जो कोड नं. के अधीन कवरड हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड क अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते तो बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस.-35014 (71) 87-एस. एस. 2]

. क. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 2089.—Whereas Messrs Davy Ashmore India Limited, 6-A, Middleton Street, Calcutta-700001 (WB/11265) and its branches covered under the same code No. (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (4A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

[No. S-35014(71)/87-SS.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का. आ. 2090.—सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 (1981 का 50) की धारा 2 के खंड (घ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित जम्मू और कश्मीर सरकार के अधिकारी को उक्त सारणी के कालम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र
1 श्रम आयुक्त	समस्त जम्मू और कश्मीर राज्य

[सं. एस-61011/5/87-डी-1 (ए) (i)]

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2090.—In pursuance of clause (d) of section 2 of the Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981 (50 of 1981), the Central Government hereby authorises the officer of the Government of Jammu and Kashmir mentioned in column (1) of the Table below, to perform the functions of the competent authority under the said Act for the area specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :—

TABLE

Designation of the Officer	Area
1 Labour Commissioner	Whole of Jammu & Kashmir State

[No. S-61011/5/87-D.I(A)(i)]

का. आ. 2091 :—सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन), 1981 (1981 50) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित जम्मू और कश्मीर सरकार के अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संशोधन अधिकारी नियुक्त करती है :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र
1	2
1 सहायक श्रमायुक्त, श्रीनगर	जिला श्रीनगर
2 सहायक श्रमायुक्त अनतनाग	जिला अनंतनाग
3. सहायक श्रमायुक्त, बारामुल्ला	जिला बारामुल्ला
4. सहायक श्रमायुक्त, कुपवाड़ा	जिला कुपवाडा
5 सहायक श्रमायुक्त, जम्मू	जिला जम्मू
6. सहायक श्रमायुक्त, ऊधमपुर।	जिला ऊधमपुर
7. सहायक श्रमायुक्त, कथुआ	जिला कथुआ
8 सहायक श्रमायुक्त पुछ	जिला पुछ
9. सहायक श्रमायुक्त, राजौरी	जिला राजौरी
10. सहायक श्रमायुक्त, डोडा	जिला डोडा
11. सहायक श्रमायुक्त, लेह	जिला लेह
12. सहायक श्रमायुक्त, कारगिल	जिला, कारगिल

सं. [एस-61011/5/87-डी-1 (ए) (ii)]

नन्द लाल, अवर सचिव

S.O. 2091 In exercise of the powers conferred by section 4 of the Cine-Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981 (50 of 1981), the Central Government hereby appoints the Officers of the Government of Jammu and Kashmir mentioned in Column (1) of the Table below to be Conciliation Officers for the purposes of the said Act, for the area specified in the corresponding entry in Column (2) of the said Table:—

TABLE

Designation of the Officer	Area
1. Assistant Labour Commissioner, Srinagar.	Srinagar District
2. Assistant Labour Commissioner, Anantnag.	Anantnag District.
3. Assistant Labour Commissioner, Baramulla.	Baramulla District.
4. Assistant Labour Commissioner, Kupwara,	Kupwara District.
5. Assistant Labour Commissioner, Jammu.	Jammu District.
6. Assistant Labour Commissioner, Udhampur.	Udhampur District.
7. Assistant Labour Commissioner, Kathua.	Kathua District.
8. Assistant Labour Commissioner, Poonch.	Poonch District.
9. Assistant Labour Commissioner, Rajouri.	Rajouri District.
10. Assistant Labour Commissioner, Doda.	Doda District.
11. Assistant Labour Commissioner, Leh.	Leh District.
12. Assistant Labour Commissioner, Kargil.	Kargil District.

[No. S-61011/5/87-D.I(A)(ii)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का. आ. 2092 :—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अवर सचिव, उत्प्रवास प्रभाग, नई दिल्ली को, अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. जेड-11025/30/87-उत्प्रवास-II]

ए० वी० एस० शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2092.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Under Secretary, Emigration Division, New Delhi to grant previous sanction for prosecution of any person in respect of any offence under the Act.

[No. Z-11025(30)/87-Emig.II]

A. V. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

का० आ० 2093:—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, मद्रास में सहायक श्री आर० सुन्दरलाल को दिनांक 17-6-1987 को उत्प्रवास संरक्षी, मद्रास के सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया है।

[संख्या ए० 22012/1/86 उत्प्रवास II)]

ए०वी०एस० शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 27th July, 1987

S.O. 2093.—In exercise of the power conferred by Section of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government authorised Shri R. Sundar Lal, Assistant in the office of Protector of Emigrants, Madras, to perform all function of Protector of Emigrants, Madras on 17-6-1987.

[No. A-22012|1|86-Emigration-II]

A. V. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1987

का.आ. 2094.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग हिन्डन गाजियाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2094.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. Hindon Ghaziabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 26/86

In the matter of dispute between :

Shri Barkat Ram, Assistant Operator (E&M), 11088, Motia Khan, Gali Pippal Wali, Delhi.

Versus

The Executive Engineer, Central Electrical Sub-Division-I, Hindon Ghaziabad, C.P.W.D.

APPEARANCES :

Shri B. K. Aggarwal—for the workman.

Shri Narinder Chaudhary—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-42012/40/85-D.II(B) dated 6th January 1986 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Executive Engineer Electrical for Hindon Central Electrical Sub-Division-I, CPWD, in refusing Shri Barkat Ram, Assistant Operator, to resume duty from 1st February, 1980 is legal and justified. If not to what relief the concerned workmen is entitled to ?"

Some of the undisputed facts are that the workman Shri Barkat Ram joined service with the Management as Assistant Operator on 24th February, 1967; that he was made semi-permanent w.e.f. 1st September, 1969 and was working under the Control and charge of the Electrical Division Hindon Sub-Division-I CPWD Ghaziabad; that the workman did not perform duty from 1st June, 1969 to 31st Jan. 1980; that the workman reported for duty on 1st February, 1980 and submitted a medical certificate but was not allowed to join duty; that a charge sheet was served on the workman on 30th August, 1982 to which the workman submitted his reply dated 10th September, 1982; that a domestic enquiry was ordered against the workman and the first hearing was held on 29th December, 1983 and that the workman was allowed to join his duties w.e.f. 13th March, 1986.

3. Since the workman has admittedly been allowed to join duty w.e.f. 13th March, 1986 the dispute now boils down to the payment of back wages and the continuity of service from 1st February, 1980 to 12th March, 1986. At the outset, it may be observed that the very fact that the Management has allowed the workman to join duty w.e.f. 13th March, 1986 amounts to admission that the earlier action of the Management in not allowing the workman to join duty w.e.f. 1st February, 1980 was clearly wrong. Rule 19(1) of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 stipulates that an application for leave on medical certificate made by non-gazetted government servant shall be accompanied by a medical certificate, in form IV given by an authorised medical attendant or a registered medical practitioner. Sub-Rule 3 of rule 19 further provides that the authority competent to grant leave may at its discretion secure a second medical opinion by requesting a government medical officer not bellow the rank of Civil Surgeon or Staff Surgeon to have the applicant medically examined on the earliest possible date. Now it is admitted that the workman had filed a medical certificate from a registered medical practitioner at the time of submitting joining report on 1st February, 1980. Thus the only curse open to the competent authority was either to accept medical certificate produced by the workman or to secure second medical opinion by requesting a Government Medical Officer to have the applicant medically examined on the earlier possible date. MW1 Shri K. K. Verma, X.En. CPWD. Hindon Central Electrical Division Ghaziabad has stated in cross-examination that the workman was asked to produce medical certificate from Government Doctor the moment he had produced medical certificate from Private Practitioner. No written order was given and that the workman was not asked to appear before any particular Government Doctor by a specific order. This was clearly contrary to Sub-Rule 3 of Rule 19 ibid because it was for the competent authority to secure a second medical opinion by requesting a Government Medical Officer to examine the applicant and the applicant could not have been asked to produce certificate from the Government Medical Officer. The Government of India have given detailed instructions under Rule 11 in Part I of the C.C.S. (CCA) Rules as to how the unauthorised absence of the employee is to be treated. It has been suggested that the employee found to be an unauthorised absence, should be asked to rejoin duty within a specific period. However, no such letter was issued by the Management in the case of the workman. It has further been suggested that if an employee reports for duty during disciplinary proceeding even then he should be allowed to join duty. In the present case the workman had reported for duty on his own even before the initiation of any disciplinary proceedings and he should have been allowed to join duty and then suitable disciplinary action taken against him under the rules if considered necessary. However, the Management was clearly in the wrong in refusing the workman to join duty w.e.f. 1st February, 1980. It has been held in 1984 (2) S.L.R. 163 Kerala that putting an employee off duty without any enquiry and non-payment of salary for an unduly long period is mala fide and unauthorised. ar[illegible] deemed to be in service at all [illegible] to all benefits officially or otherw[illegible] the workman was wrongly refused [illegible] 1980 and the Management did no[illegible] ver till 30th

August, 1982 when a chargesheet was served. Even then the enquiry was unduly prolonged and the first hearing was held only on 29th December, 1983 The request of the Management that it may be allowed to continue with the enquiry on the charge sheet dated 30th August, 1982, must be declined because the Management failed to follow the rules and seek second medical opinion which was possible only on 1st February, 1980 when the workman had reported for duty and it is too late in the day now to seek a second medical opinion. Under the circumstances, it is held that the action of the Management in refusing the workman to resume duty from 1st February, 1980 was not justified The workman, is, therefore, entitled to full back wages with continuity of service for the period upto 12th March, 1986 and the reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

[No. I-42012/40/85-D II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1987

का.आ. 2095.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मोहन कोलियरी और वेस्टर्न कोल फील्डस लि., पोस्ट मुनारदेव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 24th July, 1987

S.O. 2095.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Mohan Colliery of WC Ltd., P.O. Junnardeo, District Chhindwara (M.P.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT/LC(R)(31)/86

PARTIES :

Employers in relation to the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, P.O. Junnardeo, District Chhindwara and their workman Shri I. U. Chisty, Leave Clerk, Datla East Colliery P.O. Junnardeo, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management—Shri P. S. Nai, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines. DISTRICT : Chhindwara (M.P.)

AWARD

Dated, the 2nd July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-22012(46)/85-D. V, dated the 10th February, 1986 :

"Whether the action of the management of Mohan Colliery of Western Coalfields Limited, P.O. Junnardeo, District Chhindwara (M.P.), in dismissing Shri I. U. Chisty, Leave Clerk from 3rd July, 1981 is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

This case was registered on 24th February, 1986. Thereafter parties filed their respective pleadings Workman raised certain preliminary points. After hearing both the parties I passed a detailed order on 8th April, 1987 and held that the domestic enquiry was not fair and just. The case was then fixed for filing documents on merit. But the patties have filed settlement before me which is duly signed by parties and verified on behalf of the management by Shri P. S Nair Advocate.

I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual just and fair and in the interest of the workman.

I, therefore, pass award in terms of the settlement which are as follows :—

1. It was agreed that Shri I. U. Chisti will be taken back in employment as Clerk Gr. II and he will be posted in any of the units of Kanhan Area.

2. It was agreed that the period of idleness from 3rd July, 1981 to the date of employment will be treated as dies-non i.e. 'No work, No pay' basis However, the said period will be counted for the limited purposes of continuity for gratuity payment.

3. It is further agreed that he will be allowed notional fixation with incremental benefits but no arrear for the above period will be paid While fixing him notionally, the last basic pay drawn by him will from the basis for subsequent increments and benefits accruing on account of fixation in NCWA-III.

4 It was agreed that action will not be taken against Shri Chisti on the basis of any other charge-sheets pending against him as on date

5. In view of the above, he has agreed to give up all other claim/benefits and accept the above terms as full and final settlement and shall not claim any other benefit in respect of the matter in dispute.

6. It was agreed that this settlement shall not be treated as precedent in any other case.

7 The parties agreed to file compromise settlement before the Presiding Officer, C.G.I.T., Jabalpur and request for an Award in terms of the settlement.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No L-22012/46/85-D. V]

का.आ. 2096.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, रावनवारा ग्रुप आफ माईनस, ऑफ वेस्टर्न कोल फील्डस लि., पोस्ट परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2096.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Rawanwara Group of Mines of of W.C.L.P.O. Purasia, District Chhindwara (M.P) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT JABALPUR

Case No. CGITLC(R)(89)|86

PARTIES :

Employers in relation to the management of Pench East Incline of Rawanwara Khas Colliery of W.C.L. Pench Area, P.O. Parasia, District-Chhindwara and their workmen Shri Ratanlal, Attendance Clerk represented through the General Secretary, BKKMS (BMS), P.O. Chandametta, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Workmen—None.

For Management—Shri Rajendra Mohan, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Chhindwara (M.P.).

AWARD

Dated the 2nd July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-22012|21|86-D.V. dated the 24th October, 1986.

"Whether the action of the management of Pench East Incline of Rawanwara Khan Colliery of WCL Pench Area, P.O. Parasia, District—Chhindwara in dismissing Shri Ratanlal, Attendance Clerk from service with effect from 25-3-84 is justified ? If not, what relief the concerned workman is entitled to ?"

This case was registered on 8th December, 1986. Thereafter parties contested the dispupte by filing their respective statement of claim. The case was fixed for filing documents and issues but the parties have filed settlement duly signed by them and verified on behalf of the management by Shri P. S. Nair, Advocate.

I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual, lawful and in the interest of the workmen.

I therefore, pass award in terms of the settlement which are as under :—

1. It is agreed by the management to reinstate Shri Ratanlal ex-clerk at Shivpuri No. 2 Mine in Pench Area. He shall report for duty to Manager Shivpuri No. 2 Mine within one month from the date of the settlement.

2. The period of absence from the date of dismissal to the date of joining will be treated as dies-non.

3. Shri Ratanlal will not be entitled to wages for any other payment whatsoever for the period of idleness from the date of dismissal to the date of reinstatement.

4. On reinstatement Shri Ratanlal will be kept on probation for a period of one year during which period his performance and conduct will be closely watched. An assurance of good performance and conduct will be furnished by the workman in writing before joining the duties. If performance and|or conduct during the probation period is not found satisfactory, his services will be liable to be terminated. However, if his performance and conduct during the probation period are found satisfactory the management may consider to grant him continuity of service for the limit purpose of payment of gratuity.

5. The Union|workman agreed to drop all other claims| benefits in respect of the matter under dispute.

6. This settlement settles the dispupte fully and finally and it shall not be treated as precedent if any other case.

7. The parties agree to file the compromise settlement before the Presiding Officer, CGIT Jabalpur and request for an Award in terms of the settlement.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. L-22012|21|86-DV]

का.आ. 2097—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सब-एरिया नं. II, घुगुस कोलियरी, मैसर्स वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि., डाकघर घुगस, जिला-चन्द्रापुर (महाराष्ट्र) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2097.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispupte between the employers in relation to the management of Sub-Area No. II, Ghugus Collieries, M|s. W.C. Ltd P.O. Ghugus, District Chandrapur (M.S.) and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V.S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT|LC(R)(70)|1987

PARTIES :

Employers in relation to the management of M|s. Western Coalfields Limited in Sub Area No. II, Ghugus Colliery, P.O. Ghugus, District-Chandrapur (M.S.) and their workman Shri Premdas Sadashiv Kamble C|o Murlidhar Durve, Behind Janta Junior College, P.O. Ghugus, Tahsil & District-Chandrapur.

APPEARANCES :

For Workman—Shri Premdas Sadashiv Kamble.

For Management—Shri Rajendra Menon, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Chandrapur (M.S.)

AWARD

Dated the 1st July, 1987

The Central Government in exercise of its powers under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication, vide Notification No. L-21012|13|86-D.III(B), dated 26th May, 1987.

"Whether the action taken by the management of M|s. Western Coalfields Limited in Sub Area No. II, Ghugus Colliery, P.O. Ghugus, District Chandrapur (MS) is justified in terminating the services of the workman Shri Premdas Sadashiv Kamble with effect from 20-6-1985 ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?"

This case was registered on 8th June, 1987. Thereafter parties were to file statement of claim. Parties have filed settlement before me which is duly verified and accepted on behalf of the management by Shri R. K. Singh and on behalf of the workman himself.

I have gone through the settlement and I find that the settlement is mutual, lawful and in the interest of the workman.

I therefore, pass award in terms of the settlement and answer the reference as follows :—

1. Shri P. S. Kamble will be reinstated on the same post held by him at the time of termination.

2. The period of absence from the date of termination to the date of joining will be treatd as dies-non i.e. "No Work no Pay".

3. The workman will not be entitled to wages or any other payment whatsoever for the period of idleness from the date of his termination to the date of his reinstatement|joining his duties.

4. On reinstatement Shri P. S. Kamble will be kept on probation for a period of one year during which his attendance performance and conduct will be closely watched. An assurance of good performance, conduct and punctuality will be furnished by the workman before joining the duties. If performance conduct during the probation period is not found satisfactory, his services will be liable to be terminated. However, if his performance and conduct during the probation period are found satisfactory the management may consider to grant him a continuity of service for the limited purpose of payment of gratuity.

5. The posting of Shri P. S. Kamble shall be decided by the management.

6. The workman will be allowed to join duty within the period of one month of signing the Memorandum of settlement.

7. Both the party agreed to settle the dispute on the above terms and conditions; and the Memorandum of settlement will be submitted to the Ministry for closing the case once for all.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. L-21012|13|86-D.III(B)]

का.आ. 2098—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2098.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI V. S. YADAV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT|LC(R)(97)|1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Dhanpuri Open Cast Mines, P.O. Amlai Colliery, District Shashdol (M.P.) and their workmen represented through the Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor Sabha, Sohagpur Area, P.O. Dhanpuri, District Shahdol (M.P.).

APPEARANCES :

For Workmen —Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Shahdol (M.P.)

AWARD

Dated, 3rd July, 1987

This is a reference made by the Central Government in the Ministry of Labour by Notification No. L-22012(16)|85-D.V. dated 31-10-85 1st Nov. 85 for adjudication of the following dispute :

"Whether the dismissal of S|Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh, S. K. Kayoom and Ambika Prasad Chowbey, Elect. Helper, Mining Sirdar, Fitter and Dumper operator respectively of Dhanpuri Open cast Mines from services with effect from 24-9-84 by the General Manager, Sohagpur Area of Western Coalfields Limited P.O. Dhanpuri District Shadol is justified ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled for ?"

2. Non-controversial facts of the case are that on behalf of the management it was alleged that on 5-1-1984 at about 11.30 A.M. Shri S. K. Kayoom along with S|Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh and Ambika Prasad Chowbey and more than about 30 workers gherаod the Sub-Area Manager and abused him. They also threatened to kill him. On the basis of the said allegation chargesheets dated 6-1-1984 were issued to them in the following words :—

"It has been reported to the undersigned as under :— That on 5-1-84 at about 11.30 A.M. you along with S|Shri S. K. Kayoom, Fitter, Kanta Singh, Mining Sirdar and Shatrughan Pandey, Elec. Helper instigated a mob of about 30 workers while on duty hours and gheraod Shri Birbal Kapoor, Sub-Area Manager upto 1.30 P.M. You also abused him in a most filthy language which is reproduced below :—

"MADARCHOD-BETI CHOD" VAGAIRAH VAGAIRAH.

You also threatened to kill him if he does not sign the papers produced by Shri Kayoom, Inspite of the resistance, you forced him to sign by catching hold of his hand and as such you have obstructed him to discharge his official duties which constitutes a maior misconduct under the standing orders applicable to you which reads as under :—

17(i)(e)—Drunkness, fighting or riotous, disorderly or indecent behaviour while on duty at the place of work.

17(i)(p)—Leaving work without permission or sufficient reasons.

17(1)(c)—Any breach of the Mines Act, 1952, or any other Act or any rules, regulations or bye-laws thereunder or of any standing orders.

17(i)(r)—Threatening, abusing or assaulting any superior or co-worker."

The wor men replied to the show cause notice but it was not found satisfactory by the management. Therefore it decided to hold departmental enquiry and appointed Shri D. H. Goswami as an Enquiry Officer. Notice of enquiry was served on the workmen and they attended the enquiry with their co-worker. The enquiry against the four of the workmen was held jointly. After the necessary enquiry Enquiry Officer submitted his report finding the charges proved. Management passed orders dismissing the workmen from their services on the basis of the enquiry report, hence these proceedings. The management has supported the enquiry and findings of the Enquiry Officer and punishment awarded.

They also prayed that in case enquiry is vitiated the management be permitted to prove the misconduct on merits before this Tribunal.

3. The workmen have challenged the enquiry findings and the punishment awarded to them on various grounds which will be taken up while deciding the issues.

4. I framed the following issues and treated Issue Nos. 1 to 3 as preliminary issues. My findings with reasons on preliminary issues are as under :—

ISSUES

1. Whether the enquiry is proper and legal ?
2. Whether the management is entitled to lead evidence before this Tribunal ?
3. Whther the punishment awarded is proper and legal ?
4. Whether the termination of the workman is justified on facts of the case ?
5. Relief and costs ?

FINDINGS WITH REASONS :

5. Issue Nos. 1, 2 and 3.—Parties submitted their written arguments. In their written arguments workmen have only pressed certain grounds to show that the enquiry is vitiated. Firstly it has been contended as a preliminary objection that the Western Coalfields Limited i.e. the management has no specific Standing Orders certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (hereinafter referred to as the Act of 1946) Therefore the enquiry is vitiated on this ground alone.

6. Next it has been contended that before the Nationalisation of the Burhar and Amlai Collieries of Rewa Coalfields Ltd. they were governed by their Standing Orders of the Company. After Nationalisation new Company has been formed. Therefore the action taken by the management on the basis of non-existing Company's standing order is illegal. It has been further contended that the management has not sought any permission or submitted any Draft Standing Orders, therefore the Model Standing Orders will not be applicable to the present case. Therefore the charge-sheet issued and domestic enquiry held and findings and punishment given on the basis of Model Standing Orders are illegal and the enquiry is vitiated.

7 On the other hand, on behalf of the management it has been contended that admittedly the present workmen were appointed prior to the Nationalisation and at that time they were governed by the Standing Orders of Rewa Colliery but after Nationalisation Rewa Coalfields were taken over by the management of Western Coalfields Limited and there being no certified Standing Orders of W.C. Ltd, management has taken action on the basis of Model Standing Orders and it is not necessary to take any permission to make the Model Standing Orders applicable as is apparent from Section 13A of the Act of 1946. I am of the opinion that the Act of 1946 nowhere lays down that any prior approval or permission is required for adopting of Model Standing Orders. It is true that as per Section 3 of the Act of 1946 within six months from the date of the Act becomes applicable to an industrial establishment the employer is required to get the Standing Orders certified. But admittedly the W.C. Ltd. did not get any such Standing Orders certified Therefore in the absence of such certification proivsion of Section 12-A of the Act of 1946 which is reproduced below will apply

"12-A Temporary application of model standing orders.—

(1) Notwithstanding anything contained in Section 3 to 12 for the period commencing on the date on which this Act becomes applicable to an industrial establishment and ending with the date on which the standing orders as finally certified under this Act come into operation under Section 7 in that establishment, the prescribed model standing orders shall be deemed to be adopted in that establishment, and the provisions of Section 9, sub-section (2) of section 13 and Section 13-A shall apply to such standing orders as they apply to the standing orders so certified

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to an industrial establishment in respect of which the appropriate Government is the Government of the State of Gujarat or the Government of the State of Maharashtra."

The above provision clearly says that notwithstanding anything contained in Sec. 3 to 12 the model standing orders shall be deemed to be adopted in the establishment in the intervening period. It speaks of no prior approval or permission as contended by the Learned Counsel for the workmen.

8 Learned Counsel for the workmen has also relied on the case of Western India Match Company Ltd Vs. Their workmen (reported in AIR 1973-Not page 531, but page 2650). I have gone through the authority and I find that nowhere it supports the contention of the workmen that the model standing orders will not apply unless prior permission or approval is sought for the Standing Orders. In fact, Hon'ble Judge of our own High Court of Madhya Pradesh in the case of Sakhrullah Khan Nasrullah Khan Vs. State Industrial Court, Indore and others (MPLJ 1978 p. 455) have held that model Standing Orders under Sec. 12-A are applicable till the Standing Orders are got certified.

9 Learned Counsel for the workmen had further contended that the charge nowhere mentions which particular Standing Orders were contravened by the workmen. Therefore the charge is in any case bad for vagueness. I find that in the charge the sections of the model Standing Orders are mentioned. Therefore the omission to mention the word 'model Standing Orders' is not fatal.

10 The second ground on which the domestic enquiry has been challenged is that the workmen were not furnished with the copy of the complaint either to the management or to the policemen or even the name of the witness who had made complaint was not made known Therefore the prejudice has been caused to the workmen and the enquiry is vitiated I have gone through the record and I find that the Agent, Dhanpuri Open Cast Mine who issued the charge-sheet has clearly mentioned that it has been reported to the undersigned. He has nowhere said that he was given a complaint in writing by any particular person. So the question of furnishing a copy of the non-existing document does not arise. In any case, management has not relied on any such written complaint in support of his case. Therefore also it was not required to furnish a copy of name of the complainant It is true that in serious cases of law and order situation it is the State through the police who takes action but not in all cases In the instant case, department dealt it departmentally and not through the police. Therefore the question of furnishing a non-existing police report does not arise.

11. Lastly it has been contended that the workmen were not informed whether they are satisfied with the appointment of the Enquiry Officer because the Enquiry Officer was a Deputy Personnel Manager and a good friend of Shri Birbal Kapoor, Sub-Area Manager. Besides their official capacity there is nothing on record to prove that they were very good friends. Any way, learned Counsel for the workmen was not able to point out to me that they raised any such objection during the course of enquiry. There is no such provision that the management should satisfy the workmen about the appointment of the Enquiry Officer without even any objection in that regard.

12 No other points though pleaded has been pressed before me perhaps because there is no substantial basis for the same on record The appreciation of evidence also cannot said to be perverse.

13 From the above discussions, I find there is neither any illegibility nor impropriety in conducting the domestic enquiry or in the finding given by the Enquiry Officer. As for punishment, I find that the conduct alleged and proved against the subordinate staff about the treatment meted out to the superior officer in public the punishment awarded does not appear to be harsh or in any way excessive. Since the findings and the punishment is proper it is not necessary to give the management an opportunity to prove misconduct

before this Tribunal. I decide the preliminary issues No. 1, 2 and 3 accordingly and answer the reference as under :—

That the dismissal of S/Shri Satrughan Pandey, Kanta Singh, S. K. Kayoom and Ambika Prasad Chowbey, Elect. Helper, Mining Sirdar, Fitter and Dumper Operator respectively of Dhanpuri Open Cast Mine from services with effect from 24-9-84 by the General Manager, Sohagpur Area of Western Coalfields Limited P.O. Dhanpuri, Distt. Shahdol is justified. Workmen concerned are not entitled to any relief. No order as to costs.

V. S. YADAV, Presiding Officer

[No. L-22012/16/85-D.V]

V. K. SHARMA, Desk Officer

Dated : 3-7-1987

नई दिल्ली, 28 जुलाई 1987

का० आ० 2099.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली में पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th July, 1987

S.O. 2099.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Lakshmi Commercial Bank now amalgamated with Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th July, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT

Industrial Tribunal, New Delhi

I. D. No. 61/80

In the matter of dispute between :

Ashok Kumar Gupta s/o Shri Ram Gupta,

r/o 4/48, Rodu Mohalla, Taran Taran,

District Amritsar.

Versus

The Chief Personnel Manager,

Lakshmi Commercial Bank,

H-Block, Connaught Circus,

New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Tara Chand Gupta—for the workman.

Shri N. C. Sikri for the Management

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-12012/101/79-D. II. A, dated 1st July, 1980 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Mmanagement of Lakshmi Commercial Bank Ltd., H, Block, Connaught Circus, New Delhi (subsequently amalgamated with the Canara Bank) in terminating the services of Shri Ashok Kumar Gupta, Clerk-cum-Cashier-cum-Godown Keeper At Bundala Branch of the Bank with effect from 20-5-1978 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?

2. Some of the undisputed facts are that the workman Shri Ashok Kumar Gupta made an application dated 29-12-77 to the Management of the bank formerly known as Lakshmi Commercial Bank Ltd. and later on amalgamated with the Canara Bank vide notification dated 23-8-1985 (hereinafter referred to as the bank) for appointment as clerk/Cashier, whereupon he was appointed Clerk-cum-Cashier-cum-Godown Keeper on six months probation w.e.f. the date of joining; that pending the issue of formal letter of appointment the workman joined the branch of the bank at village Bunala Tehsil and District Amritsar on 10-1-1978; that a formal order of appointment was issued on 13-3-78 informing the workman that on the basis of his application dated 29-12-1977 he had been selected and taken into service of the bank as Clerk-cum-Cashier-cum-Godown Keeper w.e.f. the date of joining on the basis of six months probation during which period his services could be terminated at any time by giving him proper notice; that the services of the workman were terminated w.e.f. 20-5-1978. A.N.

3. The case of the workman is that his services were terminated on the basis of a telegram the text of which read "work and conduct of Shri A. K. Gupta Clerk-cum-Cashier on probation not found satisfactory relieve him by paying full dues for full settlement of his claim forthwith." The workman has contended that the action of the Management to terminate his services during the probation on the alleged misconduct was illegal unjustified and amounted to unfair labour practice. It is further stated that assuming but not admitting that his work was not found satisfactory the Management was within its rights to extend his probation period per para 495 of the Shastri Award. The workman has also alleged violation of sections 25-F, G and H of the I. D. Act. The workman further stated that in the written comments submitted by the Management before the Assistant Labour Commissioner, his services had been terminated on account of the following allegations based on surmises. and assumptions :

That he had misrepresented the fact that he was local candidate from Bundala and that he was coming late to office and was leaving bank before normal working hours of the bank and the bank branch Manager accordingly made several complaints to the Head Office about his work and for not performing the duties satisfactorily.

In the event his services were terminated on the alleged misconduct he should have been provided proper opportunity to explain his conduct and there should have been proper enquiry.

2. The case of the Management is that the liability of the Canara Bank is limited to the provisions of the scheme of amalgamation clause 10 of part III whereof provides that employees of the erstwhile Lakshmi Commercial Bank who were in the employment of the bank on the date of take over should be deemed to be in the employment of the transferee bank, if they exercise their option to the effect that the very fact that Mr. Ashok Kumar Gupta was not in the employment of the Lakshmi Commercial Bank and his contract of employment stood terminated as far back as 20-5-1978, the Canara Bank cannot be held liable in terms of the aforesaid scheme of amalgamation which has statutory force and over rides the general law including the I. D. Act. On merits the termination of the services of the workman during the period of probation was justified on the ground that the work and conduct of the workman had not been found satisfactory; that the termination of the services during the period of probation does not amount to disciplinary proceedings and it is a case of discharge simplicitor ; that the workman had made mis-representation in the application dated 29-12-1977 that he belonged to a very respectable family of Bundala whereas subsequently it was found that the workman was not a resident of Bundala and in fact belonged to Taran Taran. That he was quite unpunctual in reaching the bank from Taran Taran with the result that the work of the bank suffered and there were complaints from the customers and inspite of warning the workman did not show any improvement. It was further stated that the workman was appointed mainly for the reason that he was local resident of Bundala and will help in mobilising deposits and his claim that he belonged to Bundala was according to his own admission found to be incorrect and this resulted in loss of confidence.

5. I have given my anxious consideration to the entire facts and circumstances of this case and to the arguments advanced and authorities relied upon by the ld. representatives of both the parties and I am of the opinion that th

action of the Management in terminating the services of the workman is quite justified. It is not disputed that the workman was appointed on probation of six months w.e.f. 10-1-1978 when he joined the services of the bank and his services were terminated during the probation period w.e.f. 20-5-78. It is apparent that he had not completed continuous service of one year as defined in section 25-B and, therefore, the workman did not acquire the statutory protection of section 25-F of the Act. The question of violation of section 25-G and H in the case of this workman does not arise because the termination was within the probationary period and in this respect he is governed by the bank Award and the Binartite Settlements. The order dated 20-5-1978 of termination passed by the bank reads as under :

"Lakshmi Commercial Bank Limited, Bandala."

Ref. No. Dated 20-5-78

To

Shri Ashok Kumar Gupta
Clerk|Cashier
B|O Bundala.

Dear Sir,

As per telegraphic instructions received from H|O New Delhi you are hereby relieved from the services of the Bank w.e.f. 20-5-78 A.N. as per Order No. 16|78 of date is also handed over to you amounting to Rs. 389.88 (Rupees Three hundred eighty nine and paise 88 only) being the full and final settlement of your dues.

Yours faithfully,
Sd|-
Manager

The telegraphic instructions mentioned in the above order are also reproduced below :

"The Lakshmi Commercial Bank Limited,
(Regd. Office : 'H' Block Connaught Circus,
New Delhi).

Ref. No. Estt. 3424|78 Dated 16th May, 1978.

TELEGRAM

MANAGER
LAKSHMI COMMERCIAL BANK
BUNDALA
DISTRICT AMRITSAR

WORK AND CONDUCT OF ASHOK GUPTA CLERK CUM CASHIER ON PROBATION NOT FOUND SATISFACTORY (STOP) RELIEVE HIM BY PAYING FULL DUES IN FULL SATISFACTION OF HIS CLAIM FORTHWITH

LAKSHMI COMMERCIAL BANK."

It is apparent that the above order of termination amounts to discharge simplicitor and does not pass any stigma on the workman and hence no charge sheet or enquiry was necessary. Although it was not necessary for the Management to explain the reasons for discharge during pobation period yet it has been clearly demonstrated that he workman had made a mis-representation regarding his place of domicile. In his application dated 29-2-77 he had stated that he belonged to very respectable family of Bundala District Amritsar The Management has placed on record a letter dated 31-12-77 addressed by the Assistant General Manager to the Personnel Manager of the Bank contents of which are reproduced below :

"The Personnel Manager,
Head Office, Connaught Circus,
New Delhi-110001.

Dear Sir,

Ref : Mr Ashok Kumar Gupta-Local appointee for Bundala Branch.

We enclose an application of the above named duly recommended by the Branch Manager for appointment as Clerk-cum-Cashier in place of Mr. Ajit Singh, who has been promoted.

Since Mr. Ajit Singh was a local appointee, we thought fit to select the above named as he is also a local man.

This refers to the discussion the undersigned had with you, kindly get the appointment approved from the Chairman for issuing the regular appointment letter. In the meantime, we have advised the Branch Manager to allow the above named to join duties.

Thanking you.

Yous faithfully,
Sd|-
ASSTT. GENERAL MANAGER."

It is apparent from the above letter that the fact that the workman was local man was the major consideration for his appointment. However, the workman himself in the identity from dated 18-3-78 submitted by him gave his home address as house No. 4|48, Rodu Mohalla Taran Taran and he gave his present residential address as C|o Dr. Amar Singh Vaid V. P. & O. Bundla. This was a clear admission that the workman did not belong to Bundala and consequently the statement made to this effect in his application dated 29-12-77 was a mis-representation. This was a reasonable ground for loss of confidence and no further enquiry was called for on the part of the bank. It is an accepted fact that during the probation period an employee is on test and he has to satisfy his employer regarding his work and conduct during this period and the Management is not required to give reasons for the termination of service during the probation period. Para 522 of the Shastri Award clearly provides that the services of the probationer may be terminated by one month's notice or on payment of a month, pay and allowances in lieu of notice. No doubt para 495 of the Shastry Award provides for the extension of the probation period by further 3 months after the initial period of six months but it is not mandatory for the Management to extend the probationery period for the further period of 3 months after the initial peiod of six months. It is admitted by the Management that they did not serve the requisite one month notice on the workman nor did they make any payment of one months pay and allowances in lieu of notice. In fact the Management has offerred to make payment of the one month's pay and allowances in lieu of period of notice. The lapse of the Management in this regard is contractual in nature not mandatory and the only relief the workman is entitled to is pay and allowance for one month in lieu of non-service of the notice. The amount of pay and allowance for one month has not been indicated either by the Management or by the workman However, taking into consideration the long time which has elapsed and the cost of the proceedings the workman had to bear the Management is directed to pay to the workman a lump sum compensation of Rs. 2000|- for its lapse in not serving notice or paying one months pay and allowance in lieu of the notice. This reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

G. S. KALRA, Presiding Officer

23rd June, 1987

[No. L-12012|101|79-D.II(A)]

का० आ० 2100 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यूनियन बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 13-7-87 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2100.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th July, 1987.

BEFORE SHRI C. G ROTHOD, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Reference (ITC) 11 of 1986

ADJUDICATION

BETWEEN

Management of Union Bank of India, Dudheshwar Branch, Ahmedabad.

AND

The workmen employed under it.

In the matter of terminating the services of Smt. R. R. Solanki with effect from 1-12-84 is justified? If not, to what relief is Smt. Solanki entitled to?

STATE : Gujarat INDUSTRY : Banking Ahmedabad.

AWARD

The Desk Officer, Ministry of Labour, Government of India in exercise of the powers conferred u/s. 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the dispute which exists between the management of the Union Bank of India, Dudheshwar Branch, Ahmedabad and their workmen namely Smt. R. R. Solanki in regard to the termination of her services with effect from 1-12-84. The said dispute was first referred to the Industrial Tribunal No. 2, Bombay but by subsequent order dated 4-11-86, Government of India has transferred the same to the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad with the direction that the said Court shall proceed with the proceedings from the stage at which It is transferred and dispose of the same according to law. The statement of claim in this case was filed before the Industrial Tribunal, No. 2, Bombay vide Ex. 2 and by Ex. 6 the same was permitted to be treated as statement of claim filed in the present reference.

2. In the statement of claim at Ex. 2, it is contended by the concerned workman that she was working as a Lavatory Cleaner in the Union Bank of India at Dudheswar Branch and that she was working as a Parttime but the work was of permanent nature; that she was working with the Bank for he last ten years and that she was being paid Rs. 15 per month; that the payment was made by obtaining signature on the voucher; that during this period, the wages of the other employees were revised in the upward division whereas the second party was not given any increment or the rise in the wages. As the prices were rising, the workman submitted an application on 26-11-84 to the Manager to revise the wages. It is further her case that the second party also reliably learnt that the first party—Bank was contemplating to recruit the Safai Kamdar with higher wages. Therefore, she also submitted an application for the revision of the wages in upward directions and that she further requested that she be employed as Safai Kamdar. It is further her case that on 1-12-1984 when she reported for work, the first party i.e. the Bank informed her that her services were no longer required by the Bank; that the Bank abruptly terminated her services without assigning any reasons. It is further contended that Dudheswar Branch of the Union Bank of India is still functioning and the Branch has not been closed down so far. It is also submitted that the workman was doing the work of cleaning the lavatories; that the work of cleaning lavatories can not be said to be of a temporary nature; that it was of a permanent nature and, therefore, it can be said that she was working on temporary basis. It is also contended that the concerned workman has put in service of 10 years and during the tenure of the service she was not served with any notice; that her performance was worthy of emulation. It is also contended that merely because the concerned workman gave an application for revising the wages, she became the eyesore of the Management that the only disqualification on the misconduct of the concerned workman was that she has raised a demand for higher wages. It is further contended that the action of the Bank in terminating the services of the second party is arbitrary and deserves to be struck down; that the Bank has not issued any show cause notice, no written order has been served upon the second party for terminating her services and the Bank has not advanced any reasons for terminating her services and this action of the Bank in terminating her services is in gross violation of the principles of natural justice. It is also contended that the Bank has not paid the notice pay, unpaid wages and the retrenchment compensation and, therefore, that action of the Bank is in violation of the provisions contained in the Industrial Disputes Act, 1947. It is contended that the workman gave an application to the first party Bank for revising the wages in 1984 and that application for revision of the wages has incurred displeasure to the first party. In the circumstances, it is contended that the Bank should be directed to re-instate the workman concerned as Lavatory Cleaner or as Safai Kamdar w.e.f. 1-12-1984 and should also be paid full back wages till the date of re-instatement.

3. The Union Bank of India has filed its written statement Ex. 4 and it is contended, inter alia, that the reference is not tenable in law and it has no basis in law; in fact the reference is legally incompetent, that there was no relationship of employer-employee between the parties and, therefore, the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 are not attracted; that the second party is not a workman and, therefore, she has no locus standi to raise the present issue; that it is denied that since the workman concerned gave an application for revision of wages she has incurred the displeasure of the Bank. It is contended that the said allegation is totally false and misleading. It is denied that the concerned workman was working as a Part-timer and that the payment of Rs. 15 per month to her was a starvation wage. It is contended that there is no contract of service at any point of time. The Bank happened to enter into an arrangement with the workman in the year 1972 under which in consideration of the payment of Rs. 10 p.m. which was subsequently raised to Rs. 15 p.m. the concerned workman performed the job of cleaning urinals and lavatory at Dudheshwar Road Branch of the Bank. It is contended that the work of cleaning urinals and latrine is not incidentally connected with the main work of Bank activity and that looking to the nature of job performed by second party, it was only an arrangement to perform the job work of cleaning urinals and latrines; that she could do that job at any time convenient to her; there was no obligation on her to wok for a fixed period; that there was no actual supervision of the work; that there was no control of the Bank on the manner of the job being performed by the second party and it was not obligatory on the parts of the second party to do the job personally; that the Bank authority had no right to take disciplinary action against the concerned workman; that the work hardly took fifteen minutes per day. The arrangement entered into between the bank and the workman was that of a contractor to do a particular job and that of master and servant relationship. It is contended that per Justice K. T. Desai's award the persons who were employed by the Bank to do job work are excluded from the operations of the Award. In view of what has been stated above, the second party is not entitled to any of the relief whatsoever as prayed for and she is not entitled to reinstatement with back wages.

4. Mr. Yogesh Vyas appeared for the Bank and Mr. D. S. Vasavda for the concerned workman and after the evidence was recorded in the case, I have heard their arguments fully.

5. The poin's which require to be considered are—

1. Whether the action of the management of Union Bank of India, Dudeshwar Branch, Ahmedabad in terminating the services of Smt. R. R. Solanki w.e.f. 1-12-84 is justified?

2. If not,, to what relief she is entitled to?

6. My answer to the aforesaid points are as under:—

1 No.

2 As per order below.

REASONS

7. In the present reference the concerned workman has been examined at Ex. 7 and on behalf of the Bank, Mr. Natwarlal Chimanlal Patel, Planning and Development Officer, who was Manager in the Dudheshwar Branch of the Union Bank of India in the year 1972-73 is examined at Ex. 15 and Shri Ganpatbhai Ramjibhai Chauhan who was working as Part-time Sweeper of the Union Bank is examined at Ex. 18. In the evidence of Smt. R. R. Solanki, vide Ex. 7, she has stated that she was working as Sweeper in the Dudheshwar Branch of Union Bank of India. Admittedly even according to the written statement filed and as per the evidence of Shri N. C. Patel, Ex. 15, it appears that she was appointed as Sweeper in the year 1972-73; that her work was that of cleaning lavatories. Admittedly the concerned workman was required to clean four urinals and one lavatory at the Dudheshwar Branch of the Bank. This is the say of the concerned workman, Smt. R. R. Solanki vide Ex. 7. She has also stated that she was employed by the Branch Manager and she was instructed to come between 9.30—10.00 A.M. for an hour and complete the work. Admittedly she was not given any written order as regards her appointment, but she was orally instructed what work should be done by her. According to her she was instructed to do this work personally and not with the help of anyone else. Smt R. R. Solanki, Ex. 7, further states in her evidence—that for cleaning lavatories she was being supplied piece cloth, acid etc. She has further stated in her evidence that for doing this work of cleaning, she required to work for one hour. She denied the allegation in the cross examination that she required only Rs. 15 for doing this work. She has also stated that she has to do this work personally and she could not get this work done by anyone else. She had also denied the allegation that it is not true to say that the Manager was not supervising her work. She has also denied the allegation that the Manager had no right to reprimand her for unsatisfactory work.

8. If we were refer to the evidence of Mr. Natwarlal C. Patel, he has stated that this is a job work and does not require more than 10 minutes. He has also stated that they were not supervising this work. He has stated that the workman concerned used to work before 11.00 AM and used to clean lavatories and the urinals; that there were two lavatories and three urinals. He has stated that for cleaning the labatories and urinals, pheneoils and Acid was required to be used. He has stated that he has not seen Ranjanabbhen Ramanlal, but he has admitted that the work of cleaning lavatories and urinals was of permanent nature. At present the person who is employed at Dudheshwar Branch for cleaning the office is also cleaning Lavatories and Toilet.

9. The next witness, Shri Ganpatbhai R. Chauhan, vide Ex. 18, has stated in his evidence that he was doing the work of cleaning labatories and toilet at Dudheshwar Branch. He has stated that this work would not take more than 10 minutes, but in the cross examination, he had to admit that for cleaning the labatories water is required to be used. It is required to be cleaned by brew; that for cleaning one lavatory, it requires 5 minutes and for cleaning the toilet, it requires only one minute. I am not prepared to accept that the toilet can be cleaned within a minute. Even though, the allegation to the workmen concerned by the management was that it would take not more than half an hour for that work, the concerned workman has stated that it will take having regard to the nature of the work such as the use of phenoil, acid, water, etc. that the concerned workman used to work at the Bank for little more than half an hour but less than 45 minutes.

10. Now admittedly her services were terminated on 1-12-84, but her services were terminated orally. It is her say that she gave an application for raising her wages by application Ex. 9. In the said application she has also stated that it takes about one hour for doing the said work and that her wages be increased but instead of increasing the wages it appears that her services were terminated orally after she gave an application at Ex. 8. The Management, of course, denied this fact, but they have not come out with any specific ground as to why her services were terminated all of a sudden. Now it appears from what has been stated as above that the work of cleaning the lavatories, urinals or toilet was done by the concerned workman. She was doing this work since about ten years. Initially, she was paid Rs. 10 per month and, thereafter, the wages were increased to Rs. 15 per month. Now, it is contended by the Management that her work had not been supervised, but since she was engaged for cleaning urinals and lavatories and when material for cleaning were being supplied by the Bank, it is clear that her work was being supervised by the bank authorities. It would not be correct or proper to brush aside the case of the concerned workman on the ground that her work was not being supervised on the ground that she was required to do the work before 11.00 A.M., and therefore, her work could not have been supervised by anyone. As stated, earlier, she was being supplied material such as acid, a piece of cloth etc. and she was required to clean the lavatories and urinals with the help of the said material and water and it being so, it cannot be said that her work was not supervised by the Management. The Management had really a control and supervision of the work done by her.

11. Various decisions are cited by Mr. Yogesh Vyas for the Bank and if we were to refer the same, we find that none of authorities really help the Bank or the Management. In the decision namely Achuta Achar Annappa Achar v. Management of M/s. Sharada Jewellery, Mangalore, 1968 Lab. IC 716, it appears that the firm used to entrust the gold to the goldsmiths for making jewels. The wages were mutually agreed upon depending upon the work to be done. The goldsmiths used to work in the premises of the management to suit the convenience of the customers, although, sometimes, the goldsmiths used to take the gold to their own houses and that there were no fixed hours of work and that the goldsmiths were free to work at any time without being subject to the control or supervision by the management. In view of this evidence, the Labour Court held that he was not under the order or control of the proprietor of the concern. This decision does not in any way help the management in as much as the principles on this point are well settled. In this case, two Supreme Court decisions were referred to.

One of the decision referred to is D. C. Dewan Mohideen Sahib and Sons v. Secretary, United Beedi Workers' Union, Salem, AIR 1966, SC, page 370. In the said decision their Lordships of the Supreme Court observed the correct approach therefore, was to consider whether, having regard to the nature of the work, there was due control and supervision by the employer. It was further held that the question whether the relation between the parties was one as between an employer and employee or matter and servant was a pure question of fact, depending upon the circumstances of each case.

Similarly another decision namely Dharangadhara Chemicals Works Ltd. v. State of Saurashtra, AIR 1957, S.C. page 264 is referred to. In the aforesaid decision. In Dharangadhara Chemicals Works Ltd., it is observed in para 14 as under :—

"The principle which emerges from these authorities is that the prima facie test for the determination of the

relationship between master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant not only in the matter of directing what work the servant is to do but also the manner in which he shall do his work, or to borrow the words of Lord Uthwatt at page 23 in Mersey Docks and Harbour Board v. Coggins & Griffith (Liverpoor) Ltd., 1947-1 AC 1, at p. 23(E), The proper test is whether or not the hirer had authority to control the manner of execution of the action in question."

"The nature or Extent of control which is requisite to establish the relationship of employer and employee must necessarily vary from business to business and is by its very nature incapable of precise definition."

In view of the two Supreme Court's decisions as above, it is clear that the relationship between master and servant is the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant and further in what manner it shall be done. In the instant case, though the case is of a simple nature, the evidence on record clearly leads me to held that the management has the right to supervise and control the work. The witness for the Bank, Shri Ganaptbhai R. Chauhan has admitted that if he did not carry out his work at Dudheshwar Branch properly, he would be reprimanded. Thus, it is clear that the work that was being done by the present workman was such that as and when necessary, the management had a right to give instructions. The management could tell the concerned workman to clean the lavatories more properly and thoroughly and that it could be said that there was a control in respect of the work done by the concerned workman. There is no dispute of the fact that the Branch Manager had employed the concerned workman that she was employed to do this work and as stated above, the management had the power to supervise and control her work.

12. The next decision cited is Management of Radia Foundation Engineering Ltd. v. State of Bihar, 1970 Lab. IC, page 1119. In the said decision also it is stated that the question whether the relationship between the parties is one as between master and servant is a pure question of fact, the important test for determination being the existence of the right in the master to supervise and control the work done by the servant. In the said decision, it is also stated that mere fact that the workmen are paid on daily rates or temporary basis, will not make any independent contractors.

13. The next decision cited by the learned Advocate, Shri Yogeshbhai Vyas, for the management is namely M/s. Pivate Lal Adishwar Lal v. Commissioner of Income-tax, Delhi AIR 1960, SC 997. In the said decision, though, the question involved was under the Income-tax Act the same principle as referred to me in Dharangadhara Chemicals Works Ltd. v. State of Saurashtra, AIR 1957, SC, page 264 are referred and they need not be repeated here. Similarly, a decision was cited on behalf of the mangement namely Shankar Balaji v. State of Maharashtra, AIR 1962, SC, p. 517, namely was a case of Bidi roller and the question was conviction u/s. 92 of the Factories Act. In that case there was no agreement or contract between the appellant and Pandurang As stated in the decision it appears that Mr Pandurang whenever he went to work, the appellant used to supply Tobacco and for rolling Bidi Pandurang was paid at a certain extent on the quantity of bidis turned out. The management in that case exercise no control or supervision on Pandurang but such is not the case here. Here the workers has to attend the work regularly and she was not free to report to work whenever she liked.

14. Mr. D. S. Vasavda for the workman has referred to a decision namely Shining Tailors v. Industrial Tribunal II U.P., 1983, II LLJ, page 413. In that case since the payment was made on piece-rate basis, the Tribunal held that there is no relationship between master and servant and the workmen were independent contractors. The Supreme Court has observed that the test employed in the past was one of determining the degree of control that the employer wielded over the workmen. However, in the identical situation in Silver Jubilee Tailoring House v. Chief Inspector of Shops and Establishments, (1973-II LLJ 495, Mathew), speaking for the Court observed that the control idea was more suited to the agricultural society prior to Industrial Revolution and during the last two decades the emphasis in the field has shifted from, and no longer rests exclusively or strongly upon, the question of control. It was further observed that a search for a formula in the nature of a single test will not serve any useful purpose, and all factors that have been referred to in the cases on topics, should be considered to tell a contract of service. Approaching the matter from this angle, the Court observed that the employer's right to reject the end product if it does not conform to the instructions of the employer speaks for the element of control and supervision. So also, the right of removal of the workman or not to give the work has the element of control and supervision. If these aspects are considered decisive, they are amply satisfied to the facts of this case. So in the instant case also it is clear that the concerned workman was doing the work under the control and supervision of the Branch Manager. The control or supervision need not mean that the authorities ought to remain present there. It is possible that he may remain present, but in any case that is not in any way material. The question is whether he had a right to take the work and give suitable instructions to the concerned workman. As stated earlier, they were supplying the necessary material for cleaning the lavatories and urinals and, therefore, it is clear that they had a control over the work done by her. It, therefore, follows that the concerned workman was not merely a job worker. No such point, it appears, was canvassed during the course of the arguments, and therefore it is clear that the concerned workman was doing the work as an employee of the Bank.

15. It is then urged that the work she was required to do was of a short period of about half an hour and, therefore, she could not be said to be a worker. If we have to refer to the definition of the word "workman" as defined u/s. 2(s) of the I.D. Act, it is clear that workman means any person (including an apprentice) employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, Moreover in the decision namely Mukunda v. Managing Director, KSRTC, 1986,II LLJ, p. 470, it is held that 'Badlis are workmen who fall within the definition of workmen in S. 2(s) of the Industrial Disputes Act 1947 and they are entitled to the benefits in Chapter V-A of the said Act. Even a casual worker is held to be a workman (See the case of Tapan Kumar Jana v. Calcutta Telephones, 1981, II LLJ, p. 382). Therefore, there is no doubt that the concerned employee is a workman as defined under the Industrial Disputes Act.

16. Now as decided in the case of Santosh Gupta v. State Bank of India, 1980, II LLJ, p. 72 by the Supreme Court, we find that in the instant case there was a termination of services and this is not denied and, therefore, as held by the Supreme Court when such a termination is without following the procedure u/s. 25F, it would be bad. In the said decision, it is observed that in our view if due weight is given to the words "the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever" and if the words "for any reason whatsoever" are understood to mean what they plainly say, it is difficult to escape the conclusion that the expression "retrenchment" must include every termination of the service of a workman by an act of the employer. The underlying assumption, of course, is that the undertaking is runnig as an undertaking and the employer continues as an employer but where either on account of transfer of the undertaking or on account of the closure of the undertaking the basic assumption disappears, there can be no question of "retrenchment" within the meaning of the definition contained in S. 2(oo).

17. The other decision namely Malkhan Singh v. Union of India, 1981, II LLJ, p. 174 in which the Delhi High Court held that "Retrenchment" as defined in S. 2(oo) would include termination of services of a temporary railway servant. Similarly, in the decision namely Ramachandra Vithuji Kothare v. Industrial Court, Nagpur, 1986, I LLJ,

p. 363, it is held that termination of service for any reason whatsoever, except by way of punishment in retrenchment within the meaning of the said word in the I.D. Act. It is also stated that any reason referred to in the definition would include the reason of loss of confidence. It is further stated that the provisions of S. 25F are the provisions of statute which superimpose or super-add certain obligations upon the employer in respect of his conduct of employment, statutory or otherwise with the workmen to whom I. D. Act applied. The effect of provisions of S. 25F would be that irrespective of the contract of employment, the mandatory provisions of S. 25F will have to be complied with.

18. In view of what has been stated as above, it is clear that in the instant case, the termination of services of the concerned employee by the Management without giving one month's notice and or pay in lieu of such notice is in clear contravention u/s. 25F of the I.D. Act. Again she has not been paid retrenchment compensation and it is also in clear violation of 25F of the Act. It, therefore, appears to me that the Management was not right in terminating the services of the concerned workman. The work which she was carrying on was of a permanent nature and though it is possible that the work she was carrying on required about 30 to 40 minutes is not itself a sufficient criteria to reject the contention of the workman that she was an employee of the Bank. The work of the concerned workman was being supervised by the Bank authorities. They had a right to instruct her but not terminate. Naturally she is a workman of the Bank after her services were terminated orally and another workman namely Shri Ganpatbhai R. Chauhan, Ex. 18, was appointed in her place and he was being paid Rs. 340 for two hours work. He was also required to do the said work and besides that, according to him, he was also required to do the work of cleaning of office and it would not take more time. Therefore, it is clear that the services of Smt. R. R. Solanki were wrongly terminated without following the procedure as laid down u/s. 25F of the I.D. Act. The termination is, therefore, ab initio void. She has to be re-instated and paid wages. Her wages shall be fixed on the oasis of duty hours. Before parting with the case I may state that eventhough a contention was raised in the written statement filed by the Bank that in view of the award passed by Justice, Shri K. T. Desai in reference No. 1 of 1980, the persons employed by the Bank to do the job work are excluded from the operation of the award. The award was not produced nor any specific provisions therein were brought to my notice and, therefore, it appears that there is no substance in the contention. Moreover, as stated above, I have already held that this is not a case of job work. Lastly, I may state that eventhough this reference was received by the Tribunal in December, 1986, in view of the strike of the Advocates, no substantial progress could be made till 5th of March, 1987. It is in these circumstances that there has been a delay in the disposal of the present reference. I, threfore, pass the following order.

ORDER

19. The concerned workman, Smt. R. R. Solanki be re-instated in Union Bank of India of Dudheshwar Branch effective from 1-12-1984 and she be paid back wages on the basis that she had to carry out this work for 40/45 minutes.

20. The Management shall reinstate her within one month of the publication of this award and make the payment of arrears within two months of the publication of this award.

21 No order as to costs.

Sd/-

(Illegible),

Secretary.

Ahmedabad, 22nd June, 1987

C. G. RATHOD, Presiding Officer

[No. L-12012/255/85-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987